

भारतीय आयकर के सरल सिद्धान्त

ELEMENTS OF INDIAN INCOME-TAX

[बी कॉम तथा एलएल बी के विद्यार्थियों के लिए]

वित्त अधिनियम, १९५९ के प्रबन्धोंको समावेश करते हुए

लेखक

आर एन. लखोटिया

एम कॉम, एलएल बी

[भूत पूर्व प्रवक्ता (वाणिज्य विभाग) दयानन्द कॉलेज तथा
गवर्नमेन्ट कॉलेज, अजमेर]

रचयिता एलीमेन्ट्स ऑव इंडियन इनकम-टैक्स, ह्यूमर
एवरी व्हेअर इत्यादि ।

प्राक्कथन लेखक

श्री के. पी भटनागर

एम ए, एलएल बी

वाइस-चान्सलर, आगरा विश्वविद्यालय ।



आशा पब्लिशिंग हाउस

अहमदाबाद-१४

प्रकाशक

आशारानी,

प्रो आशा पब्लिशिंग हाउस,

अहमदाबाद-१४

लेखक द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित

164406

प्रथम संस्करण — १००० प्रतियाँ

१९५९

मुद्रक *

जीवणजी डाह्याभाई देसाई,

नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-१४

प्राक्कथन FOREWORD

I have very great pleasure in recommending to the students and teachers of commerce in our Universities the book entitled “Bhartiya Aaykar ke Saral Siddhanta ” The book has been written in a very lucid manner and will prove very advantageous to those who will study it I congratulate the author on writing such a useful book of which there was a great need.

Agra University, }
1st March 1959 }

K P BHATNAGAR
Vice-Chancellor

दो शब्द

गत कुछ वर्षों में आयकर कानून बहुत कठिन हो गया है। नये नये सशोधनो से यह कानून पेचीदेपन तथा आकार में और भी अधिक बढ गया है। यह सच है कि भारतीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी-गण तथा आयकर-दाता इसे समझने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में मैंने इस बात का पूरा प्रयत्न किया है कि कानून की इस कठिन शाखा का सरल भाषा में, साधित प्रश्नों की सहायता से, विश्लेषण किया जाय। वित्त अधिनियम १९५९ के सभी मुख्य प्रबन्धों का समावेश भी इस पुस्तक में कर लिया गया है। इसके अलावा आगरा तथा राजपूताना विश्वविद्यालयों के पाँच वर्ष के पच्ची के प्रश्न तथा उत्तर तथा अनुक्रमणिका इस पुस्तक के अन्त में दिए गए हैं जिनसे इस पुस्तक की उपयोगिता और भी अधिक बढ गई है।

मुख्यतः यह पुस्तक भारतीय विश्वविद्यालयों के बी कॉम तथा एलएलबी छात्रों के लिए पाठ्य-पुस्तक के रूप में लिखी गई है। परन्तु यह पुस्तक साधारण कर-दाता एवं आयकर की अन्य परिक्षाओं के विद्यार्थी-समाज के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है।

मैं मेरे परम गुरु श्री के० पी० भटनागर का बडा आभारी हूँ जिन्होंने कि इस पुस्तक का प्राक्कथन लिख कर मुझे अपना कृपा-पात्र बनाया है। इसके अलावा मैं प्रकाशक तथा मुद्रक को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कि इस पुस्तक को शीघ्रता तथा सफाई के साथ निकालने में मदद की है।

अहमदाबाद,
२५-७-५९

आर. एन. लखोडिया

विषय-सूची

CONTENTS

अध्याय	विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन		111
दो शब्द		v

प्रथम भाग

PART I

प्रारम्भिक (Preliminary)

१	विषय-प्रवेश तथा आयकर अधिनियम की प्रमुख परिभाषाएँ (Introduction and Important definitions of Income-Tax Act)	१
२	कर-दाताओंका निवास-स्थान तथा आयकर दायित्व (Residence of Assesseees and Income-tax Liability)	१३
	(अ) कर दाताओं का निवास-स्थान के अनुसार वर्गीकरण (Classification of Assesseees according to their residence)	
	(ब) आयकर-दायित्व (Income-tax liability)	
३	कर-मुक्त आय (Exempted Income)	१९

द्वितीय भाग

PART II

आयके शीर्षक — धाराएँ ६ से १२ बी तक (Heads of Income) Sections 6 to 12 B

४	वेतन (Salaries) — धारा ७	२७
५.	प्रति भूतियोंका ब्याज (Interest on Securities) — धारा ८	३४
६	जायदाद की आय (Income from Property) — धारा ९	३७
७	व्यापार, पेशा अथवा व्यवसाय का लाभ (Profits and gains from business, profession or vocation) — धारा १०	४२
८	अन्य साधनों से आय (Income from other Sources) — धारा १२	५३
९	पूँजी लाभ अथवा पूँजी गत लाभ (Capital Gains) — धारा १२ बी	५७

तृतीय भाग

PART III

कर-निर्धारण एवं कर-सगणना (Assessment and
Computation of Tax)

- १० कुल आय तथा कुल विश्व आय की सगणना (Computation of Total Income and Total World Income) ६१
- ११ विभिन्न कर-दाताओंका कर-निर्धारण (Assessment of different Assesseees) ६५
- (1) व्यक्ति (Individuals)
- (II) अविभक्त हिन्दू परिवार (Hindu Undivided Families)
- (III) साझेदारी फर्म तथा अन्य जन मंडल (Partnership firms and other Association of Persons)
- (IV) कंपनियाँ अथवा समवाय अथवा प्रमंडल (Companies)
- (V) अनिवासी (Non-residents)
- (VI) विरत व्यापार (Discontinued businesses)
- १२ कर की सगणना (Computation of Tax) ८७

चतुर्थ भाग

PART IV

कर-निर्धारण तथा अपील पद्धति (Assessment and
Appellate Procedure)

- १३ कर-निर्धारण पद्धति (Assessment Procedure) ९८
- १४ कर का भुगतान एवं वसूली (Payment and Recovery of Tax) १०३
- १५ अपील, पुनरीक्षण एवं निर्देश (Appeals, Revisions & References) १०७
- १६ कर-वापसी (Refunds) १०९
- परिशिष्ट - अ अनुक्रमणिका (Index) १११
- ब आगरा तथा राजपूताना विश्व-विद्यालयों की बी कॉम परीक्षा के साधित प्रश्न-प्रश्न १-२०

प्रथम भाग

प्रारम्भिक

अध्याय १

विषयप्रवेश तथा आयकर अधिनियम की प्रमुख परिभाषाएँ

१ आयकरका इतिहास

आयकर भारतवर्ष की केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के लिए आमदनी का एक प्रमुख साधन है। योजना के इस आधुनिक युग में इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। भारतीय समाजके विभिन्न वर्गों में स्थित आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए भी यह एक सर्वश्रेष्ठ साधन माना जाने लगा है। ऐसी आशा की जाती है कि भावी भारतके आर्थिक विकास के लिए विशाल आय प्राप्त करनेमें यह और भी सहयोगी सिद्ध होगा। इसलिए कर-दाताओं तथा विद्यार्थी-समाजके लिए ही नहीं वरन् समस्त जनता के लिए यह जानना नितान्त आवश्यक हो जाता है कि आयकर अधिनियम क्या है। प्रस्तुत पुस्तक इस उद्देश्य को लेकर लिखी गई है कि प्रत्येक भारतीय को आयकर के मूल सिद्धान्तोंका सरल भाषामें परिचय कराया जाय।

भारतीय आयकर विधानका इतिहास बड़ा रोचक है। भारत में आयकर का सूत्र पात सर्व प्रथम सन् १८६० में हुआ। उस समय यह एक साधारण कानून था। कुछ अन्य छोटे छोटे कानूनों के पश्चात् सन् १८८६ में एक नया कानून बना जो सन् १९०३ तक चलता रहा। इस वर्ष आयकर लगने वाली न्यूनतम सीमा को ५००० से बढ़ाकर १०००० कर दिया गया। सन् १९१८ में एक नया आयकर अधिनियम बनाया गया जिसके द्वारा न्यूनतम आयकर सीमा बढ़ाकर २०००० ०० कर दी गई। परन्तु सन् १९२२ में पास हुआ आयकर—अधिनियम ही भारतीय आयकरकी आधार-शिला है। परन्तु इसमें भी समय समयपर अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। विशेषकर यह कानून सन् १९३९, १९४४, १९४६, १९५१, १९५३, १९५४, १९५५, १९५६, १९५७, १९५८ तथा १९५९ में आयकर सशोधन अधिनियमों तथा वित्त अधिनियमों द्वारा परिवर्तित किया गया। इस पुस्तक में जहाँ भी किन्हीं धाराओंका वर्णन है वे सब भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ (Indian Income tax Act, 1922) से सम्बन्धित हैं।

भारत में आयकर सम्बन्धी दो मुख्य कानून हैं —

- (१) भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२—यह मुख्य कानून है। तथा
- (२) वित्त अधिनियम, जो कि प्रतिवर्ष भारतीय पार्लियामेन्ट द्वारा पास किया जाता है। यह प्रतिवर्ष आयकर की विभिन्न दरों को निर्धारित करता है।

२ आयकरके अन्तर्गत विभिन्न कर

भारतीय आयकर के अन्तर्गत निम्नलिखित चार प्रकार के कर शामिल हैं —

- (१) आयकर [Income-tax proper]
- (२) अतिरिक्त कर [Super tax]
- (३) निगम कर [Corporation tax] प्रमडलोपर लगाया गया अतिरिक्त कर।
- (४) वृद्धि कर [Surcharges on items (1) and (2)] [(१) तथा (२) पर]

३ कर-दाता कौन है? — (धारा ३)

केवल निम्न लिखित ही कर-दाता हैं —

- (१) व्यक्ति (Individual),
- (२) अविभक्त हिन्दू परिवार (Hindu Undivided Family),
- (३) प्रमडल (Company),
- (४) स्थानीय सत्ता (Local authority),
- (५) साझेदारी फर्म (Partnership firm), तथा
- (६) अन्य जन-मडल (Any other association of persons)

४ आयके शीर्षक — (धारा ६)

केवल निम्न लिखित आयकर शीर्षकोंके अन्तर्गत आने वाली आय पर ही आयकर लगता है —

- (१) वेतन — धारा ७
- (२) प्रति भूतियों से ब्याज — धारा ८
- (३) जायदादकी आय — धारा ९
- (४) व्यापार, पेशा अथवा व्यवसाय का लाभ — धारा १०
- (५) अन्य साधनों से आय — धारा १२
- (६) पूँजीगत लाभ — धारा १२ बी

५ आयकर आयित्व (Income-tax Liability) —

एक व्यक्ति, अन रजिस्टर्ड फर्म, रजिस्टर्ड फर्मके साझीदार या अन्य जन-मंडल के आयकर दायित्व का प्रश्न तब उठता है जबकि उसकी गतवर्ष की आय ३००० रु० से अधिक हो, अन्यथा नहीं। एक अविभक्त हिन्दू परिवार (जिसके दो सदस्य बँटवारे के हकदार हो) का आयकर दायित्व कुछ भी नहीं है यदि गतवर्षमें उसकी कुल आय ६,००० रु० या उससे कम है। एक कंपनी अथवा स्थानीय सस्थाको अपनी कुल आय पर एक ही दर से आयकर देना पड़ता है, चाहे वह कितनी ही कम व अधिक क्यों न हो। एक रजिस्टर्ड फर्म का कर — दायित्व कुछ भी नहीं है यदि उसकी गत-वर्ष की आय १०,००० रु० या उससे कम है। अतिरिक्त कर तथा वृद्धि करोंके बारे में विस्तृत विवरण के लिए देखिए अध्याय १२

६ आयकर-अधिकारी — (धाराएँ ५ तथा ५ ए)

आयकर अधिकारियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है —

- (अ) शासन-सम्बन्धी (Executive) तथा
- (ब) न्याय-सम्बन्धी (Judicial)

इनका विस्तृत विवरण नीचे दिया जाता है —

(१) सेन्ट्रल बोर्ड ऑव रेवेन्यू (Central Board of Revenue) —

• यह सर्वोच्च प्रबन्धक सत्ता है जिसका सेन्ट्रल बोर्ड ऑव रेवेन्यू अधिनियम १९२४ के अन्तर्गत निर्माण हुआ है। इस बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। उसके सदस्यों में से एक सदस्य सम्पूर्ण भारत के आयकर विभाग का नियन्त्रण करता है।

(२) डायरेक्टर ऑव इस्पेक्शन (Director of Inspection)

इनको कानूनी स्थिति १९५३ के सशोधक अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई। इनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती है और ये सेन्ट्रल बोर्ड ऑव रेवेन्यू की देख रेख में विविध प्रकार का काम करते हैं।

(३) कमिशनर ऑव इनकम टैक्स (Commissioner of Income-tax) —

यह किसी राज्य या निश्चित क्षेत्र के आयकर विभाग का अध्यक्ष होता है। इसकी नियुक्ति भारत सरकार करती है। साधारण कमिशनरों के अलावा केन्द्रीय सरकार कुछ ऐसे केन्द्रीय कमिशनर (तीन तक) नियुक्त कर सकती है जिनका कोई क्षेत्र या राज्य निर्धारित नहीं होता।

(४) **इस्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिशनर ऑफ इनकम टैक्स (Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax) —**

यह आयकर कमिशनर अथवा डायरेक्टर ऑफ इस्पेक्शन के नियंत्रण में कार्य करता है। इसका कार्य अपने क्षेत्र के समस्त इनकमटैक्स अफसरों के कार्य का निरीक्षण करना है।

(५) **अपिलेट असिस्टेंट कमिशनर ऑफ इनकम टैक्स (Appellate Assistant Commissioner of Income-tax)—**

यह सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीबे नियंत्रण में रहता है। इसका मुख्य कार्य आयकर अफसरों की आज्ञाओं के विरुद्ध अपील सुनना है।

(६) **इनकम टैक्स अफसर (Income-tax officer)—**

कर दाताओं के साथ सीधा सम्बन्ध होने के हेतु इनकम टैक्स अफसर ही उनके लिए सबसे महत्त्वपूर्ण अफसर है। आयकर लगा कर उसे वसूल करने वाला यही अफसर है। वही सूचनाएँ प्रकाशित करता है, साक्षी लेता है, कर निर्धारण करता है और उसे वसूल करता है। वास्तव में आयकर शासन की आधार-शिला आयकर अफसर ही है।

(७) **इस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स (Inspector of Income-tax)—**

इसकी नियुक्ति कमिशनर करता है और यह ऐसे सब काम करता है जो इसको इनकम टैक्स अफसर या कोई अन्य उच्च अधिकारी करने के लिए कहता है।

(८) **अपिलेट ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal)—**

सूक्ष्म रूपसे देखा जाय तो यह आयकर अधिकारी नहीं है क्योंकि यह सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अधीन नहीं है। यह भारत सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है और इसके सदस्यों की सख्या सरकार की इच्छा पर निर्भर रहती है। इसकी स्थापना २५ जनवरी १९४१ को की गई थी। इसके सदस्य दो प्रकारके होते हैं —

(अ) न्यायिक सदस्य (Judicial Member)

(ब) लेखा पाल सदस्य (Accountant Member)

समापति साधारणतः न्यायिक सदस्य ही होता है। न्यायिक सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जो कमसे कम १० वर्ष तक किसी न्यायिक ओहदे पर रहा हो या किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो। लेखापाल सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जो कम से कम दस वर्ष तक चारटर्ड अकाउन्टेन्ट के रूप में व्यवसाय करता रहा हो। यह न्यायाधिकरण (Tribunal) कुछ बेचो में

विभक्त होता है। प्रत्येक बेच देशके पृथक-पृथक भागो की अपीलें सुनती है। प्रत्येक बेच में दो सदस्य होते हैं — एक न्यायिक तथा दूसरा लेखापाल। दोनों सदस्यों में मतभेद होने की अवस्था में सभापति वोट दे सकता है।

ऐसी दशामें बहुमत का निर्णय मान्य होता है। न्यायाधिकरण का मुख्य कार्य अपिलेंट असिस्टेंट कमिश्नर की आज्ञाओं तथा निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता है। तथ्य (Facts) सम्बन्धी प्रश्नों में इसका निर्णय अन्तिम (Final) होता है। कानूनी प्रश्नों के सम्बन्ध में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक अपील की जा सकती है।

७ कर कैसे दिया जाता है ?

कोई भी कर दाता जिसकी गतवर्ष की आय करमुक्त सीमा से अधिक हो उसे एक आयका विवरण-पत्र जो कि आयकर विभाग से मुफ्त में ही प्राप्त किया जा सकता है, भरकर अपने आयकर अफसर के दफ्तर में भेजना चाहिये। आयकर अफसर उसपर कर-निर्धारित करेगा। आयकर विभाग से माँग की सूचना आने पर वहाँ कर की सारी रकम जमा करानी पड़ेगी। इस विषय में विस्तृत विवरण के लिए देखिए अव्याय १३

८ आयकरकी प्रमुख परिभाषाएँ

गतवर्ष (Previous year) धारा २ (११)

आयकर अधिनियम में कई परिभाषिक पदों एवं शब्दोंका प्रयोग किया गया है। आयकर अधिनियम को पूर्णतया समझने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि इन पदों व शब्दों की ठीक ठीक व्याख्या की जाय। इन पदों में से सबसे महत्वपूर्ण पद है “गतवर्ष”

आयकर अधिनियमके अन्तर्गत कर प्रत्येक आर्थिक वर्ष—जो कि एक वर्ष की पहली अप्रैल से लेकर दूसरे वर्षकी ३१ मार्च तक होता है — में लगाया जाता है। जैसे वर्तमान आर्थिक वर्ष (Financial year) सन् १९५९-६० (१-४-५९ से ३१-३-६०) हुआ। इसे इनकम टैक्स वर्ष, राजकोषीय वर्ष अथवा कर-निर्धारण वर्ष (Assessment year) भी कहते हैं। इस वर्षमें जो भी कर लगाया जाता है वह व्यक्तियों की गतवर्षकी आयपर होता है। इसका तात्पर्य हुआ कि आमदनी पहले वर्ष होती है और उस पर कर अगले वर्ष देना पड़ता है। गतवर्ष के सम्बन्ध में हमें निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है —

- (१) साधारणतः गतवर्ष या पिछले वर्ष की आय पर ही उसके अगले आर्थिक वर्षमें कर देना पड़ता है।

- (२) गत-वर्ष से तात्पर्य है, उन १२ महीनो का जो कि किसी भी वर्ष की ३१ मार्च को समाप्त होते हैं। यह १२ मास की अवधि किसी भी आर्थिक वर्ष के बिलकुल पहले वाला समय है। जैसे १९५९-६० आर्थिक वर्ष के लिए १९५८-५९ गत वर्ष हुआ।
- (३) एक गतवर्ष ऊपर बताए गये १२ महिने वाले समय में किसी भी समय समाप्त हो सकता है। जैसे किसीव्यक्ति का व्यापारिक हिसाबी साल १ जनवरी १९५८ से ३१ दिसम्बर १९५८ है तो यह साल भी १९५९-६० के लिए गतवर्ष हुआ क्योंकि यह समय १०-५८-५९ वर्ष में समाप्त होता है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि गत वर्षकी समाप्ति पूर्व वित्तीय वर्षके अन्दर ही अथवा इसके साथ ही अवश्य हो जानी चाहिए।
- (४) आय के विभिन्न साधनों के लिए भिन्न भिन्न गत वर्ष रखे जा सकते हैं।
- (५) साझेदारी फर्म की आय के लिए गतवर्ष वही होगा जो कि फर्म का गतवर्ष है।
- (६) नया व्यवसाय स्थापित करने वालों के लिए गतवर्ष व्यापार आरम्भ करनेकी तिथि से आनेवाली ३१ मार्च तक या उसके व्यापार की हिसाबी तिथि (Accounting date) तक (यदि उसने १२ महिनो तक के हिसाब बन्द किये हों) माना जा सकता है।
- (७) एक बार अपना गत-वर्ष निश्चय कर लेने के पश्चात् उसे अगले वर्षों के लिए बदला नहीं जा सकता, जब तक कि ऐसा करनेके लिए इनकनटैक्स अफसरकी मजूरी न मिल जावे।
- (८) साधारणतया गत वर्ष १३ मास से अधिक और ११ मास से कम नहीं हो सकता।

उदाहरणार्थ १९५९-६० आर्थिक-वर्ष में कर देने के लिए नीचे दिये हुए वर्षों में से कोई भी गत-वर्ष (अर्थात् वह वर्ष जिसकी आमदनी पर कर दिया जाता है) हो सकता है —

- (अ) १-४-१९५८ से ३१-३-१९५९ या
- (ब) १-१-१९५८ से ३१-१२-१९५८ या
- (स) १-७-१९५७ से ३०-६-१९५८ या
- (द) कोई भी सवत, दिवाली या दशहरा वर्ष जो कि १९५८-५९ वर्षमें समाप्त होता हो, या

(ई) कोई भी वर्ष जो ३० अप्रैल १९५९ के पहले समाप्त होता है। (यह नियम किन्हीं खास दशाओ में ही लागू होता है)

इस नियमके अपवाद (Exceptions to the Rule)

निम्न दशाओ में कर गतवर्ष की आमदनी पर न लगाया जाकर उसी वर्ष की आमदनी पर उसी वर्ष लगाया जाता है —

- (क) जब कि कोई व्यक्ति सर्वदा के लिए भारत छोड़कर जाने वाला हो — धारा २४ ए।
- (ख) जब कि कोई व्यापार, व्यवसाय या धंधा बद कर दिया गया हो धारा २५।
- (ग) कुछ किस्मों के जल यातायात प्रमडलो के बारेमें—धारा ए ४४ ए तथा ४४ बी।

प्रश्न सख्या १

श्री अ ने १-८-१९५८ से एक कपडे का नया व्यापार प्रारम्भ किया। १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष तक उसने अपने बही-खाते बन्द नहीं किए।

- (अ) यदि उसका कर-निर्धारण जून १९५९ में किया जाये और वह यह अनुरोध करे कि अपने व्यापार के बही खाते वह ३१ जुलाई १९५९ को बन्द करेगा, तो क्या आप उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे, और अगर हाँ तो क्यों?
- (ब) यदि उसका कर-निर्धारण सितम्बर १९५९ में किया जाये और वह कहे कि वह अपने बही-खाते ३१ अगस्त ५९ की तारीख तक बन्द करेगा, तो क्या आप उसकी प्रार्थना मान लेंगे, और यदि हाँ तो क्यों?

उत्तर

- (अ) अपने कपडे के नये व्यापार के लिए वह व्यापार के प्रारम्भकी तारीख से लेकर १२ महिने का कोई भी समय अपने गत-वर्ष के लिए रख सकता है, यदि उसने हिसाब-किताब १२ महिने की अवधि तक के किसी भी समय के लिए बन्द कर लिया हो तो।

यहाँ पर कर-दाता अपने नये व्यापार के हिसाब-किताब १२ मासके समयके अन्दर के लिए रखना चाहता है इसलिए उसकी बात माननी होगी। इस हालत में सन् १९५९-६० के लिए कोई गत-वर्ष नहीं होगा और १-८-५८ से ३१-७-५९ तक की आमदनी सन् १९६०-६१ में करदेय होगी।

- (ब) चूक कर-दाता ने अपने नये व्यापार के बही-खाते १२ महिने के समय तक नहीं बन्द किए हैं इसलिए कर-दाता की प्रार्थना नहीं मानी जायगी। कपड़े के नये व्यापार की १-८-५८ से ३१-३-५९ तक की आमदनी कर-निर्धारण वर्ष १९५९-६० में करदेय होगी

९ आयकर लगनेवाले क्षेत्र (Taxable Territories) — धारा २ (१४ ए)

१२ अप्रैल १९५४ के बाद आयकर लगने वाले क्षेत्र के अन्तर्गत सम्पूर्ण भारतवर्ष आता है। बोलचाल की भाषा में इसके लिए “भारत” शब्द आमतौर पर प्रयोग किया जाता है।

१० आय (Income) — धारा २ (६ सी)

आयकर से तात्पर्य है उस कर से जो आय पर लगता हो। आयकर अधिनियम का उद्देश्य आय पर कर लगाना है। किन्तु आश्चर्य की बात यह है कि “आय” शब्द की पूर्ण व्याख्या इस अधिनियम में नहीं की गई है। आय निश्चित साधनों द्वारा निश्चित रूप से समय समय पर द्रव्य में या द्रव्य के मूल्य में प्राप्त की जाती है। पूजीगत आय “आय” के अन्तर्गत नहीं आती। आयकर के अन्तर्गत जिन जिन साधनों द्वारा हुई आय पर कर लगता है उनका उल्लेख इस अध्यायके कण्डिका ४ (Paragraph 4) में किया जा चुका है।

११ अर्जित आय (Earned Income) — धारा २ (६ एए)

भारतीय आयकर अधिनियम अर्जित आय तथा अनर्जित आय में भेद करता है। अर्जित आयसे तात्पर्य उस आय से है जो पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं —

(१) अर्जित आय के तीन मुख्य प्रकार हैं —

- (क) वेतन।
- (ख) व्यावसायिक आमदनी अथवा व्यापार के लाभ। और
- (ग) वैयक्तिक पुरुषार्थ द्वारा हुई आय जैसे, डायरेक्ट्स फीस, पुस्तकों पर अधिकार-शुल्क (Royalties) इत्यादि।

(२) निम्न प्रकार के कर दाताओं की आय ही कमाई हुई आय हो सकती है —

- (क) व्यक्ति।
- (ख) अविभक्त हिन्दू परिवार।
- (ग) अन रजिस्टर्ड फर्म।
- (घ) अन्य जन-मंडल।

- (३) यदि किसी व्यक्ति के कर-निर्धारण में उसकी पत्नि अथवा उसके किसी नाबालिग सतान की कोई अर्जित आय शामिल की गई है तो उस व्यक्तिके लिए वह अर्जित आय मानी जायगी।
- (४) वित्त अधिनियम (नम्बर २) १९५७ के पहले अर्जित आय पर २०% छूट (कुछ अन्य शर्तोंके साथ) मिलती थी। अब यह अर्जित आय छूट (Earned Income Relief) बिल्कुल बन्द हो गई है। अर्जित आय की अपेक्षा अनर्जित आय पर अतिरिक्त वृद्धि कर (Additional Sur-charge) लगता है। बस अर्जित आय को केवल यही रियायत है।

१२ कृषि-आय (Agricultural Income) — धारा २ (१)

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत सभी प्रकार की आय पर कर नहीं लगता। कुछ ऐसी भी आय है जो सर्वथा कर-मुक्त है। कृषि-आय भी ऐसी ही एक आय है। इसलिए इसकी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि-आय से तात्पर्य उन तमाम आय से है जो निम्न शर्तों को पूरा करती है —

- (१) कि वह आय भारत में स्थित किसी भूमि से है।
- (२) कि वह भूमि किसी कृषि-कार्यमें प्रयोग की गई है। तथा
- (३) कि वह भूमि ऐसी है जिस पर सरकार को लगान अथवा किसी स्थानीय सत्ता को स्थानीय कर (Local rate) दिया गया है।

कोई भी आय जो इन तमाम शर्तों को पूरा नहीं करती वह कृषि आय नहीं हो सकती। जैसे, निम्न प्रकार की आय कृषि-आय नहीं है —

- (१) हाट-बाजारों, घाट अथवा मछली-क्षेत्रों से होने वाली आय।
- (२) सिंचाई के लिए पानी देने से आय।
- (३) पत्थरों की खानों से होने वाली आय।
- (४) खानों से प्राप्त होने वाली रायट्टी से आय, इत्यादि।

निम्न रूपों में होने वाली आय कुछ अगो में कृषि-आय है तथा कुछ अशो में अकृषि-आय है —

- (अ) भारत में चाय पैदा करके बेचने वालोंकी आय (६०% आय कृषि आय है।) तथा
- (ब) किसी गव्वर कारखाना कम्पनी की आय जिसके अपने निजी कृषि फार्म हैं तथा जो कारखाने के लिए अपनी ही ईख पैदा करती है।

कृषि-आय निम्न प्रकार की हो सकती है —

- (१) जमीनदार द्वारा वसूल किया हुआ लगान या किराया ।
- (२) पैदावार से कृषक की आय या लगान लेने वाले व्यक्ति की कृषि पैदावार से आय ।
- (३) कृषक या लगान लेने वाले की पैदावार को बिक्री योग्य बना देने की विधि से आय ।
- (४) कृषि पैदावार को बेचने से होने वाली आय ।
- (५) उस जायदाद की आय जो कृषि के काम में आती है ।

१३ आकस्मिक आय (Casual Income) — धारा ४ (३) (vii)

आकस्मिक आय वह आय है जिसका स्वरूप आकस्मिक है तथा जो किसी व्यापार से या किसी व्यवसाय, पेशे अथवा अन्य काम करनेसे उदय न हो। ऐसी आय कर-मुक्त है। लॉटरी में मिलने वाला इनाम, घुड़दौड़ में हार-जीत पर लाभ इत्यादि आय आकस्मिक है।

१४ आयकर दाता (Assessee) — धारा २ (२)

आय कर दाता वह है जिसके द्वारा आयकर दिया जाता है या जिसे आयकर विधान के अनुसार सरकार को कोई रकम देनी हो या जिसपर आय या हानि के कर-निर्धारण की या कर-वापसी की कोई कार्य-वाही जारी की गयी हो। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त उसके वैधानिक प्रतिनिधि भी आयकर दाता समझे जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति जिसे किसी दूसरे व्यक्ति की आय में से कर काटना चाहिये, कर नहीं काटे, अथवा कर काट लेने के उपरान्त उसे सरकार को अदा नहीं करे तो उस व्यक्ति को भी आयकर दाता माना जाएगा।

१५ आयानुसार बनाम विभागानुसार कर-पद्धतिया (Step system versus slab system of Taxation) —

कर लगने वाली आय पर आयकर की सगणना दो पद्धतियों से की जा सकती है — आयानुसार और विभागानुसार। आयानुसार पद्धति (step system) में कुल आयकी पूरी रकम पर एक ही दरके अनुसार जो कुल आय पर लागू होती हो, आयकर चुकाना पड़ता है। यदि आय की विभिन्न रकमों के लिए आय ऊँची है, तो उसके लिए दर भी ऊँची है। यह पद्धति १ अप्रैल १९३९ से बन्द कर दी गई, क्योंकि यह अन्यायपूर्ण थी। इस पद्धति के अनुसार जो कठोरता अन्याय, और असमान फल होते थे, उन्हें दूर करने के लिए १-४-१९३९ से एक नई और अधिक न्यायोचित करारोपण की पद्धति जिसे विभागानु-

सार करारोपण (Slab system) कहते हैं, प्रचलित हुई। इसके अनुसार आय को विभिन्न भागो में बाँटा जाता है। प्रत्येक अगले विभाग के लिए बढ़ती हुई आय करकी दर लगाई जाती है। जैसे १९५९ के वित्त अधिनियमके अनुसार निर्धारित दरे इसी पद्धति के अनुसार हैं। उदाहरण के लिये देखिए अध्याय १२

१६ कुल आय (Total Income) — धारा २ (१५)

कर-दाताकी कुल आय से आशय उसकी आय की उस कुल रकम से है, जिस पर उसका निवास-स्थानानुसार कर लगता है तथा जो आय-कर अधिनियम द्वारा निर्धारित तरीके से मालूम की गई है। इसकी गणना के लिए देखिए अध्याय १०

१७ कुल विश्व आय (Total World Income) — धारा २ (१५)

कर-दाता की कुल विश्व आय से अभि प्राय उसकी समस्त आयसे है, भले ही वह विश्व में कहीं भी उत्पन्न हुई हो। निम्न प्रकार की आय कुल आय में तो शामिल नहीं की जाती लेकिन कुल विश्व आय निकालने के लिए की जाती है —

- (१) किसी निवासीकी न भेजी हुई विदेशी आय में से ४,५०० रु० की वैधानिक कटौती।
- (२) किसी व्यक्ति द्वारा एक संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य के नाते परिवार की आय में से प्राप्त की हुई कोई रकम।

कुल विश्व आयका निकालना केवल अनिवासीके लिए ही जरूरी होता है।

१८ कर-मुक्तिवाली आय (Exempted Income) —

एक व्यक्ति का कर-दायित्व मालूम करने के लिए उसकी कर-मुक्त आय को भी ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ आय पूर्णतया करमुक्त है तो कुछ आंशिक रूप में। आंशिक कर-मुक्त आयपर एक प्रकार की कटौती दी जाती है। कर योग्य आय पर लगते वाले कर में से इस प्रकार की करमुक्त आय की कटौती (Rebate) की रकम कम की जाती है।

१९ करदाताका प्रतिनिधित्व (Representation of an Assessee) — धारा ६१

सिवाय उस समय के जबकि कर-दाता को आयकर विभाग में स्वयं उपस्थित होना पड़ता है, वह सर्वदा निम्न प्रकार के व्यक्तियों द्वारा जिन्हें

लिखित अनुमति द्वारा यह अधिकार प्रदान कर दिया गया हो, अपना प्रति-निधित्व करा सकता है —

- (१) कोई रिश्तेदार।
- (२) कोई भी मुनीम, गुमास्ता या अन्य नौकर।
- (३) वकील।
- (४) अकाउन्टेन्ट।
- (५) आयकर-सलाहकार।

प्रश्न

प्र० १ निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए —

(१) गत वर्ष, (२) कर-क्षेत्र, (३) आयकर अधिकारी (४) अपिलेट ट्रिब्यूनल, (५) कर-दाता का प्रतिनिधित्व, (६) आयानुसार बनाम विभागानुसार कर पद्धतियाँ, (७) आकस्मिक आय (८) अर्जित आय।

उत्तर देखो कड़िका (परिच्छेद) (१) ८, (२) ९, (३) ६, (४) ६ (८), (५) १९, (६) १५, (७) १३, (८) ११।

प्र० २ 'कृषि-आय' पर एक छोटा सा निबन्ध लिखिए।

उत्तर देखो कड़िका १२।

कर-दाताओं का निवास-स्थान

(अ) कर-दाताओंका निवास-स्थानके अनुसार वर्गीकरण (Classification of Assesseees on the basis of their residence)
— धाराएँ ४ए तथा ४बी

१ धारा ४ (१) के अनुसार कर-दाता का दायित्व मुख्यतः उसके निवास-स्थान पर निर्भर रहता है। निवास-स्थान के हिसाब से कर-दाता निम्न तीन श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं —

- (क) कच्चा निवासी (Resident but not ordinarily resident)
- (ख) पक्का निवासी (Resident and ordinarily resident)
- (ग) अनिवासी (Non-resident)

यही नहीं भिन्न-भिन्न कर-दाता भिन्न-भिन्न दशाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार के निवासी होते हैं। इसका विस्तृत विवरण नीचे किया जाता है।

२ (१) व्यक्ति (Individual) —

(क) कच्चा निवासी — आयकर अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति गतवर्ष में भारतीय करक्षेत्र (जिसे अग्र वृत्तान्त में “भारत” नाम से सम्बन्धित किया गया है।) का किसी गत वर्ष के लिए कच्चा निवासी तभी समझा जाता है जबकि वह निम्न चार शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी करता हो —

- (१) उस गत वर्ष में वह भारत में १८२ दिन या इस से अधिक दिनो तक रहा हो, या
- (२) उसने उस गत वर्ष में भारत में १८२ या इससे अधिक दिनो तक कोई रहने का मकान रखा हो और उस वर्ष में वह भारत में किसी भी समय आया हो, या
- (३) वह गत चार वर्षों में कुल मिलाकर भारत में ३६५ दिन या इस से अधिक दिन रहा हो और उस वर्ष में किसी भी समय भारत में आया हो, परन्तु उसका इस प्रकार का आना सयोग-वश या आकस्मिक नहीं होना चाहिए, या
- (४) वह उस गत वर्ष में किसी भी समय भारत में आया हो तथा आयकर अफसर को यह निश्चय हो जाय कि वह व्यक्ति भारत में तीन साल से कम नहीं रहेगा।

(ख) पक्का निवासी — यदि कोई व्यक्ति किसी गत वर्ष के लिए निम्न-लिखित तीनों शर्तें पूरी करे तो वह उस गत वर्ष के लिए पक्का निवासी समझा जावेगा —

- (१) वह ऊपर बताए हुए नियमों के अनुसार कच्चा निवासी हो, तथा
- (२) वह गत १० वर्षों में कम से कम ९ वर्ष तक भारत का कच्चा निवासी रहा हो, तथा
- (३) वह गत ७ वर्षों में कम से कम २ वर्ष या अधिक समय तक भारत में रहा हो।

(ग) अनिवासी — कच्चे निवासी होने के लिए ऊपरलिखी ४ शर्तों में से यदि कोई व्यक्ति एक भी शर्त पूरी नहीं करता हो तो वह अनिवासी माना जायगा।

३ (ii) अन्यकर दाता (Other Assessee) —

- (१) हिन्दू अविभक्त परिवार — इसका निवास-स्थान निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित नियम लागू होते हैं —
- (क) यदि किसी ऐसे परिवार का प्रबन्ध और नियन्त्रण पूर्णतया भारत से बाहर हो तो ऐसा परिवार अनिवासी माना जाएगा।
- (ख) यदि किसी परिवार के प्रबन्ध एवं नियन्त्रण का कोई भी अंश भारत में हो तो ऐसा परिवार कच्चा-निवासी माना जाएगा।
- (ग) परिवार के पक्का निवासी माना जाने के लिए यह आवश्यक है कि उसका कर्ता कर-क्षेत्र का पक्का निवासी हो।

(२) फर्म या अन्य जन-मंडल (Firm or other Association of persons) —

यदि गत वर्ष में उसका समस्त प्रबन्ध या नियन्त्रण भारत के बाहर न हो तो उसे उस वर्ष के लिए 'कच्चा निवासी' माना जाता है। ऐसे 'कच्चे निवासी' स्वतः ही 'पक्के निवासी' मान लिये जाते हैं।

(३) प्रमंडल (Company) —

एक कंपनी भारत में गत वर्ष के लिए तब निवासी समझी जाएगी जबकि निम्न २ शर्तों में से वह कोई भी एक शर्त पूरी करे —

- (क) उसका प्रबन्ध या संचालन पूर्ण रूप से कर-क्षेत्र में रहा हो, या

(ख) वह भारतीय प्रमडल हो। (यह शत एक अप्रैल १९५८ से पुरानी शत के बदले म लागू की गई है।)

कोई कंपनी यदि 'निवासी' है तो वह 'पक्का निवासी' भी समझी जाएगी।

(ब) निवास-स्थानके अनुसार कर-भार (Incidence of Taxation on the basis of residence) —

(४) भिन्न भिन्न कर-दाताओं को उनके निवास-स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न आय पर भिन्न भिन्न कर देना पड़ता है। प्रत्येक कर-दाता का उसके निवास-स्थान के अनुसार जो आय-कर दायित्व है वह निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है —

कर का भार (Incidence of Tax)

(क) पक्का निवासी Ordinary Resident) (१)	(ख) कच्चा निवासी (Resident) (२)	(ग) अनिवासी (Non-resident) (३)
I भारतीय आय —		
(१) वह समस्त आय जो कर क्षेत्र (अर्थात् भारत) में प्राप्त हुई है या उत्पन्न हुई है, अथवा जिसका प्राप्त होना या उत्पन्न होना भारतमें समझा गया है।	(१) वही जो खाने (१) में है।	(१) वही जो खाने (१) में है।
(२) वह समस्त आय जो भारत में उपार्जित (accrued) या पैदा की गई है अथवा जिसका उपार्जन वा पैदा होना भारत में माना गया है।	(२) वही जो खाने (१) में है।	(२) वही जो खाने (१) में है।
II विदेशी आय —		
(३) वह समस्त आय जो कर-दाता ने गतवर्ष में कर-क्षेत्र से बाहर पैदा की है और जो गत-वर्ष में ही कर-क्षेत्र में लाई गई है।	(३) वही जो खाने (१) में है।	

(४) वह समस्त आय ४,५०० घटाकर) जो कर-दाता ने भारत के बाहर विदेशों में गत वर्ष में उत्पन्न की है परन्तु जो भारत में नहीं लाई गई है।

(४) वह समस्त आय (४,५०० घटाकर) जो कर-दाता ने भारत के बाहर विदेशों में गत वर्ष में भारत से संचालित व्यापार या पेशे से उत्पन्न की है परन्तु जो भारत में नहीं लाई गई है।

नोट - भारतीय वित्त अधिनियम १९५९ द्वारा भारत में नहीं लाई गई विदेशी आय पर ४५००. की उपरोक्त तरीके से दी जाने वाली छूट १-४-६० से बन्द कर दी गई है।

(५) वह समस्त आय जो भारत के बाहर कर-दाता ने १-४-१९३३ को या इसके बाद और गत वर्ष से पूर्व पैदा की है तथा जो गत वर्ष में भारत में लाई गई है। (कुछ शर्तें पूरी करने पर यह आय कर-मुक्त हो जाती है)

(५) वही जो खाने (१) में है

प्रश्न सख्या २

एक करदाता जिसका कि गत वर्ष ३१ मई १९५९ को समाप्त होता है, की आय निम्न प्रकार है —

भारतीय आय

- (१) वेतन ११,५०० रु०।
- (२) कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज ५०० रु० तथा अन्य सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज १००० रु० (सकल)।
- (३) मकान से १००० रु० का नुकसान।
- (४) एक अन रजिस्टर्ड फर्म से लाभ का हिस्सा १५००० रु०
- (५) लाभांश (सकल) ६०० रु० तथा बैंक से प्राप्त ब्याज ४०० रु०।
- (६) अविभक्त हिंदू परिवार से अपने हिस्से की आय ३,००० रु०

विदेशी आय

(१) अफ्रीका से भारत भेजी गई आमदनी ५,००० रु० ।

(२) ईरान में किये गये व्यापार द्वारा आय (व्यापार भारत से संचालित है) १०००० रु० तथा मकान से आय २,००० रु०

गत वर्ष में वह अफ्रीका से १९५२ में बिना-कर लगी हुई आमदनी में से १०००० रु० भारत में लाया ।

कर-निर्धारण वर्ष १९६०-६१ के लिए उसकी कुल आय तथा कुल विश्व-आय की गणना करो अगर — (अ) वह पक्का निवासी है, (ब) कच्चा निवासी है या (स) अनिवासी है ।

उत्तर

भारतीय आय

	अ रु०	ब रु०	स रु०
१ वेतन ८,७००+१,२००+१,६००	११,५००	११,५००	११,५००
२ प्रतिभूतियों का ब्याज कर-देय	१,०००	१,०००	१,०००
कर-मुक्त	५००	५००	५००
३ मकान से हानि(-)	१,०००	१,०००	१,०००
४ अन रजिस्टर्ड फर्म का हिस्सा	१५,०००	१५,०००	१५,०००
५ अन्य साधनों से आय लाभार्ज (सकल)	६००	६००	६००
बैंक से प्राप्त ब्याज	४००	४००	४००
	२८,०००	२८,०००	२८,०००

विदेशी आय

१ पिछली कर नहीं दी हुई आय जो अफ्रीका से भारत में इस वर्ष लाई गई है	१०,०००	१०,०००	—
२ अफ्रीका की आमदनी जो भारत में लाई गई है	५,०००	५,०००	
३ ईरान में होने वाली आय जो भारत में नहीं लाई गई है	१२,०००	१०,०००*	
कुल आय	५५,०००	५३,०००	२८,०००
(केवल भारत से संचालित व्यापार की आय ही) अविभक्त हिन्दू परिवार से प्राप्त हिस्सा			३,०००
विदेशी आय			१०,०००
कुल विश्व आय		रु०	४८,०००

प्रश्न

प्र १ भारतीय आयकर कानून ने कर-दाताओं को तीन श्रेणी में विभक्त किया है - (१) पक्का निवासी, (२) कच्चा निवासी, तथा (३) अनिवासी या विदेशी ।

व्यक्ति, फर्म (साम्प्रदायी सस्था), अविभक्त हिन्दू परिवार तथा कंपनी के बारे में उपरोक्त श्रेणियों को निश्चय करने की विधि बताइये ।

उ कड़िका १ से ३ तक देखिये ।

प्र २ निम्न लिखित विवरण से एक व्यक्ति की कर निर्धारण वर्ष १९५९-६० के लिए कुल आय तथा विश्व आय निकालिए जब कि वह (१) पक्का निवासी है, (२) कच्चा निवासी है, अथवा (३) अनिवासी है ।

वेतन ८,००० रु०, प्रतिभूतियों का ब्याज २००० रु०, व्यापार से लाभ ५,०००, लाभांश (सकल) १,००० रु०, मकान से हानि १,००० रु० ।

भारत में लाई गई विदेशी आय १२,००० रु०, भारत में नहीं लाई गई विदेशी आय — भारत से संचालित व्यापार से ८,००० तथा मकान से २,०००

उ कुल आय (१) ३२,५०० रु०, (२) ३०,५०० रु०, (३) १५,००० रु० । कुल विश्व आय ३७,००० रु० ।

कर-मुक्त आय EXEMPTED INCOME

१ अक्सर यह कहा जाता है कि आयकर अधिनियम एक बड़ा ही कठोर कानून है तथा इसका उद्देश्य कर-दाताओं से अधिकतम कर-वसूली है। परन्तु यह कथन निराधार है। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कई ऐसी भी आय हैं जो सर्वथा कर-मुक्त हैं तथा कुछ ऐसी भी आय हैं जो आशिक रूप में कर-मुक्त हैं। ऐसी आय का वर्णन विस्तृत रूपसे नीचे दिया जाता है।

I पूर्णतया कर-मुक्त आय (Fully Exempted Income)

२ ऐसी आय जो आयकर तथा अतिरिक्त करसे पूर्णतया मुक्त है तथा जो कुल आयमें दर निश्चित करनेके लिए भी न जोड़ी जाए। (*Incomes wholly exempt from Income-tax and super-tax and not even included in total income for rate purposes*) — धारा ४ (३) इत्यादि

(१) धार्मिक या पुण्यार्थं जायदाद या व्यापारकी आय

उस जायदाद की आय (इसमें व्यापार की आय भी शामिल है) जो ट्रस्ट या अन्य वैधानिक उत्तर दायित्वों के द्वारा धर्मार्थं या पुण्यार्थं कार्यों के लिए रखी जाती हो। ऐसी आय धर्मार्थं या पुण्यार्थं कार्योंमें ही लगा दी जानी चाहिए।

(२) धार्मिक या पुण्यार्थं सस्था द्वारा प्राप्त चदा

किसी धार्मिक या पुण्यार्थं सस्था में जनता द्वारा स्वेच्छा से दिया हुआ चदा यदि वह चदा पूर्णतया उन्हीं धार्मिक या पुण्यार्थं कार्यों में खर्च किया जाय।

(३) स्थानीय सत्ताकी आय — स्थानीय सत्ता की वह आय जो उसकी सीमा में किए गए कार्यों से प्राप्त होती है।

(४) प्रोविडेंट फण्डकी प्रतिभूतियोंका ब्याज — वह ब्याज जो १९२५ के कानून के अन्तर्गत किसी प्रोविडेंट फण्ड की प्रतिभूतियों से प्राप्त होता हो।

(५) विशेष भत्ता — यदि कर्मचारी को कोई यात्रा (मनोरजन भत्ते के अतिरिक्त) किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिया गया है और वह

रकम कर्मचारी ने केवल अपने कर्तव्य पूर्ण करने में ही खर्च की हो तो इस भत्ते की केवल वह रकम जितनी उसने कर्तव्यपूर्ण करनेमें खर्च की है।

(६) (अ) किसी ऐसे व्यक्ति को जो भारत का नागरिक नहीं है, उसके मालिक द्वारा भारत से बाहर अपने घर जानेके लिए स्वयं, अपनी पत्नी तथा बच्चों के लिए प्राप्त हुई रकम तथा मुफ्त आने-जाने का मूल्य।

(ब) भारतके किसी नागरिक को अपने स्वयं, पत्नी तथा बच्चों के लिए अपने मालिक द्वारा छुट्टियों में अपने घर जानेके लिए यात्रा के सहायतार्थ दी गई कोई रकम।

(७) आकस्मिक आय (Casual Income)।

(८) कृषि आय (Agricultural Income)।

(९) स्वीकृत प्रोवीडेंट फंडकी आय — इस प्रकार के फंड के ट्रस्टियों द्वारा प्राप्त आय।

(१०) प्रिवी पर्स आदिकी आय — भारतीय रियासतों के राजाओं को प्रिवीपर्स के रूप में होने वाली आय, विदेशी राष्ट्रों के राजनैतिक कर्मचारियों की आय, विदेशी राष्ट्रों के दूतावास के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति की आय, कामनवेल्थ के ट्रेड कमिश्नर अथवा किसी अन्य विदेशी देश के किसी भी अन्य सरकारी प्रतिनिधि या किसी अन्य कर्मचारी की आय।

(११) भारतीय नागरिकोंको विदेशी भत्ता — भारतीय नागरिकों को भारत के बाहर नौकरी करने के उपलक्ष में सरकार द्वारा दिया गया किसी प्रकार का भत्ता। (यह छूट वित्त अधिनियम सन् १९५९ के द्वारा प्रवेश की गई है।)

(१२) नेपाली फौजके सदस्यकी आय — नेपाली फौजके किसी सदस्य का जो कि भारतीय सघीय फौज में कार्यकर रहा है, वेतन अथवा उसकी कोई भी विदेशी आय जो कि ऐसे सदस्य द्वारा भारत में लाई गई हो।

(१३) एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन—जो कि मुख्यतया श्रमिकों एवं मालिकों तथा श्रमिकों के पारस्परिक सम्बन्धों को नियन्त्रण करनेके लिए बनाई गई है, की ऐसी आय जो निम्न आय के शीर्षकों के अन्तर्गत आती हो —

- (अ) प्रति भूतियोका ब्याज,
- (ब) जायदाद की आय, तथा
- (स) अन्य साधनो की आय।

(यह छूट वित्त अधिनियम सन् १९५८ के द्वारा प्रवेश की गई है।)

- (१४) **विशेष जायदादकी आय** :— इस प्रकार के मकान के बनने के बाद दो वर्ष तक के किराये की आय जो जोकि ३१-३-१९४६ के बाद और १-४-१९५६ के पहले बनाया गया हो।
- (१५) **वैज्ञानिक अनुसंधान सघकी आय** — इस प्रकार के स्वीकृत वैज्ञानिक सघ की वह आय जो पूर्ण रूपसे सघ उद्देश्यों के लिए लगाई जाती है और जो ३१ मार्च १९४९ के बाद प्राप्त या उत्पन्न की गई है।
- (१६) **किसी विदेशी उद्यमके कर्मचारीका वेतन** — एक विदेशी उद्यम (Enterprise) के किसी कर्मचारी की भारत में रहते हुए की गई सेवाओं के उपलक्ष में प्राप्त की गई आय यदि (१) वह विदेशी उद्यम भारत में किसी भी प्रकार का व्यापार या पेशा न करता हो तथा (२) वह कर्मचारी भारत में ९० दिन से अधिक न रहा हो।
- (१७) **विदेशी प्रविधिज्ञोका पारिश्रमिक (Remuneration of Foreign Technicians)** — विदेशी प्रविधिज्ञों की कुछ सीमित समय की आय (अर्थात् उसके भारत आने के साल तथा उसके बाद के एक साल तक की आय) जो कि भारतीय निजी उद्योगों से प्राप्त की गई हो यदि वह विदेशी प्रविधिज्ञ भारत में आने के पूर्व ४ वर्षों में कभी भी भारत का निवासी नहीं रहा हो।

यदि भारत में उस वर्ष में जब कि वह आया हो तथा उसके अगले वर्ष में कुल मिलाकर ३६५ दिवस या अधिक रहा हो तो यह छूट उसके आने के बाद से ३६५ दिन तक सीमित रहेगी। परन्तु यदि उसकी नौकरी का समझौता सरकार द्वारा स्वीकृत है तो यह छूट उसके भारत में आने वाले साल तथा उसके अगले दो वित्त वर्षों तक लागू रहेगी।

- (१८) **किसी व्यक्ति की ऐसी आय जो उसको किसी विदेशी सरकारसे प्राप्त हो तथा जिसकी सेवाएँ किसी सहकारी प्राबैधिक कार्यक्रम अथवा परियोजना (Cooperative Technical Programme or Project) के अन्तर्गत भारतको दी गई हो।**

(१९) ऐसे किसी ऋण-पत्र का व्याज या उसके भुगतान पर दिया गया प्रीमियम जो केन्द्रीय सरकार ने अपने तथा अन्तर्-राष्ट्रीय बैंक के समझौते के अन्तर्गत जारी किए हो और जिस पर व्याज दिये जाने की भारतीय सरकार द्वारा प्रत्याभूति (Guarantee) दी गई हो। यह केवल अनिवानी के लिए ही है

(२०) दस वर्षीय $3\frac{1}{2}\%$ ट्रेजरी सेविंग्स डिपोजिट सर्टिफिकेट्स का व्याज जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके आदेश द्वारा प्रचलित किए गये हो।

(२१) पोस्ट ऑफिस सेविज बैंक, पोस्टऑफिस केश सर्टिफिकेट्स, पो आ नेशनल सेविज सर्टिफिकेट्स तथा पो आ नेशनल प्लान सर्टिफिकेट्स का व्याज।

(२२) वित्त अधिनियम (नम्बर २) सन् १९५७ ने ऐसे व्याजकी रकमों पर जो निम्न प्रकारके उधार तथा ऋणों पर दी जाती है, यह नई छूट प्रवेश की है —

(क) सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी (local authority) द्वारा किसी अनिवासी या भारत के बाहर स्थित किसी सस्था द्वारा भारत के बाहर के स्रोतों से प्राप्त ऋणपर,

(ख) किसी भारतीय औद्योगिक उद्यम द्वारा किसी ऐसे ऋण-समझौतेके अन्तर्गत जो कि विदेश में किसी ऐसी वित्त सस्था (financial institution) जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी साधारण या विशेष हुकम द्वारा स्वीकृत हो, के साथ किया गया हो प्राप्त ऋण की रकम पर, तथा

(ग) किसी भारतीय औद्योगिक उद्यम (Indian Industrial undertaking) द्वारा भारत के बाहर पूंजी तथा मशीनरी सयन्त्र (Capital Plant Machinery) खरीदने के सम्बन्ध में ली या की गई ऋण या उधार (loan or debt incurred) की रकम पर (यदि साधारण रूप से उस ऋण या उधार की शर्तों को तथा विशेष कर उसकी वापसी की शर्तों (terms of repayment) को ध्यान में रखकर केन्द्रीय सरकार ने उसे स्वीकार किया हो)।

(२३) उन सब प्रतिभूतियोंका व्याज जो कि लका के केन्द्रीय बैंक के निर्गम विभाग (Issue Department) के पास है।

(२४) वे सब दैनिक भत्ते जो किसी व्यक्ति को उसके अधिराज्य (dominion) विधान सभा या सविधान सभा या ससद या

राजकीय-विधान सभा या उनके किसी कमेटी की सदस्यता के कारण मिलते हो।

- (२५) १-४-१९३८ के पहले जारी किये हुए किसी ऋण पर दिया हुआ किसी अनिवासी को ब्याज।
- (२६) आसाम के कुछ निश्चित आदिम वासी क्षेत्रों में रहने वाले किसी आदिवासियोंकी आय।
- (२७) वीरता पुरस्कार (Gallantry awards) के विजेताओं को केन्द्रीय सरकार या किसी राजकीय सरकार द्वारा नकद रूप में अथवा वस्तु रूप में किए गये भुगतान का मूल्य।—धारा ४ (३)
- (२७) हिन्दू अविभक्त परिवार के सदस्य की आय किसी ऐसे हिन्दू परिवार के सदस्य द्वारा परिवार की आय में या अविभाजित सम्पत्ति में से आमदनी का हिस्सा जो उसे मिला हो—धारा १४(१)।
- (२८) स्वीकृत सुपरएनुएशन फंड की आय—धारा ५८ आर।

II आंशिक कर-मुक्त आय (Partly Exempted Income) —

- (क) ३ वह कर-मुक्त आय जो कुल आयमें केवल आयकर की दर निकालने के लिये जोड़ी जाती है (Income Exempt from income-tax and super-tax but included in the total income for rate purposes only) — ऐसी आय निम्न है —

(१) उस सहकारी समिति (co-operative society) की जो बीमा व्यापार न करती हो निम्न प्रकार की आय —

(अ) उसके व्यापार का लाभ।

(ब) सूद या लाभांश (dividends) जो उसे दूसरी सहकारी समिति में रुपया लगाने से प्राप्त हुआ हो।

(स) ममिति के गोदाम (ware houses) का किराया। तथा

(द) प्रतिभूतियों के सूद तथा जायदाद के किराये से आय यदि समिति की कुल आय २५००० रु० से अधिक नहीं है, तथा वह समिति कोई मकान—समिति या नगर उपभोक्ता समिति अथवा यातायात व्यापार करने वाली समिति नहीं है।

(२) एक सदस्य द्वारा प्राप्त सहकारी समिति से लाभांश।

- (३) कानून द्वारा स्थापित वस्तुओं के विपणन हेतु (for marketing of commodities) किसी भी सस्था द्वारा गोदाम इत्यादि का किराया।
- (ख) ४ वह आय जो आय-करसे मुक्त है परन्तु अतिरिक्त-करसे नहीं तथा जो कुल आयमें जोड़ी जाती है (Income exempt from income-tax but not from super-tax and included in the total Income) ऐसी आय निम्न प्रकार की है —
- (१) किसी सरकारी कर्मचारी के वेतन में से उसको या उसके परिवार को वार्षिक वृत्ति (Annuity) देने के लिए सरकार द्वारा काटी गई रकम (वेतन के $\frac{1}{5}$ हिस्से तक)।
 - (२) केन्द्रीय तथा राजकीय सरकारों की कर-मुक्त प्रतिभूतियों का व्याज।
 - (३) (अ) अन रजिस्टर्ड फर्म के साझेदार का लाभ तथा रजिस्टर्ड फर्म के अनिवासी का हिस्सा तथा अन्य जन-मंडल के सदस्य की उस मंडल से प्राप्त आय यदि उस हिस्से पर कर दे दिया गया है।
 - (ब) रजिस्टर्ड फर्म के साझेदार के लाभ के हिस्से पर दिया गया रजिस्टर्ड फर्म द्वारा आयकर।
 - (४) जीवन बीमा का प्रीमियम (बीमा पॉलिसी की पूरी रकम के $\frac{1}{5}$ हिस्से तक) किसी व्यक्ति के अपने या उसकी स्त्री के जीवन बीमा पर तथा हिन्दू अविभक्त परिवार के किसी पुरुष या स्त्री के बीमा पर।
 - (५) सन् १९२५ के प्रोविडेंट फंड ऐक्ट के अन्तर्गत स्थापित किसी प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी द्वारा दिया गया चढ़ा।
 - (६) स्वीकृत प्रोविडेंट फंड में दिया हुआ कर्मचारी द्वारा अपने हिस्से का चढ़ा।
 - (७) सुपर अनुएशन फंड में कर्मचारी द्वारा दिया हुआ चढ़ा।
- नोट — (४), (५), (६), तथा (७) में कर-मुक्ति के लिए लिखी गई रकमों की कुल जोड़ एक व्यक्ति के लिए उसकी आमदनी के $\frac{1}{5}$ भाग या ८००० (जो भी कम हो) तथा एक हिन्दू अविभक्त परिवार के लिए उसकी आमदनी के $\frac{1}{5}$ भाग अथवा १६,००० (जो भी कम हो) से अधिक नहीं हो सकती।

(ग) ५ वह आय जो अतिकरसे मुक्त है किन्तु आयकरसे नहीं तथा जो कुल आयमें जोड़ी जाती है (Income which is exempt from Super-tax but not from Income-tax and included in Total Income) —

(१) एक कम्पनी द्वारा ३१-३-१९५२ के पश्चात् बनी हुई किसी भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश जब कि (अ) केन्द्रीय सरकार इस बात से सतुष्ट हो जाय कि वह भारतीय कम्पनी कुछ उल्लेखित उद्योगों (जैसे लोहा व इस्पात, कोयला, सीमेन्ट इत्यादि) में पूर्ण तथा अथवा मुख्यकर लगी हुई है, तथा (ब) यदि धारा १५ सी उस भारतीय कम्पनी पर लागू की जा सके तो उस कम्पनी की आय उस धारा के अन्तर्गत कर-मुक्त हो सकती हो।

(२) विनियोग प्रत्यास प्रमडलो (Investment trust Companies) की कुल आय का वह भाग जो उन्हें दूसरे प्रमडलो से लाभांश के रूप में प्राप्त हुआ है।

(घ) ६ पुण्यार्थ दिए हुए दान (Charitable Donations) धारा १५ बी

१-४-१९५३ से केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किसी पुण्यार्थ सस्था में दिया हुआ चंदा कर-मुक्त है। यह छूट निम्न लिखित शर्तों पर निर्भर है।

- (१) दान की रकम २५० रु० से कम न हो।
- (२) दान की कुल रकम कुल आय (कर-मुक्त आय घटाने के बाद) के ५% से अधिक न हो।
- (३) चंदे की कुल रकम किसी भी दशा में १,००,००० रु० से अधिक नहीं हो।
- (४) दान की रकम औसत दर के लिए कुल आय में जोड़ी जाती है और उपरोक्त नियमों के अनुसार दान की रकम पर औसत दर से छूट दी जाती है। कर की छूट कर-मुक्त आय की रकम के आधे भाग से अधिक नहीं मिल सकती।
- (५) कम्पनी द्वारा दी गई दानकी रकम केवल आय-कर से मुक्त है, अतिकर से नहीं। अन्य करदाताओं द्वारा दिया गया दान आय-कर व अतिकर दोनों से ही मुक्त है।
- (६) पुण्यार्थ सस्था ऐसी हो जो निम्न शर्तें पूरी करती हो —

- (अ) उसकी आय धारा ४ (३) के अधीन कर-मुक्त है।
- (ब) जो किसी विशेष जाति या सम्प्रदाय के हित के लिए नहीं है।
- (स) जो कि अपने नियमित पूण हिसाब-किताब रखती हो, तथा
- (द) जो कोई सार्वजनिक हितकारी सस्था है या सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम १८६० या भारतीय कपनी अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड हुई है या कोई ऐसी सस्था है जिसकी पूर्णतया अथवा कुछ अंश में सरकार या स्थानीय सत्ता द्वारा आर्थिक व्यवस्था है।

(ड) ७ नए औद्योगिक उद्यम (New Industrial Undertakings) धारा १५सी —

नए औद्योगिक उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिये उनके पूँजी पर ६% लाभ पाँच वर्ष की अवधि तक आयकर तथा अतिरिक्त कर दोनों से मुक्त कर दिए गए हैं। किन्तु यह आय कुल आय में दर निकालने के लिए जोड़ी जाती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि ऐसा उद्यम १-४-१९४८ से १३ वर्ष तक कभी भी अपना उत्पादन-कार्य आरम्भ न करे। अन्यथा नीचे दी जाती है —

- (१) ऐसा उद्यम किसी पूर्व स्थापित उद्यम का अंग नहीं है।
- (२) यदि वह उद्यम शक्ति का प्रयोग करता है तो काम करनेवालों की संख्या कम से कम १० अन्यथा २० होनी चाहिये।

प्रश्न

प्र १ निम्न लिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए —

- (१) पूर्णार्थ दिये हुए दान पर कर की छूट।
- (२) नए औद्योगिक उद्यम पर कर की छूट।
- (३) (१) देखो कड़िका ६
- (२) देखो कड़िका ७

प्र २ उन सब आय का विवरण कीजिए जो कि आयकर तथा अतिरिक्त कर से पूर्णतया मुक्त है तथा जो कुल आय में दर निश्चित करने के लिए भी नहीं जोड़ी जाती है।

३ देखिए कड़िका २

दूसरा भाग
आयके शीर्षक
(HEADS of INCOME)

अध्याय ४

वेतन : धारा ७

SALARIES

१ पिछले एक अध्याय में हम देख चुके हैं कि आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आय के कुछ शीर्षक निर्धारित हैं जिनके अन्तर्गत होने वाली आय पर ही आय कर लगाया जाता है, अन्य पर नहीं। ऐसे शीर्षकों में से सर्व प्रथम शीर्षक वेतन का है।

२ वेतन सम्बन्धी ज्ञातव्य बातें — वेतन शीर्षक के अन्तर्गत आय को मालूम करने के लिए हमें निम्न लिखित बातों को पूर्ण रूप से ध्यान में रखना चाहिये —

- (१) भारत की केन्द्रीय या राजकीय सरकार, कंपनी, स्थानीय प्राधिकारी या अन्य भारतीय जन मंडल या निजी मालिक द्वारा दिया हुआ वेतन ही इस धारा के अन्तर्गत वेतन माना जाकर कर योग्य है। अतः विदेशी सरकार द्वारा किसी भारतीय या अन्य कर्मचारी को दिया जानेवाला वेतन इस धारा के अन्तर्गत कर-योग्य नहीं है।
- (२) वेतन विशेष (Salary proper) मजदूरी (wages), बोनस एन्ग्रुटी, ग्रेचूटी, पेंशन, फीस, कमीशन, अन्य प्रतिफल (perquisite) तथा वेतन के स्थान पर या साथ में लाभ का हिस्सा, अन्य भत्ता या ऊपरी आमदनी भी वेतन में शामिल है।
- (३) वेतन लेने वाले तथा देने वाले के बीच कर्मचारी तथा मालिक का सम्बन्ध होना आवश्यक है।
- (४) पेशगी तनख्वाह भी वेतन में जोड़ी जाती है। वेतन की विशेषता यह है कि उस वेतन पर जो कि देय या बाकी है चाहे वह प्राप्त किया गया नहीं तथा उस वेतन पर जो कि प्राप्त किया गया है चाहे वह देय (due) हो या नहीं, कर लगाया जाता है।
- (५) कर्मचारी को पेंशन के स्थान पर मिला हुआ एकत्रित धन कर-मुक्त है।

- (६) कर्म चारी को १६-४-१९५० के पश्चात् केन्द्रीय या राजकीय के सशोधित पेशन नियम के अनुसार मिली हुई ग्रेचुटी (death cum retirement gratuity) तथा वैधानिक प्रोविडेंट फंड, स्वीकृत-प्रोविडेंट फंड या सुपर एनुएशन फंड से प्राप्त मचित रकम कर-मुक्त है।
- (७) प्रोविडेंट फंड या जीवन बीमा के प्रीमियम सम्बन्धी सभी मुख्य नियमों का ज्ञात वेतन की कर-योग्य निकालने के लिए आवश्यक है। इनका वर्णन नीचे दिया जाता है।

३. प्रतिफल (Perquisites) — धारा ७ (१) अर्थ १

प्रतिफल का अर्थ होता है वेतन के अतिरिक्त कुछ अन्य भत्ता या किसी प्रकार का फायदा। इस धारा के अन्तर्गत निम्न प्रकार के प्रतिफल वेतन की आय में सम्मिलित किए जाते हैं —

- (१) (अ) किराया-मुक्त मकान (Rent-Free house) का मूल्य जो कि वेतन का १०% (यदि मकान असुसज्जित (un-furnished) है) अथवा १२½% (यदि मकान सुसज्जित (furnished) है) भाग के बराबर माना जाता है।
- (ब) मकान किराया-भत्ता (House Rent Allowance) की पूरी रकम चाहे वह कितनी भी क्यों न हो।
- (२) किसी कंपनी द्वारा किसी सचालक अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका कंपनी में वास्तविक हित हो, मुफ्त या कम कीमत पर दी गई सुविधा।
- (३) किसी भी कर-दाता को, जिसकी वेतन से आय १८,००० रु० प्रति वर्ष से अधिक है, कोई मुफ्त या कम कीमत में दी गई सुविधा।
- (४) मालिक द्वारा ऐसे दायित्व का भुगतान जो कर-दाता को करना पड़ता है।
- (५) मालिक द्वारा दिया गया कर-दाता के जीवन बीमे का प्रीमियम अथवा मालिक द्वारा कर्मचारी के वेतन पर लगाए गए आयकर की रकम।

४. वेतनके स्थान पर लाभ (Profits in lieu of Salary) धारा ७ (१) अर्थ २ —

- (अ) कर्मचारी को नौकरी छोड़ने पर हजनेकी नकद या किसी अन्य रूप में मिली हुई रकम वेतन में सम्मिलित की जाती है।

- (ब) अस्वीकृत प्रोविडेंट फंड से नौकरी के अन्त में प्राप्त रकम का केवल मालिक द्वारा दिया हुआ चदेका हिस्सा तथा इस पर व्याज वेतन में जोड़ा जाता है।

५ वेतनमें से कटौतियाँ (Deductions from Salaries)— चारा ७(२)

वेतन की कुल आय निकालने के लिए निम्न कटौतियाँ दी जाती हैं —

- (अ) अपने वेतन में से ५०० रु० तक की रकम जो पुस्तक या अन्य प्रकाशनो पर (जो कि उसके कर्तव्य पालन के लिए सहायक हो) कर-दाता द्वारा खर्च की गई हो।
- (ब) मनोरंजन भत्ता (Entertainment Allowance) कर-दाता के वेतन (विशेष भत्ते प्रतिफल इत्यादि रकम के अलावा) के २०% भाग या ५,०००) रु० सरकारी कर्मचारी के लिए तथा ७,५०० अन्य कर्मचारियों के लिए (जो भी कम हो) यदि उस कर-दाता को ऐसा भत्ता सन् १९५५-५६ से पहले भी मिलता रहा हो।
- (स) यदि कोई कर्मचारी अपना निजी वाहन (own conveyance) रखता हो तथा उसे अपने सेवायोजन (employment) के लिए इस्तेमाल करता हो तो उसे उस वाहन पर किए हुए खर्च की उस राशि पर छूट मिलेगी जो कि आयकर अफसर प्राक्कलित (estimate) करे।
- (द) कर्मचारी द्वारा वेतन के अतिरिक्त प्राप्त कोई भत्ता या अन्य ऐसी रकम जो उसे अपने मालिक के लिये और विशेषतया अपने कर्तव्य-पालन करने में खर्च करनी पड़ती है। (केवल उतनी ही रकम जो वास्तवमें खर्च हुई हो)

प्रश्न सख्या ३ — एक व्यक्ति एक व्यापारी गृह में निम्न शर्तों पर नौकरी करता है —

- (१) २००० रु० मासिक वेतन।
- (२) ५% कमीशन पक्के लाभ पर, (पक्का लाभ — १,००,००० रु०)।
- (३) मोटरकार भत्ता १०० रु० मासिक
- (४) मालिक की ओर से एक असुसज्जित ~~किचन~~ — मुक्त मकान।

इसके अलावा उसे पुरानी बीकानेर स्टेट से २५० रु० प्रतिमास पेशन मिलती

है।

उस कर्मचारी की वेतन से कुल आय क्या होगी ?

उत्तर -	कर्मचारीका वेतन	रुपया
१२ मास का वेतन — २००० रु० प्रति मास की दर से		२४,०००
कमीशन ५% की दर से १,००,००० रु० पर		५,०००
मोटर कार भत्ता १०० मासिक		१,२००
किराया मुक्त मकान की कीमत (वेतन का दसवाँ भाग = $\frac{१}{१०} \times$		
२४,००० + ५००० + १,२०० = $\frac{१}{१०} \times ३०,२००$) =		३,०२०
पेशन २५० रु० प्रति मास की दर से		३,०००
	वेतन की कुल आय	रु० ३६,२२०

६ प्रोविडेंट फंड (Provident Funds)

वेतन शीर्षक की कुल आय निकालने के लिए यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि प्रोविडेंट फंड कितने प्रकार के होते हैं तथा उनसे सम्बन्धित कर्मचारियों की आय में प्रोविडेंट फंड की कौन सी रकम जोड़ी जाती है और कौनसी नहीं। प्रोविडेंट फंड मुख्यतया तीन प्रकार के होते हैं —

(१) वैधानिक प्रोविडेंट फंड।

(२) स्वीकृत प्रोविडेंट फंड।

(३) अस्वीकृत प्रोविडेंट फंड।

इनके बारे में विस्तृत वर्णन नीचे दिया जाता है —

७ वैधानिक प्रोविडेंट फंड (Statutory Provident Fund) •

(अ) परिभाषा वैधानिक प्रोविडेंट फंड वह है जिसपर प्रोविडेंट फंड अधिनियम १९२५ लागू होता है। यह फंड स्थानीय प्राधिकारियों, विश्वविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों तथा नगर पालिकाओं द्वारा रखा जाता है।

(ब) वेतन में जोड़ी जाने वाली रकमें केवल कर्मचारी का निजी चढ़ा (employee's own contribution) वेतन में जोड़ा जाता है। ऐसे प्रोविडेंट फंड में मालिक द्वारा दिया हुआ चढ़ा तथा ब्याज वेतन में नहीं जोड़े जाते, वे सत्रया कर-मुक्त हैं। नौकरी छोड़ने पर सम्पूर्ण संचित रकम जो कर्मचारी को प्राप्त होती है वह भी पूर्णतया कर-मुक्त है।

- (स) कर-मुक्त आय कर्मचारीका निजी चदा व जीवन बीमे का प्रीमियम दोनों मिला कर कुल आय के $\frac{1}{4}$ भाग या ८,००० रु० तक (जो भी कम हो) आयकर से (अतिरिक्त करसे नहीं) मुक्त है।

८ स्वीकृत प्रोविडेंट फंड (Recognised Provident Fund)

- (अ) परिभाषा कुछ नियमों का पालन होने पर जब कोई प्रोविडेंट फंड आयकर कमिश्नर द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है तो उसे स्वीकृत प्रोविडेंट फंड कहते हैं।—धारा ५८ सी।
- (ब) वेतन में जोड़ी जाने वाली रकमें (१) कर्मचारी द्वारा इस फंड में जमा कराया हुआ चदा, (११) मालिक द्वारा दिया गया चदा यदि वह कर्मचारी के वेतन के 10% भाग से अधिक है, तथा (१११) फंड की संचित राशि पर वेतन के $\frac{1}{4}$ भाग से अधिक अथवा 6% दर से अधिक दिया गया ब्याज।
- (स) कर-मुक्त आय (१) कर्मचारी का चदा मूल वेतन के $\frac{1}{4}$ भाग से नहीं) मुक्त है। (२) कर्मचारी का चदा तथा जीवन बीमे तक आय कर से अति कल का प्रीमियम दोनों मिलाकर कुल आय के $\frac{1}{4}$ भाग या ८,००० रु० तक (जो भी कम हो) आयकर से (अतिरिक्तकर से नहीं) मुक्त है।

९ अस्वीकृत प्रोविडेंट फंड (Unrecognised Provident Fund)

- (अ) परिभाषा जो प्रोविडेंट फंड आयकर कमिश्नर द्वारा स्वीकृत नहीं है वह अस्वीकृत प्रोविडेंट फंड कहलाता है।
- (ब) वेतन में जोड़ी जाने वाली रकमें (१) केवल कर्मचारी का स्वयं का चदा, मालिक द्वारा दिया गया चदा अथवा ब्याज प्रति वर्ष नहीं जोड़े जाते। (११) कर्मचारी के नौकरी छोड़ते समय संपूर्ण रकममें से मालिक द्वारा दिये गये चदे तथा उस पर दी गयी ब्याज की रकमवेतन में जोड़ी जाती है।
- (स) छूट केवल जीवन बीमे का प्रीमियम कुल आय के $\frac{1}{4}$ भाग या ८,००० रु० (जो भी कम हो) आयकर से (अतिरिक्त कर से नहीं) मुक्त है। अन्य किसी भी प्रकार की छूट चदे या ब्याज के बाबत नहीं दी जाती है।

१० जीवन बीमे के प्रीमियम पर छूट (Exemption on account of Life Insurance Premiums) धारा १५

- (अ) जीवन-बीमा का प्रीमियम, यदि करदाता न्यक्ति है तो उसके स्वयं के या उसकी पत्नी या पति के जीवन बीमा के लिए कुल आय के $\frac{1}{4}$ हिस्से या ८००० रु० तक (जो भी दोनों में से कम है) आयकर (अतिकर से नहीं)। मुक्त है। यदि कर दाता सयुक्त हिन्दू परिवार है तो उस परिवार के किसी भी पुरुष व स्त्री के जीवन बीमा की प्रीमियम उस परिवार की कुल आय के $\frac{1}{4}$ हिस्से या १६,००० रु० तक केवल आयकर से ही मुक्त है।
- (ब) प्रीमियम जीवन-बीमा पॉलिसी की पूरी रकम के १०% भाग से अधिक कभी नहीं होना चाहिए।
- (स) यदि प्रीमियम की रकम का भुगतान ऐसी रकम से किया गया है जो कि भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य नहीं है तो ऐसी रकम पर कोई भी छूट नहीं दी जाती।

नोट — सुपर एनुएशन फंड के चदे पर बीमा प्रीमियम की ही तरह छूट दी जाती है।

प्रश्न सख्या ४ — कर-निर्धारण वर्ष १९५९-६० के लिए श्री 'अ' की आय इस प्रकार है —

- (१) १,००० प्रति मास वेतन।
- (२) १,५०० रु० वार्षिक बोनस।
- (३) १,००० रु० वार्षिक मूल्य तक का किराया-मुक्त मकान।
- (४) १०% वेतन-प्रोविडेंट फंड के चदे के रूप में।
- (५) १५% चदा मालिक द्वारा (प्रोविडेंट फंड में)।
- (६) ८% वार्षिक दर से फंड की संचित राशि पर ८०० रु० ब्याज।
- (७) अपनी ३६,००० रु० की जीवन बीमा की रकम पर ४००० रु० वार्षिक-प्रीमियम की रकम।
- (८) अन्य साधनों से आय १,५०० रु०

उपर के विवरणानुसार श्री 'अ' का आयकर दायित्व क्या होगा यदि वह (अ) वैधानिक प्रोविडेंट फंड, या (ब) स्वीकृत प्रोविडेंट फंड, या (स) अस्वीकृत प्रोविडेंट फंड का सदस्य है।

उत्तर **कर-निर्धारण वर्ष १९५९-६० के लिए श्री 'अ' का कर-**
दायित्व

आवक विवरण	कुल रकम रुपये में		
	वैधानिक प्रोविडेंट फंड (अ)	स्वीकृत प्रोविडेंट फंड (ब)	अस्वीकृत प्रोविडेंट फंड (स)
१२ मास का वेतन (१०००) प्रति मास	१२,०००)	१२,०००)	१२,०००)
” ” ” बोनस	१,५००)	१,५००)	१,५००)
किराया मुक्त मकान की कीमत प्रोविडेंट फंड में १०% वेतन से ज्यादा मालिक द्वारा दिया गया चढ़ा प्रोविडेंट फंड का ६% से अधिक ब्याज	१,०००) — —	१,०००) ६००) २००)	१,०००) — —
वेतन की आय	१४,५००)	१५,३००)	१४,५००)
अन्य साधनों से आय	१,५००)	१,५००)	१,५००)
कुल आय	१६,०००)	१६,८००)	१६,०००)
कर मुक्त आय			
१ कर्मचारी का चढ़ा	१,२००)	१,२००)	—
२ जीवन बीमा प्रीमियम (वार्षिक प्रीमियम पॉलिसी के १०% भाग तक कर-मुक्त है)	२,८००)	३,०००)	३,६००)
	४,०००)	४,२००)	३,६००)

प्रश्न

प्र० १ प्रोविडेंट फंड के चढ़े एवं ब्याज तथा जीवन बीमे के प्रीमियम पर आयकर से क्या और कितनी छूट मिलती है ?

उ० देखो कड़िका ६ से १० तथा प्रश्न न० ४

प्र० २ वेतन में से कौन कौन सी कटौतियाँ दी जाती हैं।

उ० देखो कड़िका ५

प्र० ३ सक्षिप्त टिप्पणी लिखो —

(अ) प्रति फल।

(ब) वेतन के स्थान पर लाभ।

(स) स्वीकृत प्रोविडेंट फंड।

उ० (अ) देखो कड़िका ३। (ब) देखो कड़िका ४। (स) देखो कड़िका ८।

प्र० ४ श्री सुभाष चन्द्र आशा पब्लिशिंग हाऊस अहमदाबाद में मनेजर है।

उनकी गतवर्ष १९५८-५९ के लिए आय के विवरण निम्न प्रकार है —

(१) वेतन ५००) मासिक।

(२) स्वीकृत प्रोविडेंट फंड में चढ़ा — वेतनका $६\frac{१}{४}\%$ ।

(३) मालिक का चढ़ा भी इतना ही है।

(४) फंड की संचित राशि पर ब्याज २००)।

(५) दो मास के वेतन के बराबर बोनस।

(६) मकान-किराया भत्ता १००) मासिक।

(७) जीवन बीमेका प्रीमियम ५००)।

आप उनकी (१) वेतन से कुल आय, तथा (२) कर मुक्त आय, कर-निर्धारण वर्ष १९५९-६० के लिए निकालिए।

उ० (१) ८,२००) (२) ८७५)

प्र० ५ गत वर्ष समप्ति ३१-३-५९ के लिए श्री सुरेश चन्द्र, सरकारी कर्मचारी, के आय के विवरण निम्न प्रकार है।

(अ) वेतन १,०००) मासिक, यात्रा-भत्ता बिल २,०००) यात्रामे वास्तविक खर्च १,५००)।

(इ) उनका तथा सरकार का प्रोविडेंट फंड में चढ़ा — $६\frac{१}{४}\%$ फंड की संचित राशि पर ब्याज ७८०), जीवन बीमे का प्रीमियम ३०००)।

(स) वर्ष भर मकान-किराया भत्ता — वेतन का १५%

उनकी कुल आय तथा कर-मुक्त आय निकालिए।

उ० कुल आय १४,३००)।

कर-मुक्त आय. ३,५७५)=(प्रोविडेंट फंड में स्वयंका चढ़ा ७५०)+
जीवन बीमे का चढ़ा २,८२५)

प्रतिभूतियों का ब्याज : धारा ८ INTEREST ON SECURITIES

१ मुख्य बातें

- (१) इस आयके शीर्षक के अन्तर्गत केवल केन्द्रीय और राजकीय सरकारों की प्रतिभूतियों पर तथा स्थानीय अधिकारियों (local authorities) तथा कपनियों के ऋण-पत्रों (Debentures) पर प्राप्त ब्याज की आय आती है। अन्य किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियों का ब्याज इस शीर्षक के अन्तर्गत नहीं लिया जाता।
- (२) इस शीर्षक के अन्तर्गत ब्याज पर तब तक कर नहीं लगाया जाता जब तक कि उस ब्याज का हकदार उसे प्राप्त न कर ले।
- (३) प्रतिभूतियों से ब्याज किन्हीं निश्चित तिथियों पर ही प्राप्त किया जाता है। इसलिए आयकर के लिए उस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है जो कि उन तिथियों पर उन प्रतिभूतियों का मालिक है।
- (४) इस सम्बन्ध में ब्याज सहित तथा ब्याज रहित सोदो (Cum-int or cum-div and ex-int or ex-div transactions) को बिलकुल ध्यान में नहीं रखा जाता।
- (५) कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज (Interest from tax-free Govt securities) कुल आय में दर बढ़ाने के लिए ही जोड़ा जाता है अन्यथा वह आय कर से (अतिकर से नहीं) मुक्त है। इन प्रतिभूतियों के ब्याज में से उधार ली गई रकम का ब्याज तथा प्रतिभूतियों के ब्याज को वसूल करने के उपलक्ष्य में दिया गया कमीशन घटा कर ही शेष ब्याज को कुल आय में जोड़ा जाता है तथा उसी रकम पर ही छूट मिलती है। अन्य किसी भी प्रकार की कर-मुक्त प्रतिभूतियों पर कोई भी छूट नहीं दी जाती।
- (६) प्रतिभूतियों के बेचने से हुआ लाभ या नुकसान पूजीगत लाभ या नुकसान है परन्तु यदि कर-दाता का व्यवसाय ही प्रतिभूतियों को खरीदना या बेचना है तो ऐसे लाभ तथा नुकसान को उसकी कुल आय में शामिल किया जायगा।
- (७) प्रतिभूतियों के ब्याज पर निर्गम के स्थान पर ही कर काट लिया जाता है। इसलिए ब्याज की रकम को सकल (Gross-up) करके ही कुल आय में जोड़ा जाता है।

२ प्रतिभूतियों के ब्याज में से कटौतियाँ (Deductions from Interest on Securities).—

प्रतिभूतियों से कर-योग्य ब्याज का लेखा करते समय निम्नलिखित कटौतियाँ दी जाती हैं —

- (अ) प्रतिभूतियोंके ब्याज वसूल करने के उपलक्ष में बैंक या किसी भी अन्य व्यक्ति को दिया गया कमीशन ।
 (ब) प्रतिभूतियों के खरीदने के लिए यदि कोई रकम उधार ली जावे तो उस उधार की रकम पर दिया गया ब्याज ।

प्रश्न सख्या ५ —

‘ज’ के विनियोग (Investments) गतवर्ष सन् १९५८-५९ में निम्न लिखित थे —

(क) १०,०००)	३%	कर-मुक्त सरकारी ऋण ।
(ख) २०,०००)	४%	म्यूनििसिपल ऋण-पत्र ।
(ग) ३०,०००)	५%	जूट मिल कपनी के ऋण-पत्र ।
(घ) ४०,०००)	६%	एक कपनी के प्रीफेस शेयर ।

“ज” के बैंक ने ब्याज सग्रह करने के लिए २००) कमीशनके लिए । ‘ज’ को १०००) उस ऋण के ब्याज के देने पड़े जो उसने जूट कपनी के ऋण-पत्रों को खरीदने के लिए लिया था । ब्याज १ जनवरी तथा १ जुलाई को मिलता है । ‘ज’ की प्रतिभूतियों से ब्याज की आय निकालिये ।

उत्तर कर-निर्धारण वर्ष १९५९-६० के लिए प्रतिभूतियोंसे ब्याज की आय

	रु	रु
(क) कर-मुक्त सरकारी ऋण का ब्याज	३००	
(ख) म्यूनििसिपल ऋण-पत्र	८००	
(ग) जूट मिल कपनी के ऋण-पत्र	१,५००	
कटौतियाँ (Deductions).—		२,६००
(१) बैंक कमीशन	२००	
(२) ऋण पर ब्याज	१,०००	१,२००
प्रति भूतियोंके ब्याज से कर-योग्य आय		१,४००
कर-मुक्त आय —		
सरकारी ऋण का ब्याज		३००

प्रश्न

- प्र० १ भारतीय आयकर अधिनियम द्वारा प्रतिभूतियों की आयमें से कौन कौन सी कटौतियाँ मिलती हैं ?
 उ० देखो कड़िका २

जायदाद की आय : धारा ९ INCOME FROM PROPERTY

- (१) जायदाद की आय शीर्षक के अधीन कर-दाताओं को जायदाद के उचित-वार्षिक मूल्य पर कर देना पड़ता है। जायदाद के अन्तर्गत मकान, इमारत तथा वह खुली जमीन जो इमारत का ही अंग हो आते हैं। उस मकान या इमारत की आय पर कर नहीं लगता जिसमें मकान-मालिक अपना निजी व्यापार (जिसका लाभ करयोग्य हो) करता है। इस शीर्षक के अन्तर्गत आयकर देने का दायित्व केवल मकान-मालिक का ही है। किसी मकान या इमारत को ठेके पर किराया देने से जो आमदनी प्राप्त होती है वह इस धारा के नहीं बल्कि धारा १२ के अन्तर्गत कर-योग्य है।

२ उचित वार्षिक मूल्य (Bona fide Annual Value) —

- (१) इस शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य किराया वह नहीं गिना जाता जो कि वास्तविक रूपमें प्राप्त हुआ है परन्तु वह किराया जिसे 'उचित वार्षिक मूल्य' कहते हैं। उचित वार्षिक मूल्य का तात्पर्य उस एक कल्पित किराए (Notional Rent) की रकम से है जिस पर मकान या इमारत प्रतिवर्ष उचित किराए पर दी जा सके। जहाँ जायदाद पर स्थानीय कर लिया जाता है वहाँ पर यह रकम सुगमता पूर्वक निश्चित की जा सकती है। अन्य स्थानों में मकान की स्थिति, बनावट, लागत तथा उसी क्षेत्र के अन्य मकानों के किराये के आधार पर ही उचित वार्षिक मूल्य निश्चित किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि किराए की रकम उचित वार्षिक मूल्यके बराबर हो। यदि वास्तविक किराया स्थानीय सगणना (Municipal valuation) से अधिक हो तो किराये की रकम पर कर लगाया जाएगा और वही रकम "उचित वार्षिक मूल्य" समझी जायगी।"

- (२) जायदादकी आय निकालने में हमें दो प्रकार की जायदादों में भेद करना होगा —

- (अ) वह जायदाद जो किराए पर दी गई है, तथा

(ब) वह जायदाद जिसे मकान-मालिक स्वयं अपने निजी निवास के लिए पूर्ण तथा अथवा आशिक रूप में काम में ला रहा हो। दोनों प्रकार की जायदाद की आय निकालने की विधि भिन्न है।

(३) जब मकान किराये पर दिया हुआ है तथा उस पर स्थानीय प्राधिकारी (Local Authority) द्वारा स्थानीय कर (जिसमें सरविस कर भी शामिल है) लिया जाता है तो किराए की रकम में से ऐसे कर का $\frac{1}{2}$ भाग घटाया जाता है। शेष रकम उस जायदाद की उचित वार्षिक मूल्य कहलाती है। यदि किरायेदार मकान की बाबत कोई कर स्थानीय सत्ता को देता हो तो वह रकम प्राप्त किराए की रकम में जोड़ कर, बाद में स्थानीय कर की कुल रकम का आधा भाग बाद में दे दिया जाता है।

(४) यदि कर-दाता जायदाद को अपने स्वयं के रहने के लिए काम में लाता हो तो उसका वार्षिक मूल्य ठीक उसी प्रकार निर्धारित किया जाता है जैसे कि किराए पर दिए हुए मकानका। इसके पश्चात् इस निर्धारित रकम में से इसका आधा या १,८००) (जो भी कम हो) घटा दिया जाता है। इस प्रकार जो रकम शेष रहती है वह उस मकान का वार्षिक मूल्य होता है। परन्तु यदि ऐसी रकम कर-दाता की कुल आय के १०% भाग से अधिक हो तो उस मकान का वार्षिक मूल्य कर-दाता की कुल आय के १०% के बराबर ही माना जायगा।

(५) यदि दूर स्थान में नौकरी करने या व्यापार अथवा व्यवसाय करने के कारण वह अपने मकान (केवल एक) में नहीं रह सकता हो तथा वह किसी अन्यकाम में न लाया गया हो तो उस मकान की आय शून्य मानी जायगी। यदि वह गत वर्ष में किसी समय के लिए अपने ऐसे मकान में रहा हो तो उन का वार्षिक मूल्य भी उसी अनुपात में उसकी आय समझा जायगा।

३ वार्षिक मूल्य में से कटौतियाँ (Deductions from Annual Value) — किसी जायदाद की कर-योग्य आय निकालने के लिए निम्नलिखित कटौतियाँ उसके उचित वार्षिक-मूल्य में से बाद दी जाती हैं —

(१) मरम्मत खर्च — वार्षिक मूल्य का $\frac{1}{2}$ भाग मरम्मत के लिए चाहे वह मरम्मत के लिए कोई रकम खर्च करे या न करे।

- (२) बीमा चदा — जायदाद के नष्ट होने के जोखिम सम्बन्धी बीमे का दिया हुआ चदा (Insurance premium) ।
- (३) रहन की रकम पर ब्याज — यदि जायदाद रहन (Mortgage) की गई हो या उस पर अन्य पूजीगत भार (Capital Charge) हो तो उनके ब्याज की रकम ।
- (४) वार्षिक भार (Annual Charge) — यदि जायदाद पर कोई वार्षिक भार [जो पूजीगत नहीं है (not of a capital nature)] हो तो इस वार्षिक भार की रकम ।
- (५) अन्य प्रकार के ऋण का ब्याज — जायदाद को बनवाने खरीदने, मरम्मत करवाने तथा पुन निर्माण करने के लिए यदि ऋण लिया गया हो तो उस ऋण का ब्याज ।
- (६) जायदाद का भूमि किराया (Ground rent) ।
- (७) जायदाद की मालगुजारी (land revenue) जो दी गई हो ।
- (८) सग्रह व्यय (Collection charges) — जायदाद के किराए को वसूल करने में जो सग्रह व्यय हुआ हो उसकी रकम (वार्षिक मूल्यके ६% भाग तक) ।
- (९) रिक्त-स्थान छूट (Vacancy Allowance) — यदि जायदाद पूर्ण या आंशिक रूप से किसी समय के लिए खाली रहे तो उस समय के लिए जायदादके वार्षिक मूल्य का उचित अनुपात रिक्त-स्थान छूट के रूप में दे दिया जाता है ।
- (१०) डूबी हुई किराये की रकम (Unrealised Rents) यदि किराये की रकम किसी भी प्रकार वसूल नहीं की जा सके तो कुछ अवस्थाओं में वह वार्षिक मूल्य में से बाद दे दी जाती है ।

प्रश्न सख्या ६ — श्री सुभाष दो मकानों का मालिक है । एक मकान में जिसका स्थानीय मूल्यांकन १०००) है वह स्वयं रहता है । दूसरा जिसका स्थानीय मूल्यांकन रु १,६००) है वह २००) महिने से किराये पर दिया हुआ है । दोनों मकानों पर खर्चे निम्न प्रकार हैं — स्थानीय कर २६०), किराये पर दिए हुए मकान की माल गुजारी १००), उसे मरम्मत करवाने के लिए ऋण का ब्याज ३००), दोनों मकानों पर दिया हुआ अग्नि बीमे का चदा २००) । सुभाष की जायदाद से क्या आय होगी यदि सन् १९५८-५९ गतवर्ष के लिए उसकी अन्य साधनों से आय १५,०००) थी ।

उत्तर — श्री सुभाष की जायदाद से आय —

कर निर्धारण वर्ष — सन् १९५९-६० —

आयका विवरण	रकम रु	रकम रु
किराये दारसे प्राप्त किराया २००) मासिक दर से	२,४००	
बाद दिया $\frac{1}{2}$ स्थानीय कर (१६०)	८०	
किराये पर दिए मकान का वार्षिक मूल्य		२,३२०
* स्वय के रहने वाले भागका किराया मूल्य (Rental Value) (किराये पर दिये मकान के आधार पर) — $१००० \times \frac{3}{4} \times \frac{100}{100} =$	१,५००	
बाद दिया — $\frac{1}{2}$ स्थानीय कर (रु० १००)	५०	
	१,४५०	
बाद दिया — $\frac{1}{2}$ वैधानिक छूट	७२५	
स्वय के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य		७२५
दोनो मकानोका वार्षिक मूल्य		३,०४५
बाद — $\frac{1}{2}$ हिस्सा मरम्मत-खर्च	५०९	
माल गुजारी	१००	
ऋण पर व्याज	३००	
अग्नि बीमा प्रीमियम	२००	
		१,१०७
जायदाद से कर-योग्य आय		१९३८

*मकान-मालिक के स्वय के रहने वाले भाग का वार्षिक मूल्य यदि कुल आय के १०% भाग से अधिक हो तो यह निम्न लिखित प्रकार से निकाला जाता है —

$१०\% \times \frac{1}{4} \times (\text{कुल आय} - \text{जायदाद सम्बन्धी सब खर्चे जो मालूम है घटा कर})$

प्रश्न

प्र० १ मकान से आमदनी निकालनेके बारेमे भारतीय आयकर अधिनियम की धारा ९ के अन्तर्गत नियमों का पूर्ण विवरण कीजिए।

उ० देखो कड़िका १ से ३।

प्र० २ उचित वार्षिक मूल्य (Bona fide Annual Value) पर एक टिप्पणी लिखो

उ० देखो कड़िका २

प्र० ३ जायदाद की आय निकालने के लिए कौन कौनसी कटौतिया दी जाती है ?

उ० देखो कड़िका ३।

प्र० ४ निम्न विवरण से श्री 'अ' की जायदाद पे आय निकालिये —

(अ) वह दो मकानोंका मालिक है जिनकी म्यूनिसिपल गणना क्रमश ४०००) तथा ५,०००) है। दोनों मकानों का म्यूनिसिपल टैक्स ९००) है।

(ब) पहले मकान में वह स्वयं रहता है तथा दूसरा ५००) प्रतिमास की दर से किराये दिया हुआ है।

(स) अन्य साधनों से आय १,०००)

उ० १७,१३१) (प्रथम मकान का उचित वार्षिक मूल्य १,६१४) है।

व्यापार पेशा अथवा व्यवसायके लाभ धारा १०

PROFITS AND GAINS OF BUSINESS PROFESSION OR VOCATION

१ आयका यह शीर्षक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आयकर के अधिकांश रकम की प्राप्ति इसी शीर्षक से होती है। इस शीर्षक के अन्तर्गत व्यापार, पेशे तथा व्यवसाय के शुद्धकर-योग्य लाभ पर ही कर लगाया जाता है। यह शुद्ध कर-योग्य लाभ (Net taxable profit) व्यापार इत्यादि के शुद्ध लाभ (Net profit) से मर्यादा भिन्न है, क्योंकि बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं जो कि सकल लाभ में से बाद दे दिये गए हैं, लेकिन आयकर अधिनियम के अनुसार ऐसे खर्चे बाद नहीं दिये जा सकते। अतः कर-योग्य लाभ मालूम करने के लिए उन खर्चों को जानना अत्यन्त आवश्यक है जिन्हें कानून द्वारा बाद दिया तथा नहीं दिया जाता।

२ कटौतियाँ (Deductions expressly allowed)

व्यापार आदि की वास्तविक आय मालूम करने के लिए निम्न खर्चे सकल लाभ (Gross profits) में से बाद दिए जाते हैं —

- (१) जायदाद का किराया जिस जायदाद में व्यापार, पेशा आदि संचालित होते हैं उसका किराया।
- (२) मरम्मत खर्च यदि कर-दाता ने दुकान या इमारत किराए पर ली हो और मरम्मत करवाने का दायित्व लिया हो तो मरम्मत खर्च।
- (३) उधार ली गई पूँजी का ब्याज व्यापार आदि के लिए ली गई पूँजी का ब्याज।
- (४) बीमा का चर्चा यदि व्यापार आदि के काम आने वाले मकानात, मशीनरी, गोदाम आदिका बीमा कराया गया हो तो बीमे के चर्चे के रूप में दी गई रकम।
- (५) चालू मरम्मत खर्च. व्यापार आदि के काम में आने वाली इमारत, मशीनरी, सयन्त्र (Plant), फर्नीचर आदि को सुचारु रूप से कार्य योग्य रखनेके लिए उन पर किया गया मरम्मत खर्च।

- (६) घिसाई (Depreciation) इत्यादि । — देखिए पृष्ठ ४६
- (७) मूल्य सतुलन बढ़ा (Balancing Allowance) देखिये पृष्ठ ४८
- (८) मृतक या बेकार पशु व्यापार आदि में काम आने वाले जान-वरो की मृत्यु व बेकार हो जाने पर बेचने से हानि ।
- (९) स्थानीय-कर व्यापार में काम आने वाली इमारत पर माल गुजारी, स्थानीय महसूल या नगर-पालिका कर ।
- (१०) डूबते खाते (Bad debts) किन्हीं अवस्थाओं में वे व्यापारिक ऋण जो डूब गए हो या सदेह जनक हो । यदि बढ़ते खाते लिखी गई रकम किसी अगले वर्ष में वसूल हो जाय तो वह उस वर्ष की कर योग्य आय समझी जायगी ।
- (११) कर्मचारियोंको बोनस यदि कर्मचारियों को उनकी सेवाओंके बदले में वेतन के अलावा कोई रकम बोनस या कमीशन के रूपमें दी गई हो, तो वह रकम ।
- (१२) वैज्ञानिक खोज का व्यय व्यापार सम्बन्धी वैज्ञानिक खोजके लिए किया गया रेवेन्यू (Revenue) खर्च ।
- (१३) वैज्ञानिक खोज इत्यादि के लिए दिया गया चढ़ा किसी ऐसी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था को दिया हुआ चढ़ा जो कि उस व्यापार सम्बन्धी वैज्ञानिक खोज कर रही है तथा किसी भी स्वीकृत विश्व विद्यालय कॉलेज अथवा अन्य संस्था को उस व्यापार सम्बन्धी वैज्ञानिक सामाजिक तथा सांख्यिक खोज (Statistical research) के लिए दिया गया चढ़ा ।
- (१४) वैज्ञानिक खोज पर पूँजीगत व्यय व्यापार सम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया गया पूँजी गत खर्च (पांच वर्षों में बराबर विभाजित होकर) ।
- (१५) विविध खर्च उपरोक्त खर्चों के अतिरिक्त वे अन्य पूर्ण तथा व्यापार इत्यादि सम्बन्धी खर्च भी जो रेवेन्यू प्रकृति के हैं सकल मुनाफे में से बाद दे दिये जाते हैं । जैसे —
- (अ) माल के उत्पादन, यातायात व विवरण सम्बन्धी लागत खर्च ।
- (ब) कर-निर्धारण कराने तथा हिसाब व बही खाते जाँच कराने के लिए लेखा-निरीक्षक (Auditor) की फीस ।
- (स) कर्मचारियों का वेतन, विश्राम वृत्ति, इत्यादि

- (द) मुहुत उत्सव, दीपावली और प्रथानुसार अन्य दिवस पर भेट के अन्य खर्चे जो कि ४००) से अधिक नहीं हों।
- (ई) किसी कमचारी या नौकर द्वारा व्यापार के कार्य काल में व प्रसंग वश गबन या चोरी।
- (फ) डाइरेक्टरो की फीस।
- (ज) माल बेचने के लिए किया गया साधारण विज्ञापन खर्च इत्यादि

(३) न काटे जाने वाले व्यय (In admissible Allowances)

निम्न लिखित व्यय व्यापार इत्यादि की आमदनी मालूम करते समय नहीं घटाये जाते —

- (१) ऐसी ब्याज अथवा वेतन की रकम जो कि किसी अनिवासी को दी गई हो और जिस पर कर न काटा गया हो।
- (२) फर्म द्वारा साझी दार को दिया जाने वाला वेतन, कमीशन, ब्याज या अन्य पारितोषिक।
- (३) अस्वीकृत प्रोविडेंट फंड में कर्मचारियों के हितार्थ मालिक द्वारा दिया गया चढ़ा।
- (४) धर्मादा खर्च।
- (५) भागीदारों (Partners) अथवा मालिकों के निजी खर्च की रकम।
- (६) अप्राप्य ऋण रक्षित निधि (Bad debt Reserve fund) या अन्य किसी फंड या निधि (Reserve) में जमा की गई कोई रकम।
- (७) आयकर या अतिकर या अन्यकर (बिक्री कर (Sales-tax) को छोड़कर)।
- (८) पूजा गत व्यय तथा हानि।
- (९) किसी भी रक्षित निधि या फंड में जमा रकम पर ब्याज।
- (१०) रिश्वत दी जाने वाली रकम।
- (११) गत वर्ष का नुकसान।
- (१२) कानून द्वारा निश्चित दरों से अधिक घिसाई।
- (१३) ऋण-पत्रोंको प्रचलित करने पर तथा ऋण प्राप्त करने पर किया गया खर्च।
- (१४) नई कम्पनी द्वारा अपने हिस्से (Shares) को बेचने के लिए दिया गया अभिगोपन कमीशन (underwriting Commission)।

- (१५) हिस्सो तथा ऋण-पत्रों को बेचने के लिए दी गई दलाली ।
- (१६) कम्पनी का सस्थापन करने के समय के किए गए प्रारम्भिक खर्च (Preliminary Expenses) ।
- (१७) व्यापारी की ऐसी निजी जायदाद का वार्षिक मूल्य जो व्यापार के कार्य में आ रही हो ।
- (१८) किसी भी व्यावसायिक जायदाद को बढ़ोतरी करने, बदलने या परिवर्तन करने या सुधार करने में किया गया खर्च ।
- (१९) वे अन्य समस्त खर्च जो पूज्यगत हैं और पूर्णरूप से और पृथक् रूपसे व्यापार के लिए व्यय नहीं किए गए हो ।

४ भूतकाल में दी गई अतिरिक्त कटौतियाँ (Excess Deductions allowed) जिन्हें वापिस जोड़ा जाता है — धारा १० (२ए)

इस धारा के अन्तर्गत किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए लाभ निकालते समय यदि कोई हानि, खर्च या अन्य व्यय व्यापारी को छूट दे दिया गया हो तथा भविष्य में अन्य किसी भी गतवर्ष में वह रकम पूर्णतया अथवा आंशिक रूपमें वापस मिल गई हो तो जिस वर्ष में वह रकम प्राप्त की गई है, उसी वर्ष की आय मानी जायगी तथा कर-योग्य होगी । उदाहरणार्थ, गत वर्ष १९५५-५६ में एक व्यापारी को १,०००) डूबत ऋण (Bad debts) के बारे में छूट मिली परन्तु सन् १९५८-५९ में, उनमेंसे उसे ६००) वापस प्राप्त हो गए तो गत वर्ष १९५८-५९ के लिए ६००) की यह रकम उसकी कर-योग्य आय मानी जायगी ।

५ कुछ प्रकार के हर्जाने की रकमें अथवा अन्य भुगतानों का कर-दायित्व (Taxability of certain types of compensation moneys or other payments) — धारा १० (५ए)

निम्न लिखित व्यक्तियों द्वारा प्राप्त अथवा उन्हें देय कोई हर्जाने की रकम अथवा कोई अन्य भुगतान जो उन्हें किसी गतवर्ष में प्राप्त हो या देय हो, उनके व्यापार के लाभ के रूप में कर-योग्य है —

- (अ) भारतीय प्रमडल (Indian Company) के किसी प्रबन्धामिकर्ता (managing agent) द्वारा उसके समझौते की समाप्ति अथवा परिवर्तन के समय या बारे में ।
- (ब) भारतीय प्रमडल के किसी प्रबन्धक (manager) द्वारा उसके पद (office) की समाप्ति अथवा उसकी शर्तों के परिवर्तन के समय या बारे में ।

- (स) किसी भी व्यक्ति द्वारा जो भारत में (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) किसी भी दूसरी कंपनी का पूर्णतया प्रबन्ध कर रहा हो, उसके पद को समाप्ति अथवा उसकी शर्तों के परिवर्तन के समय या बारे में।
- (द) किसी भी व्यक्ति द्वारा (चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाय) जिसके पास किसी भी दूसरे व्यक्ति के व्यापारिक कार्यों के सम्बन्ध में भारत के लिए अभिकरण (Agency) है, उसके अभिकरण की समाप्ति अथवा उसके शर्तों के परिवर्तन के समय या बारे में।

उपरोक्त हर्जाने अथवा भुगतान की रकमों पर, यदि कर-दाता चाहे, तो हर्जाने इत्यादि मिलने वाले वर्ष के पिछले तीन वर्षों की आय पर लगने वाली आयकर तथा अतिरिक्त की औसत दरों पर उस गत वर्ष में कर लगाया जा सकता है जिस वर्ष में कि उसे हर्जाने इत्यादि की रकम मिली हो।

नोट — साधित प्रश्नों के लिए देखिए अध्याय ११

६ घिसाई (Depreciation) —

धारा १०(२) (vi) (viए) (viबी) और (vii)

व्यापार व्यवसाय या वृत्ति के निरन्तर काम आने से स्थायी सम्पत्ति जैसे भवन, फर्नीचर, सयंत्र, (Plant) मशीनरी इत्यादि के मूल्यकी कमी को घिसाई कहते हैं। घिसाई की छूट केवल मालिक को ही निश्चित दरों के अनुसार ही जाती है। विभिन्न प्रकार की घिसाई की छूटों तथा पदों का वर्णन नीचे दिया जाता है।

- (१) साधारण घिसाई छूट (Normal Depreciation) साधारण घिसाई छूट स्थायी सम्पत्ति के लिखित मूल्य पर निश्चित दरों के अनुसार दी जाती है।
- (२) अतिरिक्त चलने का भत्ता (Extra Shift Allowance) जितने दिन दुगुनी अथवा उससे अधिक पर्याय (Shift) तक सयंत्र या मशीन को काम में लाया जाता है उतने दिनों के लिए साधारण घिसाई का ५०% अतिरिक्त पर्याय भत्ता मिलता है। इस भत्ते को मालूम करने के लिए साल में ३०० दिन माने जाते हैं।
- (३) अतिरिक्त घिसाई (Additional Depreciation) ३१-३-१९४८ के बाद जो नई इमारत या नई मशीनरी या नया सयंत्र व्यापार आदिके काम में लिया जावे तो उसके लिखित मूल्य पर लगाये जाने वाले वर्ष के बाद ५ कर-निर्धारण वर्षों तक साधारण घिसाई के बराबर अतिरिक्त घिसाई भत्ता दिया जाता है। यह कटौती कर-निर्धारण वर्ष १९५८-५९ तक ही मिल सकती है।

(४) प्रारम्भिक घिसाई (Initial Depreciation)

नई इमारत मशीनरी तथा सयत्र (जिन्हे विकास छूट नहीं मिली है) पर प्रथम वर्ष के लिए प्रारम्भिक घिसाई दी जाती है जो कि पूरी साल के लिए तथा पूरी दरो के अनुसार होती है। इसे लिखित मूल्य मालूम करने के लिए नहीं घटाया जाता। परन्तु यदि सम्पत्ति बेची जाय या रद्द हो जाय या नष्ट हो जाय तो वास्तविक नुकसान या लाभ को मालूम करने के लिए यह प्रारम्भिक घिसाई अवश्य ध्यान में रखी जाती है तथा उसको घटाकर ही सन्तुलन छूट (Balancing Allowance) मालूम की जाती है। १-४-१९५६ से यह घिसाई बिल्कुल बन्द कर दी गई है। इसके पहले १-४-१९४६ से यह साधारणतः नये मकान पर १५% तथा नई मशीनरी या सयत्र पर २०% दी जाती थी।

(५) विकास छूट (Development Rebate) धारा १०(२)(vi)

यदि ३१-३-१९५४ के पश्चात् कोई कर-दाता पूर्ण रूप से केवल अपने व्यापारिक कार्यों के लिए ही कोई नई मशीनरी या सयत्र लगावे अथवा किसी नए जहाज का जलावतारण करे (launch) तो ऐसी मशीनरी, सयत्र अथवा जहाज पर प्रथमवर्ष में उसकी लागत मूल्य के २५% के बराबर विकास छूट दी जाती है। यदि नए जहाज का जलावतरण ३१-१२-१९५७ के बाद किया गया हो तो उस पर ४०% विकास छूट दी जायगी। यह प्रबन्ध भारत में औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने के लिये है।

इस सम्बन्ध में निम्न बातें याद रखना आवश्यक है —

- (1) जिन मशीनरी या सयत्र अथवा जहाज पर विकास छूट मिलती है उस पर प्रारम्भिक घिसाई नहीं मिलती।
- (ii) विकास छूट घिसाई नहीं है, इसलिए न तो यह लिखित मूल्य मालूम करने के लिए घटाई जाती है और न ही यह छूट मशीनरी इत्यादि को बेचने या रद्द करने से हुए लाभ या हानि का पता लगाने के लिए प्रयोग की जाती है।
- (iii) यह केवल व्यापार के लिए ही दी जाती है, व्यवसाय अथवा वृत्ति के लिए नहीं।

(६) लिखित मूल्य (Written down Value)

घिसाई सम्पत्ति के लिखित मूल्य पर निकाली जाती है। किसी सम्पत्ति के लिखित मूल्य का अर्थ है —

- (अ) यदि संपत्ति को गतवर्ष में खरीदा गया हो तो उसकी दी गई वास्तविक कीमत से, तथा
- (ब) यदि संपत्ति गतवर्ष से पहले खरीदी गई हो तो उसकी वास्तविक लागत में से कर-दाता को मिली हुई घिसाई की रकम को घटाने के बाद में जो रकम बचती हो, उससे।

(७) सतुलनीय छूट (Balancing Allowance)

यदि व्यापार के काम में आने वाली मशीनरी सयंत्र या इमारत (फर्नीचर नहीं) को बेच दिया जाए या रद्द कर दिया जाए या गिरा दिया जाए या नष्ट हो जाए तो इसके लिखित मूल्य में से बिक्री मूल्य या शेष मूल्य (Scrap Value) को कम करने के उपरान्त जो नुकसान होता है वह सतुलनीय छूट के रूप में बाद दे दिया जाता है। परन्तु यदि बिक्री मूल्य लिखित मूल्य से अधिक हो तो ऐसी सतुलनीय वृद्धि (Balancing Charge) संपत्ति के वास्तविक लागत की सीमा तक तो कर-योग्य लाभ समझा जाता है। परन्तु लागत के ऊपर का लाभ पूंजीगत लाभ (Capital Gains) समझा जावेगा।

(८) अशोधित घिसाई (Unabsorbed Depreciation)

यदि किसी व्यापार में लाभ न होने के कारण घिसाई की छूट न मिल सके या थोड़ा लाभ होने के कारण घिसाई का कुछ भाग बाकी रह जाए तो ऐसी घिसाई की शेष रकम को अशोधित घिसाई कहते हैं। अशोधित घिसाई आगामी वर्षों के लाभ में से बिना किसी प्रतिबन्ध के शोधित की जा सकती है। अशोधित घिसाई को संपत्ति का लिखित मूल्य मालूम करने के लिए बाद दिया जाता है क्योंकि यह घिसाई वास्तव में स्वीकृत की हुई घिसाई ही है।

(९) घिसाई के सम्बन्ध में ज्ञातव्य बातें

- (अ) साधारण घिसाई छूट केवल इमारत, मशीनरी सयंत्र तथा फर्नीचर पर ही दी जाती है। आयकर नियम १९२२ के नियम ८ के अनुसार कुछ साधारण घिसाई की दरें नीचे दी जाती हैं —

(१) इमारत	प्रथम श्रेणी की इमारत	२५%
	द्वितीय श्रेणी की इमारत	५%
	तृतीय श्रेणी की इमारत	७५%

यदि इमारत फेक्टरी के काम में आती है तो ऊपर लिखी दरों की दुगुनी दरें काम में ली जाती हैं।

(२) फर्नीचर तथा फिटिंग . साधारण दर	६%
होटलो के लिए	९%

(३) मशीनरी तथा सयत्र—

साधारण दर	७%
काँफी, जूट, जूते, शक्कर, चावल की फेक्ट्रीयो	
तथा आटे की चक्कियो के लिए	९%
सीमेट, पेपर, लोहा व स्पात फेक्ट्रीयो के लिए	१०%
कार व साइकल	२०%
मोटर लॉरी, टैक्सी तथा ट्रक्स	२५%

(ब) अतिरिक्त घिसाई केवल नई मशीनो, सयत्र तथा इमारतो (फर्नीचर नहीं) पर ही दी जाती है।

(स) अतिरिक्त पर्याय छूट केवल मशीनरी तथा सयत्र पर ही दी जाती है।

(द) प्रारम्भिक घिसाई केवल नए सयत्र, मशीनरी, तथा इमारतो पर ३१-३-५६ तक ही दी जाती है।

(ई) विकास छूट पूर्णतया केवल व्यापार केही लिए काम में आने वाले नये सयत्र, मशीनरी तथा जहाज पर दी जाती है।

प्रश्न सख्या ७ — गतवर्ष १९५७-५८ के लिए एक व्यापारी का घिसाई सम्बन्धी विवरण निम्न लिखित है —

फेक्ट्रीकी इमारत - प्रथम श्रेणी (घिसाई दर ५%)

	रु०	रु०
१-४-५७ को लिखित मूल्य	२५०००	
१-४-५७ को नई खरीद	१०,०००	
		३५,०००

मशीनरी (घिसाई दर १०%)

१-४-५७ को लिखित मूल्य	५०,०००	
१-१०-५७ को नई खरीद	१२,०००	
		६२,०००

पुरानी मशीनरी सालमे १५० दिन दो पर्याय (Shifts) चली।

फर्नीचर घिसाई दर ६%

१-४-५७ को लिखित मूल्य	३,०००	
१-१-५८ को नई खरीद	१,०००	
		४,०००

उसको कर-निर्धारण वर्ष १९५८-५९ के लिए घिसाई तथा विकास छूट की क्या रकम मिलेगी तथा १-४-५८ को विभिन्न सम्पत्तियों का लिखित मूल्य क्या होगा ?

उत्तर

कर-निर्धारण वर्ष १९५८-५९ के लिए घिसाई तथा विकास छूट —

फेक्ट्री की इमारत —

₹५,०००) पर ५% से साधारण घिसाई	१,७५०	
₹१०,०००) पर ५% से अतिरिक्त घिसाई	५००	२,२५०
		<hr/>

मशीनरी —

विकास छूट ₹२०००) पर २५% की दर से		₹३,०००
₹५०,०००) पर १०% से सालभरकी साधारण घिसाई	₹५,०००	
₹१२,०००) पर १०% से ६ महीने की साधारण घिसाई	₹६००	
₹१२,०००) पर अतिरिक्त घिसाई	₹६००	
अतिरिक्त पर्याय छूट $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times ५००० =$	₹१,२५०	
		<hr/>
		₹७,४५०

फर्नीचर

₹३,०००) पर ६% की दर से सालभरकी साधारण घिसाई	₹१८०	
₹१,०००) पर ६% की दर से ३ महीने की घिसाई	₹१५	
		<hr/>
		₹१९५

कुल घिसाई तथा विकास छूट	रु०	₹१२,८९५
-------------------------	-----	---------

१-४-१९५८ को लिखित मूल्य —

फेक्ट्री की इमारत	१-४-१९५७ की लिखित मूल्य अथवा लागत	घिसाई	१-४-१९५८ को लिखित मूल्य
फेक्ट्री की इमारत	₹३५,०००)	₹२,२५०)	₹३२,७५०)
मशीनरी	₹६२,०००)	₹७,४५०)	₹५४,५५०)
फर्नीचर	₹४,०००)	₹१९५)	₹३,८०५)

प्रश्न सख्या ८ —

गत वर्ष १९५८-५९ के लिए एक व्यक्ति के घिसाई सम्बन्धित आकड़े निम्न प्रकार हैं —

	फेक्ट्री के मकानात (घिसाई दर-५%)	मशीनरी (घिसाई दर १०%)
१-४-५८ के दिन लिखित मूल्य	१०,०००)	२०,०००)
नई खरीद - १-४-५८ के दिन	५,०००)	१०,०००)
	<hr/> १५,०००)	<hr/> ३०,०००)

कर निर्धारण वर्ष १९५९-६० के लिए उसे घिसाई तथा विकास छूट की क्या रकम मिलेगी तथा १-४-५९ के दिन लिखित मूल्य (Written-down value) क्या रहेगी ?

उत्तर

फेक्ट्रीके मकानात —

१५०००) पर ५% दर से साधारण घिसाई ७५०
१-४-५९ को लिखित मूल्य - (१५०००-७५०) = १४,२५०

मशीनरी —

३०,०००) पर १०% दरसे साधारण घिसाई ३,०००
१०,०००) पर २५% दर से विकास छूट २,५००
१-४-५९ को लिखित मूल्य (३०,०००-३,०००-२,५००)=२४,५००

सन् १९५९-६० के लिए कुल घिसाई एवं विकास छूट रु० ६,२५०

प्रश्न

प्र० १ “घिसाई” से आप क्या समझते हैं ? यह किसे, कब तथा किस प्रकार दी जाती है।

उ० देखो कड़िका ६ से ७

प्र० २ सक्षिप्त टिप्पणिया लिखो —

(अ) विकास छूट, (ब) सतुलनीय छूट, (स) अतिरिक्त पर्याय भत्ता,
(द) लिखित मूल्य, (ई) अशोधित घिसाई

उ० देखो कड़िका (अ) ६ (५), (ब) ६ (७), (स) ६ (३),
(द) ६ (६), (ई) ६ (९)

प्र० ३ एक व्यापारी को उसके कर देय लाभ निकालने के लिए कौन से खर्चें मजूर किये जाते हैं तथा कौनसे नामजूर।

उ० देखो कड़िका २ से ३

प्र० ४ श्री शरदचन्द्र के निम्न लाभ हानि खाते से कर-निर्धारण वर्ष १९५९-६० के लिए उनकी व्यापार से कर योग्य आय निकालिए —

	रु०		रु०
दफ्तर खर्च	५,७२०	सकल लाभ	२७,६३५
मिश्रित खर्च	२,६४०	सरकारी प्रतिभूतियोंका	
पूजी पर ब्याज	१,५८०	ब्याज	१,६६०
अप्राप्य ऋण रक्षित निधि	८३५	कमीशन	३६५
ऑडिट-फीस	३००	डूबे खातेकी वसूली	६४०
किराया	१,२५५	प्रतिभूतियोंके बेचने पर लाभ	७५०
इनकम-टैक्स	१,७६०	मिश्र आय	३५०
घर्मादा	४८५		
कानूनी खर्च	३७०		
कर्मचारी को दिया हुआ हर्जना	१,५००		
इमारत खर्च	१,५००		
लाभ	१२,०००		
	<hr/>		<hr/>
	३१,२००		३१,२००
	<hr/>		<hr/>

कर-योग्य आयके सम्बन्ध में कुछ और विवरण निम्न प्रकार का है —

- (अ) किराये की रकम में ६००) की ऐसी रकम है जो उस मकान के बारेमें है जिसमें वह स्वयं रहता है।
- (ब) वेतन-खर्च में स्वीकृत प्रोविडेंट फंड में मालिक द्वारा चढ़े की ३२०) की रकम भी शामिल है।
- (स) मिश्रित खर्च में ३५०) की रकम फर्नीचर के बारे में है।
- (द) कानून द्वारा प्राप्य घिसाई की रकम १,४७५) है।

उ० रु० १५,४२५

अन्य साधनो से आय

INCOME FROM OTHER SOURCES धारा १२

१ इस शीर्षक के अन्तर्गत कर-दाता को उन सब प्रकारकी आय व लाभ पर कर देना पड़ता है जो उसे अन्य पांच आय के शीर्षको के अलावा होती है। जैसे, विदेशी सरकारसे प्राप्त वेतन या पेशन, कपनी के डाइरेक्टरोंकी फीस, किसी विशेषाधिकार शुल्क (Royalty) के रूप में प्राप्त आय, भूमि से प्राप्त किराया लाभांश इत्यादि।

२ कटौतियाँ (Deductions) — अन्य साधनो से कर-योग्य आय मालूम करने के लिए उन समस्त खर्चों को बाद दिया जाता है जो उस विशेष आय अथवा लाभ को उत्पन्न करने के लिए व्यय किये गए हैं तथा जो पूजीगत व्यय नहीं है। लाभांश को वसूल करने के लिए बैंक या अन्य किसी व्यक्ति को दिया गया कमीशन (उचित रकम तक) बाद दिया जाता है। यदि कर-दाता ने अन्य साधनो में शारीरिक अथवा मानसिक परिश्रम करके आय प्राप्त की है तो उस पर अतिरिक्त वृद्धि कर (Additional Surcharge) नहीं लगता।

३ लाभांश (Dividends) — अन्य साधनो की आय में लाभांश भी सम्मिलित है—धारा १२ (१ए)। कपनी द्वारा अपने नफों में से साधारण रूपमें दिए गए लाभांशों के अलावा भी कुछ अन्य रकमें लाभांश में गिन ली जाती हैं — धारा २ (६ ए)। कपनी को लाभांश देने से पहले अपनी समस्त आय पर एक ही दर से आयकर देना पड़ता है। परन्तु आयकर अधि नियमके अनुसार जो भी आयकर उन लाभांशों के बाबत एक कपनी देती है वह अशधारियों (Shareholders) के लिये दिया हुआ समझा जाता है — धारा ४९ बी।

४ लाभांशोंका सकल करना (Grossing up of Dividends)
धारा १६ (२)

अशधारी के लाभांश की वास्तविक आय मालूम करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त किए हुए लाभांश में आयकर की वह रकम ओर जोड़ी जाती है जो कि कम्पनी ने आयकर विभाग को दी है। परन्तु किस वर्ष की दर से? लाभांश की रकम को सकल (Gross) उस समय की दर से किया जाता है जिस समय लाभांश की रकम दी गई है या जमाकी की गई है या बाटी गई है या ऐसा होना माना गया है। लाभांश की रकम को उस आय कर की अनुपात से बढ़ाया जाता है जो कि कम्पनी को कुल आय पर उस आर्थिक वर्ष की

दर से लागू होती है जिस वर्ष में कि अश धारी को लाभाश दिया गया है इत्यादि। एक विदेशी कम्पनी से प्राप्त हुए लाभाशों को सकल नहीं किया जाता है। यदि कपनी की आय कर-मुक्त साधनों से प्राप्त है तथा कपनी को किन्हीं कारणों से इस आय पर कुछ भी कर नहीं देना पड़ा है तो लाभाशों को सकल नहीं जायगा परन्तु अशधारी के हाथों में ऐसी आय से प्राप्त लाभाश की रकम पूर्ण-तया कर योग्य अवश्य रहेगी।

५ सकल लाभाश निकालने का सूत्र (Formula for grossing-up of Dividends) —

$$\text{सकल लाभाश} = \text{नेट लाभाश} \times \frac{1}{(1 - (\text{दर} \times \%))}$$

जब कि दर से अर्थ है कपनी पर लागू उस वर्ष की दर से अर्थात् १९५९-६० के लिए ३०% + १५% सर चाज अर्थात् ३१५%

% से अर्थ कपनी के लाभ के उस प्रतिशत से है जिस पर कर लगा है।

जहां कपनी की १००% आय पर लगा है, वहां साधारणसूत्र हुआ

$$\text{सकल लाभाश} = \text{नेट लाभाश} \times \frac{1}{\frac{(1 - 315)}{100}}$$

$$\text{सकल लाभाश} = \text{नेट लाभाश} \times \frac{1}{\frac{685}{1000}}$$

$$\text{सकल लाभाश} = \text{नेट लाभाश} \times \frac{200}{137}$$

उदाहरणार्थ किसी व्यक्ति ने एक कपनी से १०० नेट लाभाश प्राप्त किया, तो उसका सकल लाभाश जो कि उस व्यक्ति की आयमें जोड़ा जायगा वह निम्न होगा —

$$100 \times \frac{200}{137} = 146 \text{ रु०}$$

६ लेखकों की पुस्तकोंके अधिकार-शुल्क की आय (Income of Authors from royalty on books) —

— धारा १२ ए ए

यदि किसी पुस्तक को संपूर्ण करनेमें किसी लेखक को १२ महिने से अधिक लेकिन २४ महिने से कम समय लगे तो लेखक द्वारा माग करने पर उसके अधिकार शुल्क की आय (Royalty) के ५०% हिस्से को एक वर्ष में तथा दूसरे ५०% हिस्से को दूसरे वर्ष में उसकी आयमें सम्मिलित करके कर लगाया जायगा। यदि पुस्तक को संपूर्ण होने में २४ महिने से अधिक लगे तो उसकी आमदनी को तीन वर्षों में बराबर विभाजित करके उसपर कर लगाया जाता है।

७ हिसाब पद्धति (System of Accounting) — धारा १३

व्यापार, वृत्ति व व्यवसाय के लाभ तथा अन्य श्रोतों की आय पर कर की गणना कर दाता की बहियों के अनुसार की जाती है। बही खातों की हिसाब पद्धति नियमित रूपसे प्रयोग में लानी चाहिए। कर दाता द्वारा बही-खाते नहीं रखने पर या हिसाब की एक ही पद्धति को लगातार वा नियमित रूप से प्रयोग में नहीं लाने पर या हिसाबी पद्धति ऐसी हो जिसके द्वारा इनकम-टैक्स अफसर की सम्मतिमें लाभ या आमदनी ठीक प्रकार से मालूम न हो सके तो वह अपने निर्धारित रीति या आधार के अनुसार लाभ या आय की गणना करेगा।

बही खाते कौन सी पद्धति से रखने चाहिए, इसका स्पष्टीकरण या उल्लेख आयकर कानून की किसी भी धारा में नहीं किया गया है। हमारे देश में साधारणतः तीन प्रकार की हिसाब पद्धतियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं —

(१) रोकड़ पद्धति (Cash System) — इसमें केवल नकदी खर्च व आमदनी का हिसाब रखा जाता है। डाक्टरों, मुनीमों, वकीलों क्लबों तथा विद्यालयों के लिए यह पद्धति सुगमता से प्रयोग में लाई जा सकती है।

(२) महाजनी पद्धति (Mercantile System) — इस पद्धति के अनुसार वर्ष भरके तमाम रोकड़ तथा उधार दोनों प्रकार के लेनदेनोका हिसाब रखा जाता है। इस पद्धतिके अनुसार व्यापार का असली हानि लाभ मालूम किया जा सकता है।

(३) मिश्रित पद्धति (Mixed System) — कुछ लेन देन रोकड़ रीति से और कुछ लेन देन महाजनी रीति के अनुसार खातों में लिखे जाते हैं उसे मिश्रित पद्धति कहते हैं।

प्रश्न

प्र० १ सक्षिप्त टिप्पणिया लिखिए —

- (१) लाभाशो को सकल करना ।
- (२) रोकड तथा महाजनी पद्धति ।

- उ० (१) देखो कडिका ४ से ५
- (२) देखो कडिका ७

- प्र० २ कर-निर्धारण वर्ष १९५९-६० के लिए निम्न लाभाशो को सकल कीरि
- (अ) ७।१% *१०० प्रिफरेस शेयर — प्रति शेयर की रकम १००
 - (ब) १०% लाभाश एक सूती-वस्त्र मील के १,०००) के शेयरो प
 - (स) एक इजीनियरिंग कपनी (जिसके ८०% लाभ कर-योग्य है के १००० शेयरो पर ५) प्रति शेयर ।
 - (द) (अ) रु० ७५० (ब) रु० १४६ (स) फु० ६,६८३,

पूँजीगत लाभ : धारा १२ बी

CAPITAL GRAINS

१ वित्त अधिनियम (नवम्बर) १९५६ द्वारा कुछ परिवर्तनों के साथ पूँजीगत लाभ पर कर लगाने की योजना को पुनः प्रारम्भ किया है। पहले यह कर १-४-४६ से ३१-३-१९४८ की अवधि में होने वाले पूँजीगत लाभ पर लगता था। अब इस धारा के अन्तर्गत ३१-३-१९५६ के पश्चात् किसी स्थायी परिसम्पत् (Capital Asset) के विक्रय (sale), विनिमय (exchange), अवत्याग (relinquishment) अथवा हस्तान्तरण (transfer) से होने वाले लाभों पर कर लगाया जाता है। ऐसे लाभ उसीगत वर्ष की आय गिने जाएँगे जिस वर्ष में विक्रय इत्यादि हुए हैं।

२ “स्थायी परिसम्पत्” का अर्थ (Meaning of “Capital Asset”) — धारा २ (४ए)

‘स्थायी परिसम्पत्’ के अन्तर्गत हर प्रकार की सम्पत्ति आती है, चाहे वह कर-दाता के व्यापार के कार्य के लिए काम में लाई जाती हो, या नहीं। परन्तु इसमें निम्न प्रकार की सम्पत्ति शामिल नहीं है —

- (अ) व्यापार के काम के लिए किया हुआ स्कन्ध (stock) इत्यादि।
- (ब) निजी वस्तुएँ (जैसे, गहने, फर्नीचर इत्यादि) तथा
- (स) वह जमीन जिसकी आय कृषि-आय है।

३ छूट (Exemptions) — निम्न प्रकार के पूँजीगत लाभ पूर्ण तथा कर-मुक्त हैं —

इच्छापत्र (will) भेट अथवा दान द्वारा स्थायी परि सम्पत् को हस्तांतरण करने से उत्पन्न होनेवाले लाभ।

- ✓ (२) पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से किसी अविभक्त हिन्दू परिवार के बटवारे के समय स्थायी परिसम्पत् के वितरण (distribution of capital assets) से होने वाले लाभ।

✓ (३) एक कम्पनी द्वारा अपनी पूर्णतया अधीन (wholly owned) सहाय कम्पनी (subsidiary company) को स्थायी परिसम्पत् के हस्तान्तरण करने से होनेवाले लाभ।

- (४) अपने उस रहने के मकान, जिसमें कि कर-दाता या उसके माता-पिता दो वर्ष रहे हो के विक्रय से होने वाले लाभ यदि ऐसे पूजीगत लाभों की रकम को एक वर्ष के पहले या बादमें किसी दूसरे रहनेके मकान में लगा दिया गया हो। परन्तु यदि पूजीगत लाभ की रकम नए मकान की कीमत से अधिक हुई तो वह अधिक रकम कर-योग्य है।
- (५) यदि कर-दाता अपनी किसी इमारत को २५००० रु० से कम रकम में बेचे तथा उसकी तमाम इमारतों का उचित विपणि मूल्य (fair market value) ५०,००० से अधिक नहीं है तो ऐसे विक्रय से होने वाले पूजीगत लाभ कर-योग्य नहीं है।

४ कटौतियाँ (Deductions) -

कर-योग्य पूजीगत लाभ निकालने के लिए निम्न लिखित कटौतियाँ विक्रय के प्रतिफल की रकम में से की जाती हैं —

- (१) विक्रय इत्यादि करने के सम्बन्धमें हुआ खर्चा, तथा
- (२) कर-दाता को लगी हुई उस स्थायी परिसम्पत्ति की वास्तविक कीमत (actual cost)। इस सम्बन्धमें निम्न बातें ध्यान रखने योग्य हैं -
 - (अ) यदि कर-दाता तथा स्थायी परिसम्पत्ति के लेनेवाले व्यक्तिमें घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा इनकमटैक्स अफसर को यह विश्वास है कि विक्रय इत्यादि कर-परिहार (tax-avoidance) के उद्देश्यसे किया गया है तो उस स्थायी परिसम्पत्ति की कीमत विक्रय के समय की उचित विपणि कीमत के बराबर मान ली जायगी।
 - (ब) जहाँ किसी स्थायी परिसम्पत्ति पर कर-दाता को घिसाई मिल चुकी है वहाँ उस सम्पत्ति की वास्तविक कीमत उसकी लिखित कीमत में धारा १० (२) (vii) के अन्तर्गत समायोजन (Adjustment) होने से वृद्धि या कमी की रकम को घटाने या बढ़ाने से मालूम की जायगी।
 - (स) स्थायी परिसम्पत्ति की वास्तविक कीमत के स्थान पर कर-दाता चाहे तो १-१-१९५४ को होने वाली उसकी उचित विपणि कीमत (fair market value) को पूजीगत लाभ में से घटाने के लिए माँग कर सकता है।
 - (द) जहाँ कर-दाता को फर्म या कंपनी की समाप्ति पर, अथवा अविभक्त हिन्दू परिवार के विभाजन पर अथवा दान

इत्यादि द्वारा कोई स्थायी परिसम्पत् प्राप्त हुई हो तो १-१-५४ को होने वाले उचित विपणी मूल्य के अनुसरण करने के अलावा भी अन्य कई रियायत हैं जिनका सम्बन्ध ता १-४-१९५६ से है।

५ पूँजीगत लाभ पर कर की सगणना (Computation of Tax on Capital Gains) धारा १७ (६) तथा (७) —

(अ) कपनियाँ — पूँजीगत लाभ पर एक कपनी को अपनी दरसे (जैसे १९५९-६० के लिए ३१.५%) आय कर देना पड़ता है। सन् १९५९-६० तक पूँजीगत लाभ पर अतिरिक्त कर (Super-tax) नहीं लगता। १-४-६० से कपनियों पर भी १०% अतिरिक्त कर लागू हो जायगा।

(ब) अन्य कर-दाता — कपनियों के भौति अन्य कर दाताओं के पूँजीगत लाभपर कोई अतिकर (Super-tax) नहीं लगता। पूँजीगत लाभ तथा अन्य आय पर निम्न प्रकार से आयकर लगाया जाता है —

(1) कर-दाताकी अन्य कुल आय में पूँजीगत लाभ का $\frac{1}{3}$ भाग जोड़ कर आयकर की दर निकाली जाती है। उसी दर से सारे पूँजीगत लाभ पर आयकर लगाया जाता है। किसी भी दशा में पूँजीगत लाभ पर आयकर पूँजीगत लाभ तथा ५,००० रु० के अन्तर के $\frac{1}{3}$ से ज्यादा नहीं हो सकता।

एक विशेष बात यह है कि यदि पूँजीगत लाभ ५,०००) से ज्यादा नहीं है अथवा कुल आय (पूँजीगत लाभ मिलाकर) १०,०००) से अधिक नहीं है, तो पूँजीगत लाभ पर कुछ भी कर नहीं लगता।

(11) अन्य आय पर आयकर तथा अतिरिक्त कर कुल आय में से पूँजीगत लाभ घटाकर ही लगाया जाता है।

६ पूँजीगत हानियों का प्रतिसादन तथा अग्रनयन अथवा आगे ले जाना (Set-off and carry forward of Capital losses) — धारा २४ (२ए) तथा (२बी)

वे पूँजीगत हानियाँ जो किसी वर्ष में किसी पूँजीगत लाभ में से पूरा नहीं हो सकती हैं वे आगे ले जाकर भविष्य में अगले ८ वर्षों तक होने वाले पूँजीगत लाभ से प्रति सादन (Set-off) की जा सकती हैं। परन्तु यदि किसी गत वर्ष में पूँजीगत हानि ५,०००) से अधिक नहीं है तो वह आगे नहीं ले जाई जाती।

प्रश्न सख्या ९

श्री सतीशचन्द्र, जो एक व्यापारी है, ने १-११-१९५८ को ६१,०००) में एक मशीन बेची जिसे उसने ४०,०००) में खरीदी थी तथा जिसके बारे में १५,०००) घिसाई उसे मिल गई थी। इसके अलावा उसकी कुल आय ५०,०००) है। कर-निर्धारण वर्ष १९५९-६० के लिए बताइए उसका कर-दायित्व क्या होगा ?

उत्तर

रु०

श्री सतीशचन्द्र का मशीन बेचने पर कुल लाभ ६१,०००-२५,०००
(लिखित मूल्य)
= ३६,०००

इस में से १५,००० रु० धारा १० (२) (vii) में कर योग्य सतुलित लाभ है तथा २१,०००) धारा १२ बी में पूँजीगत लाभ है। उसकी कुल आय निम्न हुई —

अन्य कुल आय	५०,०००
धारा १० (२) (vii) के अन्तर्गत लाभ	१५,०००
	<hr/>
	६५,०००
धारा १२ बी के अन्तर्गत लाभ	२१,०००
	<hr/>
कुल आय	८६,०००
	<hr/>

वह ६५,०००) पर आयकर तथा अतिरिक्त कर ६५,०००) की ही दर से देगा। तथा २१,०००) पर ७२,०००) (६५,००० + $\frac{1}{3} \times २१,०००$ (पूँजीगत लाभ) पर लगने वाली आय कर की दर से कर देगा।

प्रश्न

प्र० १ “पूँजीगत लाभ” पर एक छोटा सा लेख लिखो।

उ० देखो कड़िका १ से ६ तक।

प्र० २ संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखो —

- (1) स्थायी परिसम्मत, और
- (ii) कर-मुक्त पूँजीगत लाभ।

- उ० (1) देखो कड़िका २, तथा
- (ii) देखो कड़िका ३।

भाग तीसरा

कर-निर्धारण एवं कर-संगणना

ASSESSMENT & COMPUTATION OF TAX

अध्याय १०

कुल आय तथा कुल विश्व आय की संगणना

COMPUTATION OF TOTAL INCOME AND TOTAL WORLD INCOME

१ पिछले अध्यायों में विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत कर योग्य आय को मालूम करने की रीति को हम समझ चुके हैं। इसके पश्चात् हमें कर-दाता की कुल आय तथा कुल विश्व आय के निकालने की विधि का भी अध्ययन करना जरूरी है। इस बारे में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है —

२ कुल आय तथा कुल विश्व आय की परिभाषा — यह अध्याय १ में विस्तृत रूप से उल्लेखित हो चुकी है।

३ कर-मुक्त आय — तीसरे अध्याय में हम ऐसी कुछ आयों के बारे में पढ़ चुके हैं जो वैसे तो कर मुक्त हैं पर कर-निकालने के लिए कुल आय में जोड़ी जाती हैं। इसलिए ऐसी आशिक कर-मुक्त आय को कुल आय तथा कुल विश्व आय निकालने के लिए जोड़ा जाता है।

४ पत्निकी आय (Income of wife) धारा १६ (३) — कर-दाता के स्त्री की निम्न लिखित आय उसकी कुल आय में जोड़ी जाती है —

(क) उस फर्म की साझेदारी से होने वाली आय जिसमें कि कर-दाता (पति) साझेदार है।

(ख) उस संपत्ति से आय जो कर-दाताने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके हक में बिना पर्याप्त प्रतिफल के या प्रथक रहने के विचार से हस्तांतरित की है।

५ नाबालिग बच्चे की आय (Income of Minor Child)
धारा १६ (३) —

कर-दाता की कुल आय में उसके नाबालिग (Minor) बच्चे की निम्न लिखित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साधनों से प्राप्त आय भी जोड़ी जाती है —

- (क) उस फर्मकी साझेदारी से होने वाली आय जिसमें कर-दाता (पिता) साझेदार है।
- (ख) उस सम्पत्ति से आय जिसे कर-दाता ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसके पक्ष में बिना उचित प्रतिफल (without adequate Consideration) के हस्तांतरित करदी है। परन्तु विवाहिता लड़की को दी गई सम्पत्ति की आमदनी उसके पिता की कुल आय में नहीं जोड़ी जाती।

६ अन्य व्यक्तियों के पक्ष में हस्तांतरण —

यदि कोई कर-दाता अपनी पत्नी या नाबालिग बच्चे के हितार्थ बिना उचित प्रतिफल के कोई सम्पत्ति किसी तीसरे व्यक्ति या सस्था के नाम हस्तांतरण कर देवे, तो उस सम्पत्ति की आय हस्तांतरण करनेवाले की ही आय मानी जाती है।

७ प्रतिभूतियोंके बनावटी क्रय-विक्रयके सौदे [Bond-washing transactions] — धारा ४४ ई

कभी कभी कुछ कर-दाता करसे बचनेके लिए ब्याज सहित प्रतिभूतियों या लाभांश सहित हिस्सों को इस गुप्त समझौते पर बेच देते हैं कि ब्याज अथवा लाभांश मिल जानेके बाद वे कुल ब्याज रहित प्रतिभूतियों या हिस्सों को वापस खरीद लेंगे। इसका फल यह होता है कर बच जाता है। ऐसे अनुचित उपायोंको रोकने के लिए इन प्रतिभूतियों का ब्याज इत्यादि उनके वास्तविक मालिक की कुल आयमें जोड़ दिया जाता है और उनके खरीद कर बेचने वाले व्यक्ति पर इस सम्बन्ध में मागी हुई यथार्थ सूचना न देने पर ५००) तक प्रतिदिन जुर्माना इनकमटैक्स अफसर कर सकता है।

८ हानियों का प्रतिसादन (Set-off of Losses) — धारा २४ (१)

यदि कर-दाता को किसी वर्ष आय के किसी शीर्षक में हानि हो जाए तो उस हानि का प्रतिसादन उसी कर-निर्धारण वर्षकी किसी अन्य शीर्षक से प्राप्त आय से कर सकता है। जहाँ करदाता अनरजिस्टर्ड फर्म के रूपमें है तो केवल उसी को घाटे की पूर्ति या प्रतिसादन करनेका अधिकार है, उसके किसी भी साझेदार को व्यक्तिगत रूप से फर्म के अपने हिस्से के घाटे की पूर्ति उसी वर्ष की अपनी आय में से करने का अधिकार नहीं है।

जहाँ कर दाता रजिस्टर्ड फर्म है, तो जो हानि उसे आय के किसी शीर्षक में हुई हो उसका प्रतिसादन उसी वर्ष के अन्य किसी शीर्षक से होनेवाली आयसे हो सकता है। वह हानि जिसका इस प्रकार प्रतिसादन नहीं हो सका हो वह साझेदारों में विभाजित की जाती है। और प्रत्येक साझेदार फर्मके हानि के अपने हिस्से का प्रतिसादन अपनी अन्य शीर्षक से हुई आय से कर सकता है।

व्यापार, व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ मालूम करने के लिए सट्टे की हानि का प्रतिसादन केवल सट्टे के लाभों से ही किया जा सकता है।

९ व्यापारिक हानियोंको आगे ले जाना (Carry-forward of Business Losses) धारा २४ (२) —

यदि व्यापार में किसी वर्ष नुकसान हो जाए और वह उस वर्ष की किसी अन्य आय से पूरी न हो सके तो नुकसान की ऐसी रकम आगे ले जाई जा सकती है और उसी या अन्य किसी व्यापार के लाभों से आगामी ८ वर्षों तक पूरी की जा सकती है।

जहाँ अशोधित घिसाई भी अस्तित्व में हो, तो व्यापारिक हानि की पूर्ति उसकी पूर्तिके पहले कर लेनी चाहिए। रजिस्टर्ड तथा अन रजिस्टर्ड फर्मों की व्यापारिक हानियों को आगे लाने के सम्बन्ध में वे ही नियम लागू होते हैं जो हानियों के प्रतिसादन के सम्बन्ध में लागू होते हैं। हानियों को आगे लाकर उनकी पूर्ति करनेका अधिकार केवल उसी व्यक्ति को है, जिसे नुकसान हुआ है। यदि किसी फर्म के सगठन में कोई परिवर्तन हुआ है अथवा व्यापार में कोई नया साझेदार आया है तो केवल उसी व्यक्ति को जिसे वास्तवमें हानि हुई है अपनी आयमें से उस हानि की पूर्ति करनेका अधिकार है। सट्टेकी पिछले वर्षों से लाई गई हानियों की रकम की पूर्ति केवल सट्टे के लाभ से ही अगले ८ वर्षों तक हो सकती है।

प्रश्न सख्या १०

एक कर-दाता ने अपने गतवर्ष १-४-५८ से ३१-३-५९ के लिए निम्न लिखित विवरण दिया है —

- (१) एक भारतीय औद्योगिक कम्पनी से ८ महिने की तनख्वाह २४,००० रु०।
- (२) उसी कपनी से चीन में की गई सेवाओं के उपलक्ष्य में ४ मास का वेतन — १६,००० रु० — (जिसे उसने चीन में ही प्राप्त किया) जिसमें से २,००० रु० प्रति मास उसने अपनी स्त्री को भेजे।
- (३) विदेशी कम्पनी से विदेशमें ही प्राप्त लाभांश ४,००० रु० (यह रकम कम्पनी ने २,००० रु० वहाँ के इनकमटैक्स के बाबत काटकर दी है)।
- (४) रजिस्टर्ड फर्म से अपने हिस्से की आय — १०,००० रु०।
- (५) अजमेर में किए गये तेल के घड़े से ६,००० रु० की गतवर्षकी हानि इस वर्ष लाई गई है तथा इस वर्ष उस व्यापार से २,००० रु० का लाभ है।

उसकी कुल आय तथा कुल विश्व आय निकालिए यदि वह (1) पक्का निवासी है तथा (II) अनिवासी है।

उत्तर -

कर-निर्धारण वर्ष १९५९-६०	(I) रु०	(II) रु०
(१) वेतन	२४,०००	२४,०००
(२) व्यापार के लाभ (१०,००० + २,०००) बाद, अजमेर के तेल के व्यापार से हानि ६,०००	६,०००	६,०००
(३) विदेशी आय जिसे भारत में भेजा गया है	८,०००	--
(४) विदेशी आय जिसे भारत में नहीं भेजा गया है चीन में नोकरी करने का वेतन ८,००० विदेशी कम्पनी के लाभांश ४,०००		
	१२,०००	
बाद, कानूनी छूट ४,५००	७,५००	
कुल आय रु०	४५,५००	३०,०००
विदेशी आय		२०,०००
कुल विश्व आय रु०		५०,०००

प्रश्न

प्र० १ हानियोंके प्रतिसादन (Set-off of Losses) तथा व्यापारिक हानियों को आगे ले जाना (carry-forward of business losses) से क्या समझते हो, विस्तार से समझाइए।

उ० देखो कड़िका ८ से ९।

प्र० २ संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखो —

(अ) प्रतिभूतियों के बनावटी क्रय-विक्रयके सौदे।

(ब) पति तथा नाबालिग बच्चों की आय।

उ० (अ) देखो कड़िका ७।

(ब) देखो कड़िका ४ से ५।

विभिन्न कर-दाताओं का कर निर्धारण

(1) व्यक्तियों का कर-निर्धारण

व्यक्ति के कर निर्धारण सम्बन्धी मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं —

(१) सर्व प्रथम यह देखना चाहिए कि व्यक्ति किस प्रकार का निवासी है, क्योंकि निवास-स्थान के विचार से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के कर निर्धारण भिन्न भिन्न होते हैं।

(२) तत्पश्चात् यह मालूम करना चाहिए कि व्यक्ति अविभक्त हिन्दू परिवार का सदस्य है या एक रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड फर्म का साझेदार है या किसी अन्य जन मंडल या कपनी का सदस्य है अथवा इनमें से सभी का या कुछ का मिश्रण है।

(३) गत अध्याय में बताए गए नियमों के अनुसार यदि उसकी पत्नी की या उसके किसी नाबालिग बच्चे की कोई आय है जो उसकी आयमें शामिल होनी चाहिए तो यह देखना जरूरी है कि वह आय उसकी कुल आय में जोड़ ली गई है।

(४) अन्त में अध्याय ४ से १० तक बताए गए तरीकों के अनुसार उसकी कुल आय तथा कुल विश्व आय (यदि व्यक्ति अनिवासी हो तो) मालूम करनी चाहिए।

प्रश्न सख्या ११

निम्न लिखित विवरण से सन् १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए श्री सुरेश, श्रीमती सुरेश तथा उनके नाबालिग बच्चों के ट्रस्टियों का कर-दायित्व निर्धारित कीजिए —

- (१) श्री सुरेश की अपने निजी व्यापार से गतवर्ष में ४,५०,००० रु० की आय है।
- (२) एक साझेदारी में श्री सुरेश तथा श्रीमती सुरेश दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। सारी पूंजी श्री सुरेश द्वारा ही लगाई गई है। गतवर्ष में उस साझेदारी द्वारा कुल आय १,०००,०० रु० है।
- (३) श्री सुरेश ने एक प्रतिसहाय व्यवस्था-विलेख (revocable deed of settlement) लिखा है जिससे ४०,००० रु० लाभांशों द्वारा आय हुई है। इस व्यवस्था द्वारा सारी आमदनी श्रीमती सुरेश को जीवन भर मिलने के लिए है।

- (४) श्री सुरेश ने एक और प्रतिसहाय्य व्यवस्था-विलेख लिखा है जिससे ३०,००० रु० लाभानो द्वारा आय हुई है। इस व्यवस्था द्वारा सारी आमदनी श्री सुरेश के तीनों नाबालिग बच्चों के जीवन भरके लिए है।

उत्तर —

श्री सुरेश का सन् १९५९-६० के लिए कर-निर्धारण —

(१) व्यापार के लाभ स्वयं का व्यापार	४,५०,०००
रजिस्टर्ड फर्म से $\frac{1}{2}$ हिस्सा	५०,०००
	<hr/>
	५,००,०००
(२) अन्य साधनों से आय	
स्त्री के हिस्से की रजिस्टर्ड फर्म से आय	५०,०००
दोनों व्यवस्थाओं (settlement) से आय	७०,०००
	<hr/>
कुल आय	रु० ६,२०,०००

श्रीमती सुरेश तथा तीनों नाबालिग बच्चों को कोई कर नहीं देना पड़ेगा।

प्रश्न सख्या १२

३१ मार्च १९५९ को समाप्ति होने वाले वर्ष के लिए श्री शरतचन्द्र की आय का विवरण निम्न लिखित है —

- (१) उसका वेतन १,००० रु० प्रति मास था। उसके यात्राभत्ते के बिल की कुल रकम २,००० रु० थी परन्तु उसका वास्तविक खर्चा केवल १,५०० रु० था।
- (२) उसने एक वैधानिक प्रोविडेंट फंड में १०% चढ़ा दिया तथा उसके मालिक ने १०% चढ़ा दिया। फंड की संचित राशि पर साल भर में १,००० रु० ब्याज प्राप्त हुआ।
- (३) वह जयपुर में स्थित दो मकानों का मालिक है। एक मकान २०० रु० प्रति मास की दर से किराए पर दिया हुआ है, दूसरा रहनेका मकान (जिसका वार्षिक मूल्य १,००० रु० है) साल भर खाली रहा क्योंकि उसकी नागपुर में बदली हो गई। इस मकान से उसे अन्य कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। दोनों मकानों पर ३०० रु० तथा १२० क्रमशः स्थानीय कर लगता है।
- (४) उसे कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों से ५०० रु० का ब्याज तथा लाभानो से ६०० रु० (सकल) की आयकी प्राप्ति ई।

(५) वह अपने ६०,००० रु० के जीवन बीमा पर ४,००० प्रति वर्ष बीमा प्रीमियम देता है।

कर-निर्धारण वर्ष १९५९-६० के लिए उसकी कुल आय तथा कर-मुक्त आय निकालिये।

उत्तर —

श्री शरत चद्र का सन् १९५९-६० के लिए कर-निर्धारण

(१) वेतन — १,००० रु० प्रति मास की दर से	रु०	
—धारा ७		१२,०००
(२) कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों का व्याज		५००
धारा ८		
(३) जायदादकी आय—धारा ९		
किराये पर दिये हुए मकान का वार्षिक	२,४००	
किराया		
बाद — स्थानीय कर	१५०	
वार्षिक मूल्य	२,२५०	
बाद — मरम्मत खर्च $\frac{१}{६}$	३७५	१,८७५
दूसरा मकान धारा ९ (२) के दूसरे प्रबन्ध		
(proviso) के अन्तर्गत मुक्त है।		
(४) अन्य साधनों से आय—धारा १२		
लाभांश	१००	
अधिक यात्रा भत्ता	५००	१२००
कुल आय रु०		१५,०७५

कर-मुक्त आय :

(१) स्वयं का प्रोविडेंट फंड में दिया हुआ चंदा	१,२००	
(२) जीवन-बीमा का प्रीमियम		
(प्रोविडेंट फंड का चंदा तथा बीमा प्रीमियम कुल मिलाकर आय के $\frac{१}{६}$ हिस्से से अधिक नहीं होना चाहिए)		२,७६९
(३) कर-मुक्त व्याज		५००
कुल रु०		४,४६९

(11) अविभक्त हिन्दू परिवारोंका कर-निर्धारण (Assessment of Hindu Undivided Families) —

१ अविभक्त हिन्दू परिवार का कर-निर्धारण एक प्रथक कर-दाता की हैसियत से होता है। हिन्दू न्याय-शास्त्र (Hindu-Law) के अनुसार सयुक्त हिन्दू परिवार तथा आयकर कानून के अनुसार अविभक्त हिन्दू परिवार में अंतर है। हिन्दू न्याय शास्त्र के अनुसार एकाकी पुरुष या केवल स्त्रियो का भी सयुक्त परिवार हो सकता है। आयकर कानूनमें बिना सहभागियो (co-parceners) के अविभाजित हिन्दू परिवार नहीं हो सकता। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अविभक्त हिन्दू परिवार की शामिलता जायदाद पर कर लगता है न कि उसके सदस्यो की निजी आय पर।

२ सन् १९५८ तथा १९५९ के वित्त अधिनियमो के अनुसार एक अविभक्त हिन्दूपरिवार को कोई कर नहीं देना पडता यदि उसकी कुल आय ६,००० रुपये की न्यूनतम सीमा से अधिक नहीं है। यह सीमा तभी लागू होती है जब कि बँटवारे के अधिकारी सदस्य कम से कम दो हो तथा उनमें से कोई भी —

- (क) १८ वर्ष से कम आयु का नहीं हो, या
- (ख) किसी दूसरे सदस्य की सतान नहीं हो, या किसी दूसरे सदस्य के साथ किसी ऐसे जीवित सदस्य (जिसे बँटवारे का अधिकार नहीं हो) की सतान नहीं हो।

३ विभाजन के पश्चात् कर-निर्धारण

धारा २५ ए

कोई भी अविभक्त हिन्दू परिवार का सदस्य आयकर अफसर के पास बँटवारे की प्रार्थना कर सकता है और उक्त अफसर नोटिस देकर बँटवारे की जाँच करवा सकता है। यदि जाँच के बाद आयकर अफसर इस बात से पूर्ण तया सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसे हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पत्ति का निश्चित तथा भौतिक (By Metes & Bounds) हिस्सो में विभाजन हो चुका है तो आयकर अफसर विभाजन की स्वीकृति की आज्ञा दे देगा। जब तक ऐसी आज्ञा नहीं दी जाय तब तक विभाजन होने पर भी वह अविभक्त हिन्दू परिवार ही समझा जाएगा। विभाजन होने के बाद भी सम्पूर्ण कर की रकम के लिए सब सदस्य मिलकर तथा अलग अलग जिम्मेदार हैं।

(111) साझेदारी तथा अन्य जन मंडल का कर-निर्धारण (Assessment of Partnership firms and other Association of persons) —

१ आयकर अधिनियम के अन्तर्गत साझेदारीफर्म दो प्रकार के होते हैं — पजीयित सार्थ-तथा अपजीयित सार्थ। दोनों का आयकर दायित्व एक दूसरे से

बिलकुल भिन्न है। पजीयित सार्थ उस सार्थ को कहते हैं जो आयकर कानून की धारा २६ ए के अन्तर्गत इनकमटैक्स अफसर द्वारा पजीयित किया गया हो। भारतीय भागिता अधिनियम १९३२ के अन्तर्गत पजियन करवाई गई सार्थ को आयकर अधिनियम में पजीयित सार्थ नहीं माना जाता है। अपजीयित सार्थ वह सार्थ है जिसका २६ ए के अन्तर्गत पजियन (Registration) नहीं हुआ है।

२ पजियन (Registration) की विधि — धारा २६ ए

इस सम्बन्ध में निम्न बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है —

(१) सार्थ के पजियन कराने के नियम आयकर अधिनियम की धारा २६ ए तथा सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू द्वारा बनाए गए आयकर नियम १९२२ के २ से ६ बी तक नियमों में पाये जाते हैं।

(२) पजियन के पूर्व एक सार्थ को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना पड़ता है —

(अ) पजियन के लिए प्रार्थना पत्र एक निश्चित फॉर्म भरकर इनकम-टैक्स अफसर को दिया जाता है। इसमें सभी भागीदारों के व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने चाहिये। यदि सार्थ का पजियन सर्व प्रथम करवाया जा रहा तो प्रार्थना पत्र सार्थ के हिसाबी वर्ष के अन्त के पहले या फर्म के बनने के ६ महीने की अवधि के पहले (जो भी समय पहले आए) भेजना चाहिए। पजियन प्रतिवर्ष पुन (Renew) कराया जाता है तथा उसके लिए प्रार्थना-पत्र प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष की ३० जून तक आयकर अफसर के पास पहुँच जाना चाहिए।

(ब) साझेदारी या भागिता की रचना भागिता सलेख (Instrument of Partnership) के अन्तर्गत होनी चाहिए।

(स) भागिता-सलेख के अन्दर प्रत्येक भागी का हिस्सा कितना और किस प्रकार है, स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए।

(द) भागिता सच्ची (Genuine) होनी चाहिए न कि आयकर से बचने के लिए एक मिथ्या सस्था।

(३) यदि प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति पर इनकमटैक्स अफसर पूर्णरूप से सन्तुष्ट हो जाय तो वह सलेख के नीचे इसके पजियन होने के तथ्य को नोट कर देता है। पजियन केवल एक वर्ष के ही लिए होता है। यदि इनकमटैक्स अफसर सन्तुष्ट नहीं है तो वह भागिता-सार्थ (Partnership firm) को पजी करने से इन्कार कर सकता है।

- (४) धारा २३ (४) के अन्तर्गत एक-तरफा कर-निर्धारण होने पर भी इनकम-टैक्स अफसर सार्थ (firm) को पजी करने से इन्कार कर सकता है तथा यदि सार्थ को पजीयन दे चुका हो तो उसे रद्द कर सकता है। यही नहीं यदि सार्थ के जालसाजी का असलीरूप इनकम टैक्स अफसर को ज्ञात हो जाय तो वह पजीयन को रद्द कर सकता है।

३ भागीदारों में आय का आवन्टन (Allocation of Income amongst partners) — धारा १६ (१) (बी)

सार्थ की कर योग्य आय उसके भागीदारों में बाँटी जाती है। सार्थ की कर-योग्य आय में प्रत्येक भागीदार का हिस्सा सार्थ से प्राप्त की गई आय ही नहीं होता बल्कि वह निम्न रूप से निकाला जाता है —

- (अ) सर्वप्रथम धारा १० की व्यवस्थानुसार सार्थ का हानि लाभ-निकाला जाता है ,
- (ब) सार्थ की आय इस प्रकार निकालने के पश्चात् भागीदारों को वेतन व्याज, कमीशन अथवा अन्य प्रारिश्मिक के रूप में दी गई रकम घटा दी जाती है, तथा
- (स) अन्त में सार्थ की शेष कर-योग्य आय को भागीदारों में उनके लाभ के हिस्सों के अनुपात में बाँट दिया जाता है।

४. पजीयित सार्थ (Registered firms) —

(अ) आय-कर —

१-४-१९५६ के पहले एक पजीयित सार्थ पर उसकी कुल आय के लिए कर-निर्धारण तो होता था परन्तु सार्थ की आय पर सार्थ द्वारा कोई कर नहीं दिया जाता था। प्रत्येक भागीदार की कुल आय में सार्थ के लाभ का हिस्सा सम्मिलित होकर उसपर कर लगाया जाता था। परन्तु १-४-१९५६ से पजीयित सार्थ भी अपनी कुल आय पर कर देते हैं यदि उनकी कुल आय ४०,००० रु० से अधिक है।

भागीदारों को तो अपने अपने हिस्सों पर पूर्ववत् कर देना ही पड़ता है परन्तु उनको अपने व्यक्तिगत आयकर की दर से उस रकम पर छूट मिलती है जो कि सार्थ द्वारा दिए गए आयकर के बारे में उनके हिस्से में आती है।

उदाहरण —

एक पजीयित सार्थ मे ('अ', 'ब', 'स' तथा 'द' चार बराबर के हिस्से वाले भागी हैं तथा सन् १९५८-५९ मे जिसकी कुल आय १,००,००० रु० है। भागीदारों की कोई अन्य आय नहीं है। पहले ऐसी सार्थ कोई भी नहीं कर नहीं देती थी हालांकि प्रत्येक भागी को २५,००० रु० पर कर-देना पड़ता था। अब उसे ३,२५० रु० आय कर देना पड़ेगा। परन्तु प्रत्येक भागी को ३,२५० रु० के $\frac{1}{4}$ भाग पर (अर्थात् ८१२ ५० रु०) पर अपनी कुल आय २५,००० रु० पर लगने वाले आयकर की औसत दर से छूट मिल जायगी।

(ब) अतिरिक्त कर — पजीयित सार्थ की आय पर अतिरिक्त कर नहीं लगता। साथ के प्रत्येक भागी की अन्य आय मे सार्थ के लाभ के उसके हिस्से की रकम भी जोड़ी जाती है तथा इस प्रकार भागी द्वारा अपनी कुल आयपर अतिरिक्त कर देना पड़ता है।

(स) हानिका प्रतिसादन तथा उसका आगे ले जाना धारा २४ यदि पजीयित सार्थ के किसी व्यापार मे घाटा होता है तो पहले सार्थ की अन्य आय में से उसकी पूर्ति की जाती है और तब घाटे की शेषांश रकम भागीदारों मे उनके हिस्सों के अनुसार बाँट दी जाती है जिसे प्रत्येक भागी उसी वर्ष की अपनी अन्य आय से पूर्ण कर सकता है या उसे व्यापारिक घाटे के रूप मे प्रतिसादन के लिए आगामी ८ वर्षों तक आगे ले जा सकता है।

५ अपजीयित सार्थ (Unregistered Firms) —

(अ) आयकर — ऐसे सार्थ पर एक अविवाहित व्यक्ति की भाँति ही उसकी कुल आय की रकम पर कर लगाया जाता है। यदि इसकी कुल आय कर-योग्य न्यूनतम सीमा से कम है तो इस पर कोई आयकर नहीं लगता। यदि सार्थ पर कर लग गया हो तो भागीदारों की अन्य आय मे सार्थ से उनका हिस्सा केवल कर की दर निश्चित करने के लिए ही छोड़ा जाता है। यदि सार्थ की कुल आय कर-योग्य सीमा से अधिक है तो भागीदारों को अपनी अन्य आय के साथ सार्थ के लाभ के अपने हिस्से पर भी कर देना पड़ेगा।

(ब) अतिरिक्त कर — ऐसे सार्थ पर व्यक्ति की ही भाँति अतिरिक्त-कर लगता है और यदि फर्म पर अतिरिक्त कर लग गया हो तो फर्म के लाभ से अपने हिस्सों पर भागीदारों को अतिरिक्त-कर नहीं देना पड़ता।

(स) घाटेका प्रतिसादन तथा उसका आगे ले जाना — धारा २४
अपजीयित सार्थ प्रथम तो अपने व्यापारिक घाटे का प्रतिसादन उसी वर्ष में अपनी अन्य आय में से कर सकता है और शेष रहे घाटे की आगामी ८ वर्षों तक व्यापारिक हानि के रूप में आगे ले जा सकता है। किन्तु कोई भी भागी साथ में अपने हिस्से की हानि का प्रतिसादन अपनी अन्य आय से नहीं कर सकता।

(द) अपजीयित सार्थ को पजीयित सार्थ माना जाना (Unregistered firm assessed as registered firm) — धारा २३ (५) (बी) — इनकम-टैक्स अफसर को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि वह यह समझे कि एक अपजीयित सार्थ को पजीयित मानने से अधिक आयकर और अति-रिक्त कर मिलेगा तो वह इसके वस्तुतः पजीयित न होने पर भी इसे पजीयित सार्थ मान लेगा। ऐसी परिस्थिति में कर-निर्धारण के समय 'पजीयित सार्थ' के लिए लागू होने वाले सभी नियम तथा सिद्धान्त ऐसी पजीयित मानी गए साथ के कर-निर्धारण में भी लागू होंगे।

६ सार्थके सगठन में परिवर्तन (Change in the Constitution of firm) धारा २६

यदि किसी सार्थ के सगठन में कोई परिवर्तन हुआ है अथवा कोई सार्थ पुनः गठित हुआ है तो कर-निर्धारण के समय सार्थ जिस रूप में सगठित है उसी रूप में उस पर कर-निर्धारण किया जायगा किन्तु सार्थ का लाभ गतवर्ष में सार्थ के जो भागीदार रहे थे, उन्हीं में बाँटा जायगा। इस प्रकार प्रत्येक भागी के ऊपर कर केवल उसी रकम पर लगता है, जिसको प्राप्त करने का वह गतवर्ष में वास्तविक रूप से हकदार था। यदि किसी भागी के ऊपर लगाए हुए कर की वसूली उससे न हो सके तो वह कर-निर्धारण के समय सम्पत्ति सार्थ से वसूल किया जायगा।

यदि सार्थ के किसी ~~अधिसूक्त~~ ^{अपभ्रष्ट} (Retired) अथवा स्वर्गवासी भागी के हिस्से में सार्थ के नुकसान के हिस्से की रकम आती है तो सार्थ इस घाटे की पूर्ति बाद के किसी वर्ष में अपने लाभ से नहीं कर सकती, केवल वह भागी ही उसी गत वर्ष की अपनी अन्य आय में से इसकी पूर्ति कर सकता है।

७ सार्थ का बंद होना (Discontinuance of firm) धारा ४४

यदि किसी सार्थ का कारोबार बंद हो जाता है तो सार्थ के बन्द होने के समय वे सब व्यक्ति जो फर्म के भागीदार थे, सामूहिक रूप से तथा व्यक्ति-

गत रूप से भी कर-निर्धारण के दायित्व को वहन करते हैं। यदि सार्थ का कर-निर्धारण हो चुका हो और केवल उससे कर-वसूली न हो सकी है तो कर-भुगतान का दायित्व भी इन पर है।

८ अन्य जन मंडल का कर-निर्धारण (Assessment of other association of persons)

अन्य जन-मंडल पर आयकर तथा अतिरिक्त कर ठीक उसी प्रकार लगता है जैसे कि एक अविवाहित व्यक्ति पर। अन्य जन-मंडल की आय में प्रत्येक सदस्य के हिस्से को इसी प्रकार माना जाता है जैसे कि वह अपजीयित सार्थ से हिस्सा हो। इसके भग हो जाने पर वे ही नियम लागू होते हैं जो कि सार्थ के बद होने पर।

प्रश्नसख्या १३

अ, ब तथा स एक सार्थ में क्रमशः २ २ १ हिस्सों में भागी हैं। ३१-१२-१९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ प्राप्ति का विवरण-पत्र निम्नलिखित है —

	रु०		रु०
मिश्रित व्यापारिक खर्च	५०,०००	सकल लाभ	१,४५,०००
पूँजी पर ब्याज		लाभांश (सकल)	५,०००
श्री अ ३,०००			
श्री ब २,०००			
श्री स १,०००			
ब का वेतन	६,०००		
स को कमीशन	३,०००		
पक्का लाभ	८५,०००		
	<hr/>		<hr/>
	१,५०,०००		१,५०,०००
	<hr/>		<hr/>

सार्थ की कुल आय की गणना कीजिए तथा उसके भागीदारों में उसका आवंटन (Allocation) कीजिए।

उत्तर

कर-निर्धारण वर्ष १९५९-६०

सार्थ के कुल आय की सगणना

१ व्यापारिक लाभ	रु०
लाभ-हानि खाते के अनुसार पक्का लाभ	८५,०००
जोड़ो - पूँजी पर व्याज	६,०००
भागी का वेतन	६,०००
भागी का कमीशन	३,०००
	<hr/>
	१५,०००
	<hr/>
	१,००,०००
बाद लाभांश, जो व्यापारिक लाभ नहीं है	५,०००
	<hr/>
व्यापारिक लाभ	९५,०००
२ लाभांश (सकल)	५,०००
	<hr/>
सार्थ की कुल आय रु०	१,००,०००
	<hr/>

भागीदारों में सार्थ की आय का आवंटन

भागी	हिस्सा	पूँजी पर व्याज रु०	वेतन रु०	कमीशन रु०	शेष आय में हिस्सा रु०	कुल आय रु०
अ	$\frac{३}{४}$	३,०००			३४,०००	३७,०००
ब	$\frac{३}{४}$	२,०००	६,०००		३४,०००	४२,०००
स	$\frac{१}{४}$	१,०००		३,०००	१७,०००	२१,०००
कुल		६,०००	६,०००	३,०००	८५,०००	१,००,०००

धारा १४ (२) (एए) के अन्तर्गत निम्न आय आय-कर से मुक्त है —

सार्थ की कुल आय १,००,००० रु० पर कर $10\% \times 1,00,000 = ३,२५०$ रु०
 आयकर घटा कर सार्थ की कुल आय = १,००,००० रु० - ३,२५० रु०
 = ९६,७५० रु०

प्रत्येक भागी के हाथ में निम्न भाग कर-मुक्त है —

	सार्थ की कुल आय में हिस्सा रु०	सार्थ की कुल आय में से आयकर निकालने के बाद बची हुई रकम रु०	सार्थ के लाभ का वह भाग जो भागीदारों के हाथ में कर-मुक्त है रु०
अ	३७,०००	३५,७००	१,३००
ब	४२,०००	४०,७००	१,३००
स	२१,०००	२०,३५०	६५०
कुल	१,००,०००	९६,७५०	३,२५०

प्रश्न सख्या १४

एक सार्थ के तीन भागीदार क, ख तथा ग हैं, जिनका हिस्सा क्रमशः ४ ३ १ है। १९५८ कैलेंडर वर्ष के लिए सार्थ को निम्नलिखित रकमें घटाने के पश्चात् १६,००० रु० का पक्का नुकसान हुआ है —

		रु०
पूँजी पर ब्याज	क	३,०००
	ख	२,०००
	ग	१,०००
वेतन	ग	२,०००

क की आय साधनों से आय ५,००० रु० है जबकि ख तथा ग की और कोई आय नहीं है।

कर-निर्धारण कीजिए (1) जब सार्थ पजीयित है तथा (11) जब वह अपजीयित है।

उत्तर

भागीदारों की पूंजी पर दिए गए ब्याज तथा भागी के वेतन को १६,००० रु० में से घटाने के पश्चात् सार्थ का वास्तविक नुकसान ८,००० रु० है तथा तीनों भागीदारों का क्रमशः हिस्सा निम्न प्रकार होगा —

भागी	हिस्सा	पूंजी पर ब्याज रु०	वेतन रु०	सार्थ के घाटे में हिस्सा रु०	कुल रु०
क	$\frac{2}{3}$	३,०००	—	८,०००	हानि ५,०००
ख	$\frac{2}{3}$	२,०००	—	६,०००	हानि ४,०००
ग	$\frac{1}{3}$	१,०००	२,०००	२,०००	लाभ १,०००
कुल		६,०००	२,०००	१६,०००	८,०००

(I) जब सार्थ पजीयित है

‘क’ सार्थ से अपने हिस्से के नुकसान (५,००० रु०) का प्रतिसादन अपनी अन्य आय ५,००० रु० से कर सकता है। इस प्रकार उसे कोई कर नहीं देना पड़ेगा।

‘ख’ सार्थ से अपने हिस्से के नुकसान (४,००० रु०) को आगे ८ वर्षों तक व्यापारिक लाभों से प्रतिसादन करने के लिए ले जा सकता है।

‘ग’ की आय केवल १,००० रु० है, इसलिए उसे कोई कर नहीं देना पड़ेगा।

(II) जब सार्थ अपजीयित है

सार्थ अपने नुकसान (८,००० रु०) को अपनी भविष्य की आमदनी से प्रतिसादन करने के लिए अगले ८ वर्षों तक आगे ले जा सकता है।

‘क’ सार्थ के अपने हिस्से के नुकसान का प्रतिसादन अपनी अन्य आय से नहीं कर सकता। उसे अपनी अन्य आय ५,००० रु० पर कर देना पड़ेगा।

‘ख’ सार्थ के नुकसान को आगे नहीं ले जा सकता।

‘ग’ को कोई कर नहीं देना पड़ेगा।

ग्रेशन सख्या १५

अ तथा ब एक पजीयित साथ मे बराबर हिस्से वाले भागी है । गत वर्ष १९५८-५९ मे साथ का नफा-नुकसान खाता निम्न प्रकार है —

	रु०		रु०
वेतन तथा बोनस	७,०००	सकल लाभ	६५,०००
अन्य व्यापारी खर्च	१०,०००	अन्य आय	५,०००
सेल-टैक्स	५,०००		
किराया	३,०००		
घिसाई निधि	२,०००		
डूबत ऋण की रकम	१,०००		
डूबत ऋण-निधि	२,०००		
विज्ञापन खर्च	३,०००		
चदा तथा धर्मादा	१,०००		
मोटरकार की बिक्री पर हानि	३,०००		
पूजी पर ब्याज अ	३,०००		
ब	३,०००		
भागीदारो का वेतन अ	३,०००		
ब	२,०००		
कमीशन	१,०००		
पक्का लाभ	२२,०००		
	<hr/>		<hr/>
	७०,०००		७०,०००
	<hr/>		<hr/>

(१) मिश्रित व्यापारिक खर्च मे सरकारी जमाने के दंड की २०० की रकम शामिल है।

(२) विज्ञापन खर्च मे १,००० रु० पूजिगत खर्च की रकम है।

(३) चदे तथा धर्मादि मे निम्न रकम शामिल है —

- (अ) २०० रु० एक व्यापारिक सघ का चदा,
 (ब) ६०० रु० शार्थीयोके लिए टीन का छपर, तथा
 (स) २०० रु० एक स्कूल को दान।

(४) मोटर कार पूर्णतया उसके निजी कार्य मे आती है।

५) घिसाई की मिलने वाली रकम १,००० रु० है।

अ — प्रतिभूतियों का ब्याज (सकल) — ५,००० रु०, जायदाद की आय — १,००० रु०, लाभांश (सकल) — ३,००० रु०, विदेशी आय जो भारत में नहीं लाई गई है — ३,००० रु०

ब — प्रतिभूतियों का ब्याज (सकल) — ७,००० रु०, लाभांश (सकल) — १,००० रु०, जायदाद की आय — ३,००० रु०, भारत में लाई गई विदेशी आय — १,००० रु०

यह मान कर कि अ तथा ब भारत के पक्के निवासी हैं, उनकी कुल आय की सगणना कीजिए।

उत्तर

कर-निर्धारण वर्ष १९५९-६०

	रु०	रु०
लाभ-हानि खाते के अनुसार पक्का लाभ		२२,०००
जोड़ो-१ घिसाई निधि	२,०००	
२ डूबत-ऋण निधि	२,०००	
३ पूँजी पर ब्याज	६,०००	
४ भागी का वेतन	४,०००	
५ भागी को कमीशन	१,०००	
६ कानूनी दंड	२००	
७ पूँजीगत विज्ञापन खर्चा	१,०००	
८ चंदा तथा धर्मादा	८००	
९ मोटरकार के बेचने का नुकसान	३,०००	
		२०,०००
		४२,०००
बाद-घिसाई		१,०००
		४१,०००

सार्थ की कुल आय

४१,०००

सार्थ का आय-कर दायित्व

पहले ४०,००० रु० पर कुछ नहीं
आगे १,००० रु० पर ५ प्रतिशत से ५० रु०
प्रत्येक भागी को २५ रु० पर आयकर से छूट मिलेगी।

सार्थ की कुल आय का भागीदारों में आवन्तन —

	अ	ब
	रु०	रु०
पूँजी पर ब्याज	३,०००	३,०००
वेतन	२,०००	२,०००
कमीशन	—	१,०००
शेष आय	१५,०००	१५,०००
	<hr/>	<hr/>
	२०,०००	२१,०००
	<hr/>	<hr/>

अ तथा ब का सन् १९५६-६० के लिए कर-निर्धारण —

	अ	ब
	रु०	रु०
१ प्रतिभक्तियों पर ब्याज (सकल)	५,०००	७,०००
२ जायदाद की आय	१,०००	३,०००
३ व्यापारिक लाभ	२०,०००	२१,०००
४ लाभांश	३,०००	१,०००
भारत में लाई गई विदेशी आय	—	१,०००
भारत में नहीं लाई गई विदेशी आय (४,५००) <small>का हि</small> से अधिक)	—	—
	<hr/>	<hr/>
कुल आय	२९,०००	३३,०००
	<hr/>	<hr/>

प्रश्न सख्या १६

एक व्यापारिक सार्थ में अ, ब तथा स तीन भागीदार थे जिनके हिस्से क्रमश २ २ १ थे। आठ महीने के पश्चात् स ने भागिता सार्थ को छोड़ दिया तथा उसकी जगह प को सार्थ में ले लिया गया तथा फिर से उनके हिस्सोंको क्रमश ६ ५ ५ रखा गया।

गत वर्ष १-७-५७ से ३०-६-५८ के लिए उनका लाभ ४८,००० रु० था ।

लाभ निकालने में निम्न खर्च भी बाद किए गए हैं —

- (१) ४,००० रु० श्री अ को ब्याज
- (२) ६,००० रु० श्री ब को वेतन
- (३) ३,००० रु० श्री स को दुकान किराया
- (४) १,५०० रु० श्री प को कमीशन
- (५) २,००० रु० धर्मादा (धारा १५ बी के अन्तर्गत)

सार्थ ३०,००० रु० घिसाई भत्ता लेने की हकदार है ।

सार्थ की कुल आय निकालिए तथा उसका भागीदारों में आवंटन कीजिए ।

उत्तर

		रु०
लाभ-हानि खाते के अनुसार लाभ		४८,०००
जोड़ो १ अ को दिया हुआ ब्याज	४,०००	
२ ब को दिया हुआ वेतन	६,०००	
३ प को दिया हुआ कमीशन	१,५००	
४ धर्मादा	२,०००	
		<hr/>
		१३,५००
		<hr/>
		६१,५००
बाद घिसाई		३०,०००
		<hr/>
		कुल आय रु० ३१,५००
		<hr/>

धारा (१६) (१) (बी) के अन्तर्गत सार्थ की आय का भागीदारों में आवंटन

	अ रु०	ब रु०	स रु०	प रु०
ब्याज	४,०००	—	—	—
वेतन	—	६,०००	—	—
कमीशन	—	—	—	१,५००
शेष आय (८ महिने तक)	६,६६७	३,३३४	३,३३३	—
शेष आय (४ महिने तक)	२,५००	२,०८३	—	२,०८३

कुल १३,१६७ ११,४१७ ३,३३३ ३,५८३

धारा १५ बी के अन्तर्गत वार्षिक सस्थाओंको दिया हुआ कर-मुक्त चदा

	अ	ब	स	प
	रु०	रु०	रु०	रु०
८ महिने तक (१,३३३)	६६७	३३३	३३३	—
४ महिने तक (६६७)	२५०	२०८	—	२०९
कुल	९१७	५४१	३३३	२०९

(IV) कपनी, समवाय अथवा प्रमडलो का कर-निर्धारण (Assessment of Companies)

१ कपनी को परिभाषा धारा २ (५ ए)

एक कम्पनी से अर्थ है उस कम्पनी से —

- (1) जो एक भारतीय कम्पनी है, अथवा
- (II) जो एक ऐसी सस्था है (चाहे वह निगमित (Incorporated) हो या नही तथा (चाहे वह भारतीय हो या नही) जो कि सन् १९४७-४८ निर्धारण-वर्ष के लिए निर्धारित की गई थी या करने योग्य थी अथवा जिसे सेन्ट्रल बोर्ड ऑव रेवन्यू ने आयकर सबधी मामलो के लिए कपनी घोषित किया हो।

२ कम्पनी करारोपण (Company taxation) की विशेषताएँ कम्पनी के कर-निर्धारण सम्बन्धी मुख्य बाते निम्नलिखित हैं —

- (१) एक कम्पनी को उसकी आय चाहे जितनी कम क्यों न हो एक निश्चित दर से तमाम आय पर आयकर तथा अविकर (Super-tax) देना पडता है। आयकर की दर ३० प्रतिशत है उस पर ५ प्रतिशत अधिभार (Surcharge) है। अधिकर को दर ५० प्रतिशत है परन्तु उसमे से भिन्न दशाओ मे भिन्न भिन्न प्रकार की कपनियो को छूट (Rebate) मिलती है। अधिकाश कपनियो को २० प्रतिशत अधिकर देना पडता है। अधिकर पर कोई अधिभार नही लगता। कपनियो द्वारा दिया जाने वाला अविकर कपनियोके सीमित दायित्व की सुविधा तथा निगम-अस्तित्व के लिए लगाया जाता है इसलिए इसे 'निगम-कर' (Corporation tax) भी कहते हैं।

- (२) यदि कपनियों के डाइरेक्टरो अथवा उसके कुछ विशेषाधिकारियों पर कपनी द्वारा अनुचित खर्चा किया गया हो तथा कपनी के लाभो को देखते हुए ऐसा व्यय यथोचित प्रतीत नहीं होता है तो आयकर अफसर अनुचित व्यय की राशि को खर्चों के रूप में मजूर करने से इन्कार कर सकता है। धारा १० (४ए)
- (३) कपनियों द्वारा जारी किए गए बोनस हिस्सो पर तथा प्राप्त पूंजी पर ६ प्रतिशत से अधिक लाभाशो के विभाजन पर कपनी को विशेष अधिकार देना पड़ता है।
- (४) कपनी द्वारा दिए गए आयकर का श्रेय उसके हिस्सेदारो को उनके व्यक्तिगत कर-निर्धारण में दिया जाता है। यदि लाभाशो को घोषित करने के समय से तीन वर्षों में कपनी अपने आयकर की अदायगी नहीं करे तो हिस्सेदारो को लाभाशो के सकल करने की दी गई सुविधा को वापिस ले लिया जाता है।

३ धारा २३ ए कपनियाँ (Sec 23 A Companies) — एक व्यक्ति को एक कपनी के बजाय ज्यादा आयकर तथा अधिकार देना पड़ता है यदि उसकी आमदनी एक विशेष सीमा से अधिक हो। जैसे एक व्यक्ति की उच्चतम कर की दर १,००,००० ₹० आय के ऊपर अर्जित आय के लिए ७७% तथा अनर्जित आय के लिए ८४% है। जबकि एक कपनी को साधारणतया आय कर तथा अधिकार मिलाकर ५१.५% देना पड़ता है। हिस्सेदारोको कम्पनी द्वारा दिए गए आयकर का श्रेय (Credit) तो मिल जाता है परन्तु अधिकार का कोई श्रेय नहीं मिलता। इसलिए यदि एक कपनी में कुछ ही हिस्सेदारोका पूरा नियंत्रण हो तो कपनी के लाभाशो को वितरित नहीं करके वे अपने अधिकार के दायित्व को बिल्कुल कम देते हैं। इसलिए यह धारा बनाई गई जिसके द्वारा आयके एक विशेष उल्लेखित प्रतिशत तक लाभाशो को घोषित न करने पर एक दण्डिक-अधिकार (Penal Super-tax) देना पड़ता है। वित्त अधिनियम (न २) सन् १९५७ द्वारा सशोधित इस धारा की मुख्य बातें निम्न लिखित हैं —

- (१) यह धारा उस कपनी को लागू नहीं होती है जिसमें कि जनता सारत बद्धिहत (Substantially interested) हो अथवा जो कपनीकी १००% सहायक कम्पनी (Subsidiary Company) हो।

- (२) जहाँ आयकर अफसर को यह विश्वास हो जाता है कि इस कम्पनी द्वारा जिस पर कि वह धारा लागू होती है गतवर्ष के अन्त से १२ महिने तक वितरित लाभांशों की राशि वैधानिक प्रतिशत (Statutory percentage) से कम है तो वह एक लिखित हुक्म जारी करेगा कि वह आय कर तथा अधिकर के अतिरिक्त अवितरित आय के शेष भाग पर (कुल आय-आयकर तथा अतिकर और वितरित लाभांश) एक दांडिक अधिकर (Penal Super-tax) देगी जो कि नियोजन कम्पनी (Investment Companies) के लिए ५०% तथा अन्य कम्पनियों के लिए ३७% होगा।
- (३) वैधानिक प्रतिशत की राशि वह राशि है जिसके बराबर रकम को इस धारा के अन्तर्गत आने वाली सभी कम्पनियों को गतवर्ष से १२ महिनो तक लाभांशों के रूपमें वितरित करना ही पड़ता है। ऐसा न करने पर वह कम्पनी दांडिक अधिकर देने के लिए उत्तर दायी है। वैधानिक प्रतिशत की राशि विभिन्न कम्पनियों के लिए विभिन्न है, जैसे नियोजन कम्पनियों के लिए १००% भारतीय औद्योगिक कम्पनियों के लिए ४५% (सन् १९६०-६१ से ५०%) कुछ अन्य व्यापारिक कम्पनियों के लिए ६०% (सन् १९६०-६१ से ६५%) इत्यादि।
- (४) यदि आयकर अफसर को यह विश्वास है कि पिछले वर्षों में बहुत हानि होने के कारण अथवा वर्तमान वर्ष में लाभ की मात्रा कम होने के कारण वितरित लाभांशों से ज्यादा लाभांशों का वितरण अनुचित है अथवा ज्यादा लाभांशों के वितरण से सरकारी आय में कोई लाभ नहीं है तो वह इस धारा के अन्तर्गत दांडिक अधिकर लगाने वाला हुक्म नहीं जारी करेगा।
- (५) आयकर अफसर अपने इसपेक्टिंग असिस्टेंट कमिशनर की पूर्व अनुमति बिना ऐसा हुक्म जारी नहीं कर सकता तथा इसपेक्टिंग असिस्टेंट कमिशनर भी कम्पनी को सुने बिना अनुमति नहीं दे सकता।
- (VI) अनिवासी का कर-निर्धारण (Assessment of non-resident) धारा १७ (१)

अनिवासी का कर निर्धारण उसके स्वयं के नाम में अथवा उसके किसी एजेंट के नाम में हो सकता है। एक अनिवासी अपनी भारतीय आय पर निम्न प्रकार से कर देता है।

- (१) (अ) आयकर — अपनी कुल आय पर उच्चतम दरो से, तथा
 (ब) अधिकर — अपनी कुल आय पर १९% की दर से
 या एक निवासी पर लगने वाली दरसे यदि उससे ज्यादा
 अधिकर प्राप्त हो।
- (२) एक अनिवासी को एक और चुनाव (option) दिया जाता है
 कि वह ऊपर लिखे तरीके से आयकर तथा अधिकर देवे अथवा
 अपनी कुल विश्व आय पर लागू होने वाली दरो से अपनी
 आय पर आयकर तथा अधिकर देवे। प्रथम कर-निर्धारण के समय
 उसे ऐसा चुनाव करना पड़ता है जो कि अंतिम (Final)
 होता है।

(VI) बंद हुए व्यापार का कर-निर्धारण (Assessment of Discontinued businesses) — धारा २५

एक व्यापार इत्यादि के बन्द होने से तात्पर्य है उस व्यापार के बिलकुल बन्द हो जाने तथा उसके समस्त कार्यों के समाप्त हो जाने से। धारा २५(२) के अन्तर्गत उन कर-दाताओं को (जिन्हें निम्न छट नहीं मिलती है) जो अपने व्यापार बन्दकरते हैं चाहिए कि व्यापार के बन्द करने के १५ दिन के अन्दर आयकर अफसर को इस बात से सूचित कर देवे अन्यथा कर के बराबर उन्हें दंड देना पड़ता है।

बन्द किए गए व्यापार का कर-निर्धारण निम्न दो परिस्थितियों में विभिन्न होता है —

- (ए) यदि वह सन् १९१८ के अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित नहीं हो (If not assessed under the 1918 Act) —
 धारा २५ (१)

ऐसी दशा में पिछले गत वर्ष के अन्त से लेकर व्यापार के बन्द होने की अवधितक की आय पर व्यापार बन्द होनेवाले कर-निर्धारण वर्ष में ही कर लगाया जाता है। यह निर्धारण गतवर्ष की आय के अतिरिक्त होता है। इसलिए इसे संचयी कर-निर्धारण (Cumulative Assessment) भी कहते हैं —

- (बी) यदि वह सन् १९१८ के अधिनियम के अन्तर्गत कभी भी निर्धारित हो (If ever assessed under the 1918 Act)
 धारा २५ (३) व (४)

ऐसी दशा में कर-दाता को निम्न सहायताएँ (Reliefs) मिलती हैं -

- (१) गत वर्ष के अन्त से व्यापार के बन्द होने की अवधि तक की आय सर्वथा कर-मुक्त है।
- (२) इसके अतिरिक्त कर-दाता चाहे तो यह माँग कर सकता है कि इस समय की आय को गत वर्ष की आय के बदले मानी जाय तथा गत वर्ष का कर-निर्धारण इसी तरीके से किया जाय।

यदि ऐसे व्यापार का उत्तराधिकार (Succession) १-४-१९३९ के पश्चात् हुआ हो तो उत्तराधिकार के लिए भी उपरोक्त सहायताएँ उपलब्ध रहेंगी।

उपरोक्त सहायताएँ आयकर के लिए हैं। अधिकार के लिए सहायता लेनेके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उस व्यापार पर सन् १९२०-२१ या १९२१-२२ निर्धारण वर्ष में अधिकार लगाया गया हो।

नोट —उपरोक्त सहायताएँ कपनियों को नहीं मिलतीं।

प्रश्न सख्या १९

श्री सुभाष पर सन् १९१८ के अधिनियम के अन्तर्गत कर लग चुका है। मार्च सन् १९५८ को उसने अपना व्यापार बन्द कर दिया। १-९-५७ से १-३-५८ तक २०,००० रु० का लाभ रहा। गतवर्ष १-७-१९५६ से ३०-६-५७ तक का लाभ ५०,००० रु० रहा। बतलाइए उसे आयकर की कौनसी रियायतें मिलेंगी ?

उत्तर

श्री सुभाष को धारा २५ (३) के अन्तर्गत निम्न लिखित आयकर की रियायतें मिलेंगी। —

- (१) १-७-५७ से १-३-५८ तक की आय (२५,००० रु०) पूर्ण तया कर मुक्त रहेगी।
- (२) यदि वह चाहे (जैसा कि वह जरूर चाहेगा) तो वह माँग कर सकता है कि उसके गतवर्ष की ५०,००० रु० की आय को १-७-५७ से १-३-५८ तक होने वाली २५,००० रु० की आय से स्थानापन्न (Substitution) करा ले। ऐसी माँग १ मार्च १९५९ के पहले की जानी चाहिए।

प्रश्न

प्र० १ भारतीय आयकर विधान में सार्थ का पजीयन (Registration) कैसे होता है? पजीयित सार्थ (Registered firm) और अपजीयित सार्थ (Unregistered firm) के कर निर्धारण पद्धति में क्या अन्तर है?

उ० देखो (III) कडिका १ से ५ तथा प्रश्न सख्या १४ से १६।

प्र० २ सक्षिप्त टिप्पणी लिखो —

(१) धारा २३ ए कम्पनियों।

(२) बन्द हुए व्यापार का कर निर्धारण।

(३) अनिवासी का कर-निर्धारण।

(४) हिन्दु अविभक्त परिवार के बँटवारे के पश्चात् कर-निर्धारण।

उ० (१) देखो कडिका ३, विभाग (1V)।

(२) देखो विभाग (VI)।

(३) देखो विभाग (V)।

(४) देखो कडिका ३, विभाग (II)

कर की सगणना

COMPUTATION OF TAX

१ भूमिका — आयकर अधिनियम में आयकर तथा अधिकर दोनो का उल्लेख है। इस अधिनियम में करनिर्धारण के आधार, तरीको तथा प्रणाली का विवरण है। किस दर से आय पर कर लगना चाहिए इसका उल्लेख इसमें नहीं। आयकर तथा अधिकर की दरे प्रत्येक वर्ष में भारतीय ससद द्वारा पास होने वाले वार्षिक वित्त अधिनियम के द्वारा निश्चित की जाती है।

२ आयकर की दरें —

सन् १९५८-५९ तथा १९५९-६० कर-निर्धारण वर्षों के लिए सन १९५८ तथा १९५९ के वित्त अधिनियमों द्वारा आयकर की निम्न दरे निश्चित की गई हैं।

(अ) (१) प्रत्येक विवाहित व्यक्ति तथा अविभक्त हिन्दू परिवार जिसकी आय २०,००० रु० से ज्यादा नहीं है, के लिये —

आयके विभाग रु०			दर प्रतिशत
(१) कुल आय के प्रथम	३,०००	पर	कुछ नहीं
(२) कुल आय के अगले	२,०००	पर	३
(३) " " " "	२,५००	"	६
(४) " " " "	२,५००	"	९
(५) " " " "	२,५००	"	११
(६) " " " "	२,५००	"	१४
(७) " " " "	५,०००	"	१८

(२) प्रत्येक अविवाहित व्यक्ति, अपजीयित सार्थ अथवा अन्य जन-मंडल अथवा प्रत्येक विवाहित व्यक्ति तथा अविभक्त हिन्दू परिवार जिसकी आय २०,००० रु० से अधिक हो, के लिए —

		(प्रतिशत)
(१)	कुल आय के प्रथम १,००० रु० पर	कुछ नहीं
(२)	” ” अगले ४,००० रु० पर	३
(३)	” ” ” २,५०० रु० पर	६
(४)	” ” ” २,५०० रु० पर	९
(५)	” ” ” २,५०० रु० पर	११
(६)	” ” ” २,५०० रु० पर	१४
(७)	” ” ” ५,००० रु० पर	१८
(८)	” ” शेष भाग पर	२५

उपरोक्त दरों से कर की गणना करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है —

(१) कर-मुक्त सीमा (Exemption Limit) —

वह आय जो निम्न लिखित सीमाओं से अधिक नहीं है कर देने से मुक्त है। किसी भी दशा में करकी रकम कुल आय तथा निम्न सीमाओं के अन्तर के आधे से अधिक नहीं हो सकती। सीमाएँ निम्न लिखित हैं —

(१) ६००० रु० प्रत्येक अविभक्त हिन्दू परिवार के लिए जो गतवर्ष के अन्त में निम्न लिखित शर्तों में से कोई एक पूरी करता हो —

(अ) कि उसके कम से कम दो सदस्य ऐसे हैं जो बँटवारे के हकदार हैं तथा जिनमें से कोई भी १८ वर्ष की उम्र से कम नहीं है। अथवा

(ब) कि उसके कम से कम दो ऐसे सदस्य ऐसे हैं जो बँटवारे के हकदार हैं तथा जिनमें से कोई एक दूसरे की सतान नहीं है तथा वे सब परिवार के किसी अन्य जीवित सदस्य की सतान नहीं हैं।

(२) ३००० रु० अन्य प्रत्येक दशामें।

२ बच्चों का भत्ता

एक विवाहित व्यक्ति तथा हिन्दू अविभक्त परिवार जिसकी कुल आय २०,००० रु० से अधिक नहीं है, को प्रत्येक बच्चे पर जो उस पर पूर्णतया निर्भर है, ३०० रु० (केवल दो बच्चों तक) छूट मिलती है। इस प्रकार एक विवाहित पुरुष को जिसके दो बच्चे उसपर पूर्णतया निर्भर हैं कोई कर नहीं देना पड़ता यदि उसकी कुल आय ३६०० रु० से अधिक नहीं है।

३. अर्जित आय पर छूट तथा अधिभार (Earned Income Relief and Surcharges)

३१ मार्च सन् १९५७ तक अर्जित आय पर एक विशेष प्रकार की छूट मिलती थी। वित्त अधिनियम १९५७ के अनुसार यह छूट बिलकुल बन्द कर दी गई है। अब आयकर तथा अधिकर दोनों की दरे अर्जित आय तथा अनर्जित आय के लिए समान हैं किन्तु अनर्जित आय पर अर्जित आय की अपेक्षा एक अतिरिक्त अधिभार लगाया जाता है। इससे यह तात्पर्य निकला कि अनर्जित आय पर आयकर तथा अधिकर दोनों से एक विशेष रियायत मिलती है परन्तु पहले की अपेक्षा बिलकुल दूसरी शकल में।

उपरोक्त दरों से लगाये गये आयकर पर निम्न अधिभार लगता है —

(अ) सघ के कार्यों के लिए निम्न अधिभार —

(१) आय कर का ५%, तथा

(२) १ लाख से ऊपर अर्जित आय के आयकर का ५%

(ब) अनर्जित आय पर एक विशेष प्रकार का अधिभार अनर्जित आय के आयकर का १५%।

सीमान्त आमदनी वाली दशाओं में सहायता देने के लिए अधिभार लगाने के लिए निम्न सीमाएँ हैं —

(1) १५,००० रु० उस अविभक्त हिन्दू परिवार के लिए जो कि ६,००० रु० की कर-मुक्त सीमा के लिए अधिकारी है।

(11) ७,५०० रु० किसी अन्य दशामें। यदि कुल आय में साधारण हिस्से (ordinary shares) का लाभांश शामिल है तो इस सीमा को लाभांशों की रकम अथवा १५०० रु० (जो भी कम हो) से बढ़ा दिया जायगा।

(४) सन् १९५९-६० के कर-निर्धारण में यदि किसी कर-दाता की (कम्पनी को छोड़कर) कुल आय में निम्न शीर्षको की आय शामिल हो कुल आय के इतने हिस्से की आय पर गतवर्ष (सन् १९५८-५९) की दरों से कर लगेगा —

(१) वेतन,

(२) प्रति भूतियों का व्याज, तथा

(३) लाभांश-जिनके बारेमें धारा ४९ बी के अनुसार कम्पनी द्वारा हिस्सेदार के लिए कर देना माना गया है।

सन् १९५८-५९ तथा १९५९-६० के लिए आयकर की दरें समान होने से उपरोक्त नियम कोई महत्व नहीं रखता है।

(ब) प्रत्येक कम्पनी तथा स्थानीय अधिकारी की कुल आय पर ३०% आयकर तथा उसपर ५% अधिभार लगता है।

(स) उस प्रत्येक दशा में जबकि उच्चतम दरों से कर लगाया जाता है आयकर की दर २५% तथा उसपर २०% अधिभार है।

उस प्रत्येक दशा में जब कि करकी कटौती उच्चतम दरों से की जाती है आय कर की दरें निम्न हैं —

	आयकर	अधिभार
प्रत्येक कम्पनी के लिए	३०%	१५%
अन्य दूसरी दशामें	२५%	५%

(द) प्रत्येक पञ्जीयित सार्थ पर निम्न दरों से आय कर लगता है —

	दर
(१) कुल आय के प्रथम ४०,००० रु० पर	कुछ नहीं
(२) " " " अगले ३५,००० रु० पर	५%
(३) " " " " ७५,००० रु० पर	६%
(४) " " " शेष भाग पर	९%

३ अधिकर (Super-tax)

धारा ५५ के अनुसार अधि कर एक प्रकारका अतिरिक्त आयकर आरोपण (additional levy of Income-tax) है। आयकर तथा अधिकर के लिए कुछ दशाओं में कुल आय भिन्न भिन्न होती है, जिसका विस्तृत उल्लेख अध्याय ३ में किया जा चुका है।

४ अधिकर की दरें

कर-निर्धारण वर्ष १९५८-५९ तथा १९५९-६० के लिए अधिकर की निम्न दरें हैं —

(अ) प्रत्येक व्यक्ति, अविभक्त हिन्दू परिवार, अपजियित सार्थ तथा अन्य जन-मंडल के लिए —

(१) कुल आय के प्रथम	२०,००० रु० पर	कुछ नहीं
(२) " " " अगले	५,००० रु० पर	५%
(३) " " " "	५,००० रु० पर	१५ "
(४) " " " "	१०,००० रु० पर	२० "
(५) " " " "	१०,००० रु० पर	३० "
(६) " " " "	१०,००० रु० पर	३५ "
(७) " " " "	१०,००० रु० पर	४० "
(८) " " " शेष भाग	पर	४५ "

अधिकर पर अधिभार (Surcharge on Super tax)

उपरोक्त दरो से निश्चित अधिकर की रकम पर निम्न अधिभार लगाया जाता है —

(अ) सघ के कार्यों के लिए निम्न रकमों के बराबर अधिभार —

(१) अधिकर की रकम का ५%, तथा

(११) १००,००० रु० से अधिक अर्जित आय की रकम पर लगे अधिकर का ५%

(ब) अर्जित आय पर एक विशेष अधिभार — जो कि अर्जित आय पर लगे हुए अधिकर की रकम के १५% के बराबर है।

(ब) प्रत्येक स्थानीय अधिकारी पर उसकी कुल आय के १६% के बराबर अधिकर लगता है तथा उस अधिकर पर १२१% अधिभार लगता है।

(स) प्रत्येक सहकारिता समिति के लिए अधिकर की दरें निम्न हैं —

(१) कुल आय के प्रथम २५,००० पर कुछ नहीं

(११) कुल आय के शेष भाग पर १६%। ऐसे अधिकर पर १२१% अधिभार लगता है।

(द) प्रत्येक कम्पनी के लिए अधिकर की दर ५०% है जिसमें से भिन्न भिन्न छूटे दी जाती है। कम्पनी के अधिकर पर कोई अधिभार नहीं लगता।

जहाँ किसी कर-दाता (कम्पनियों को छोड़कर) की कुल आय में “वेतन” शीर्षक की ऐसी आय शामिल है जिस पर अधिकर काटा गया है

अथवा जिसपर अधिकर काटा जाना चाहिए था, तब सन् १९५९-६० वर्ष के लिए कर-निर्धारण करते समय वेतन की ऐसी आय पर सन् १९५८-५९ की दरों से अधिकर लगाया जायगा। परन्तु चूंकि सन् १९५८ तथा सन् १९५९ की दरों में कोई अन्तर नहीं है इसलिए इसका कोई विशेष महत्व नहीं है।

५ कर-निर्धारण की सगणना (Computation of Assessment) एक कर दाता के कर-निर्धारण में मुख्य क्रम निम्न लिखित है —

- (१) अध्याय १० में बताए गए तरीकों के अनुसार उसकी कुल आय तथा कुल विश्व आय मालूम करनी चाहिए। उद्गम स्थान पर काटे हुए करको तथा अन्य प्रकार से दिए गए कर की रकमों को जोड़ देना चाहिए।
- (२) कुल आय पर आयकर तथा अधिकर एवं उनपर अविभार निकालना चाहिए।
- (३) इसके पश्चात् आयकर तथा अधिकरकी औसत दरें मालूम करनी चाहिए। यह कार्य कुल आय को आयकर से तथा अधिकर से विभाजित करके किया जाता है।
- (४) इसके पश्चात् आशिक कर-मुक्त आय की रकम मालूम करके उस पर आयकर तथा/अथवा अधिकर की औसत दरों से छूट की रकम निकालनी चाहिए।
- (५) आय कर तथा अधिकर की कुल रकमों में से निम्न रकम घटानी चाहिए —
 - (अ) आशिक कर-मुक्त आयकर छूट की रकम।
 - (ब) दुबारा-करारोपण छूट— यदि होतो।
 - (स) धारा १८ ए के अन्तर्गत दिया गया अग्रिम कर तथा उस पर व्याज।
- (६) शेष आय वह होगी जो कि कर दाता द्वारा देनी होगी या लेनी होगी। यदि कोई दंड लगाया गया हो तो उसकी रकम भी इस कुल रकम में जोड़ देना चाहिए।

प्रश्न सख्या १८

गत वर्ष १९५८-५९ के लिए एक वकील (जिसके चार बच्चे उसपर निर्भर हैं) की व्यावसायिक आमदनी १०,००० रु० तथा जायदाद की आय ५००० रु० थी। कर-निर्धारणवर्ष १९५९-६० के लिए उसे कितना आयकर देना पड़ेगा।

उत्तर

श्री वकीलका सन् १९५९-६० के लिए कर-निर्धारण —

	रु०
अर्जित आय १०,००० रु० पर आयकर	४१७
उसपर ५% अधिभार	२१
शेष अनर्जित आय ५,००० रु० पर आयकर	६२५
उसपर २०% (५% + १५%) अधि भार	१२५
	<hr/>
कुल आय-कर रु०	१,१८८
	<hr/>

नोट —

अर्जित आय —

	रु०		
कुल आय के प्रथम	३,६००	पर	कुछ नहीं
कुल आय के अगले	१,४००	पर	३% - ४२
कुल आय के अगले	२,५००	पर	६% - १५०
कुल आय के अगले	२,५००	पर	९% - २२५
	<hr/>		<hr/>
			४१७

अनर्जित आय —

कुल आय के अगले	२,५००	पर	११% - २७५	
कुल आय के अगले	२,५००	पर	१४% - ३५०	६२५
	<hr/>		<hr/>	<hr/>
			रु०	१०४२
				<hr/>

प्रश्न संख्या १९

कैलेंडर वर्ष सन् १९५८ के लिए अ, (अविवाहित व्यक्ति) की आय निम्न लिखित है —

(१) ३,००० रु० - व्यापार से कर-योग्यलाभ ।

(२) ४,५०० रु० - जायदाद की आय ।

सन् १९५९-६० के लिए उसे कितना कर देना पड़ेगा ?

सन् १९५९-६० के लिए श्री अ का कर-निर्धारण —

			रु०
कुल आय के प्रथम	१,००० पर		कुछ नहीं
कुल आय के अगले	४,००० पर	३%—	१२०
कुल आय के अगले	२,५०० पर	६%—	१५०
			<hr/>
कुल आयकर			रु० २७०
			<hr/>

नोट — चूँकि आय ७५०० से अधिक नहीं है इसलिए इस पर कोई अधि-भार नहीं लगेगा।

प्रश्न सख्या २०

३१ मार्च १९५९ को समाप्ति होने वाले गतवर्ष के लिए श्री कान मल (जो एक विवाहित व्यक्ति है तथा जिनके ३ बच्चे उनपर निर्भर हैं) की आय का विवरण निम्न प्रकारसे है —

- (१) प्रतिभूतियोंका व्याज (सकल) १००० रु० (उद्गम-स्थान पर कर-कटौती की रकम ३०० रु०
- (२) कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों का व्याज ५०० रु०
- (३) जायदाद की आय ३,००० रु०
- (४) चिल्लर किराने की दूकान से लाभ ४,००० रु०
- (५) लाभका $\frac{१}{२}$ हिस्सा एक अपजीयित सार्थ से २५,००० रु०
(जिसमें वह सक्रिय भागी नहीं है।)
- (६) सहकारिता समिति के लाभशो से आय २,००० रु०
- (७) उस कम्पनी के लाभशो से आय जिसपर कोई कर नहीं लगा है ८५४ रु०
- (८) उस कम्पनी के लाभशो से आय जिसकी पूर्ण १०० रु०
आय पर कर लग चुका है।

उसने २५००० रु० के जीवन बीमा पर ३,००० का वार्षिक प्रीमियम तथा १,००० रु० का दान एक यूनिवर्सिटी को दिया।

उत्तर

श्री कानमल का सन् १९५९-६० के लिए कर-निर्धारण —

आय का विवरण	रकम र०	उद्गम स्थान पर काटा गया अथवा अन्य प्रकार से दिया हुआ कर र०
(१) प्रति भूतियोका ब्याज—करारोपित (taxed)	१,०००	३००
प्रतिभतियो का ब्याज कर-मुक्त (tax-free)	५००	
(२) जायदाद की आय	३,०००	
(३) व्यापार के लाभ स्वयंके किराने का -व्यापार	४,०००	
“ हिस्सा अपजीयित सार्थ से	२५,०००	
(४) अन्य साधनो से आय		
सहकारी समिति के लाभाश	२,०००	
कम्पनियो की कर मुक्त आय से लाभाश	८५४	
“ , करारोपित “ “ “ (१०० नेट)	१४६	४६
$\text{सकल} = \left(\frac{१०० \times २००}{१३७} \right) \text{र०} =$		

कुल आय	३६,५००	३४६
--------	--------	-----

कर-सगणना :

अर्जित आय	कुल आय के प्रथम	दर प्रतिशत	कर र०
	१,००० पर कुछ नहीं		
	“ “ अगले	३,००० पर ३%	९०
अर्जित आय .	“ “ “	१,००० पर ३%	३०
	“ “ “	२,५०० पर ६%	१५०
	“ “ “	२,५०० पर ९%	२२५
	“ “ “	२,५०० पर ११%	२७५
	“ “ “	२,५०० पर १४%	३५०
	“ “ “	५,००० पर १८%	९००
	“ “ “	१६,५०० पर २५%	४,१२५
आयकर			६,१४५

अधिभार	अर्जित आय के आयकर रु० ९० पर ५%	५
	अनर्जित आय की आयकर रु० ६,०५५ पर २०%	१२११
	कुल आयकर तथा अधिभार	७,३६१

औसत दर $७३६१-३६५०० \times १०० = २०.१७\%$

आशिक कर मुक्त आय —

(१) कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों का व्याज	५००
(२) सहकारी समिति के लाभांश	२,०००
(३) अपजीयित सार्थ से $\frac{१}{२}$ हिस्सा	२५,०००
(४) जीवन बीमा प्रीमियम (जीवन बीमे की रकम के १०% तक ही)	२,५००
(५) धर्मादा चंदा जो कि कुल आय में से कर-मुक्त आय घटाकर बची हुई रकम का ५% है। [$३६,५०० - (५०० + २००० + २५,००० + २,५००)$] अर्थात् $५\% \times ६,५००$	३२५
	३०,३२५

	रु०
कुल आय पर कुल आय कर	७,३६१
बाद, ३०,३२५ पर २०.१७% को औसत दर से छूट	६,११७
सन् १९५९-६० के लिए आयकर	१,२४४
बाद, उदगम स्थान पर काटा गया अथवा दिया गया कर	३४६
कुल आयकर जो देना पड़ेगा	रु० ८९८

नोट : श्री कानमल को कोई अधिकर (Super-tax) नहीं देना पड़ेगा क्योंकि अपजीयित सार्थ का $\frac{१}{२}$ हिस्सा अर्थात् २५,००० रु० अधिकर से मुक्त है (ऐसा तब होता है जबकि अपजीयित सार्थ ने अपनी आय पर अधिकर दिया हो।) शेष आय ११,५०० रु० रहती है जो अधिकर की न्यूनतम सीमा से बहुत कम है।

प्रश्न सख्या २१ •

निम्न विवरण से एक सीमित लोक कम्पनी का सन् १९५९-६० के लिए कर-निर्धारण कीजिए —

(१) कम्पनी की कुल आय ३०,००,००० रु० है।

- (२) उद्गम स्थान पर काटा हुआ कर १४,५०० रु० है।
 (३) धारा १८ ए के अन्तर्गत अग्रिम कर की दी गई रकम ८,००,००० रु० है।
 (४) एक यूनिवर्सिटी को दिया गया दान १,२०,००० रु० है।
 (५) कम्पनी के अधिकर की वास्तविक दर २०% है।

उत्तर :

सन् १९५९-६० के लिए कम्पनी का कर निर्धारण

	रु०
कुल आय	३०,००,०००
३०,००,००० रु० पर, आय कर ३०% दर से	९,००,०००
उसपर ५% अधिभार	४५,०००
३०,००,००० रु० पर अधिकर २०% दर से	६,००,०००
	१५,४५,०००
बाद, धर्मादा चन्दे पर अवहार (Rebate) जिसकी उच्चतम कर मुक्त रकम १,००,००० रु० है ३१.५% की दर से	३१,५००
	१५,१४,५००
बाद, उद्गम स्थान पर काटा हुआ कर	१४,५००
धारा १८ ए के अन्तर्गत दिया हुआ अग्रिम कर	८,००,०००
	८,१४,५००
कुल कर जो कम्पनी को देना है रु०	७,००,०००

प्रश्न

- प्र० १ “करकी सगणना” पर एक छोटा सा लेख लिखो।
 उ० देखो कड़िका १ से ५

चतुर्थ भाग

कर-निर्धारण एवं अपील पद्धति

ASSESSMENT AND APPELLATE PROCEDURE

अध्याय १३

कर-निर्धारण पद्धति

ASSESSMENT PROCEDURE

१ पिछले अध्यायो मे बताए गए नियमो के अनुसार विभिन्न कर-दाताओ की कुल आय को मालूम करने पर ही आयकर-सम्बन्धित कार्य समाप्त नही हो जाता। इसके अतिरिक्त मुख्य बात कर-दाता की कर-निर्धारण पद्धति है जिसके अनुसार उसकी कुल आय पर उसे कर देना पडता है। कर-निर्धारण मे दो बातें शामिल होती हैं — (क) कर-दाता की कुल आय का मालूम करना, तथा (ख) , कर-दाता को कितना और किस प्रकार से कर देना है या आयकर विभाग से वापिस लेना है, मालूम करना। निम्न पक्तियो मे इस पद्धति का विस्तृत विवरण किया जाता है —

२. आय का नक्शा (Return of Income)

धारा २२

आय का नक्शा दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करना आयकर-निर्धारण की पहली कार्यवाही है। नोटिस दो प्रकार के होते हैं — (क) सामान्य नोटिस, तथा (ख) व्यक्तिगत नोटिस। सामान्य नोटिस वह होता है जो आयकर अफसर द्वारा प्रतिवर्ष १ मई के पहले जारी किया जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जिसकी आय न्यूनतम कर-योग्य सीमा से अधिक होती है, आज्ञा दी जाती है कि नोटिस की तारीख से ६५ दिन के अन्दर वह अपनी आय का नक्शा दाखिल करे। व्यक्तिगत नोटिस के अनुसार आयकर अफसर किसी भी कर-दाता को यह आज्ञा दे सकता है कि वह नोटिस मिल जाने के ३५ दिन के अन्दर स्वीकृत फार्म मे आय का नक्शा दाखिल करे। सामान्य तथा व्यक्तिगत दोनों प्रकार के नोटिसो मे नक्शा दाखिल करने की तारीख बढ़ाने का अधिकार आयकर अफसर को प्राप्त है। यदि किसी व्यक्ति ने अपना नक्शा दाखिल कर दिया हो और बाद मे उसे ज्ञात हो कि उसके अन्दर कोई चूक अथवा त्रुटि रह गई है तो ऐसी स्थिति मे कर-निर्धारण से पूर्व किसी भी समय वह ठीक किया हुआ नक्शा दाखिल कर सकता है।

३ अस्थायी कर-निर्धारण (Provisional Assessment) धारा २३बी

इनकम-टैक्स अफसर को यह अधिकार है कि वह कर-दाता के बनाए नक्शे इत्यादि के आधार पर नियमित कर-निर्धारण से पूर्व ही अस्थायी कर-निर्धारण कर ले। ऐसा कर-निर्धारण वस्तुतः एक सक्षिप्त कर-निर्धारण है। इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती और इस कर-निर्धारण में कर की जो रकम निश्चित कर दी गई है उसे मांग की सूचना में आवेदित अवधि के अन्दर ही अवश्य जमा कर देना चाहिए नहीं तो कर-दाता को कर की रकम के बराबर दंड भुगतना पड़ता है।

४ नियमानुसार कर-निर्धारण (Regular Assessment) धारा २३

(क) नक्शे के आधार पर धारा २३ (१)

यदि आयकर अफसर को यह विश्वास हो जाता है कि आय के नक्शे में सम्पूर्ण सामग्री सही और पूर्ण है तो वह बिना किसी अन्य साक्षी के ही कर-निर्धारण कर देता है।

(ख) प्रस्तुत किए गए सबूत के आधार पर धारा २३ (३)

यदि आयकर अफसर कर-दाता के नक्शे को पूर्ण तथा सही नहीं समझता तो वह आवश्यक जांच पड़ताल और पूछताछ के पश्चात् कर-निर्धारण कर देता है। आयकर अफसर कर-दाता के नाम नोटिस जारी कर उसे स्वयं या उसके प्रतिनिधि को नक्शे के समर्थन में सबूत देने के लिए बुला सकता है। वह धारा ३७ के अनुसार आज्ञा जारी करके कर-दाता को स्वयं उपस्थित होने के लिए भी बाध्य कर सकता है। हिसाबों, हिसाब-पत्रको तथा कर-दाता द्वारा प्रस्तुत किसी अन्य साक्ष्य का निरीक्षण करके आयकर अफसर कर-निर्धारण सम्बन्धी आज्ञा देता है।

(ग) अति उत्तम निर्णय के आधार पर (Best Judgment Assessment) धारा २३ (४)

यदि (i) कर-दाता व्यक्तिगत नोटिस के उत्तर में आय का नक्शा दाखिल नहीं करता, या (ii) आवश्यक सबूत प्रस्तुत नहीं करता अथवा (iii) मांग गए बही खाते तथा हिसाब-पत्रकोको पेश नहीं करता या वह स्वयं उपस्थित नहीं होता तो आयकर अफसर अपने उत्तम निर्णय के अनुसार इकतरफा (Ex-parte) कर-निर्धारण करता है। उत्तम निर्णय करते समय आयकर अफसर को इमानदारी से कार्य करना चाहिए। ऐसे कर-निर्धारण के विरुद्ध कर-दाता को निम्न अधिकार प्राप्त है —

(१) ऐसे कर-निर्धारण को रद्द करने के लिए वह आयकर अफसर को प्रार्थना कर सकता है। कर-निर्धारण की तिथि से एक महिने के अन्दर ऐसी प्रार्थना की जानी चाहिए। — धारा २७

(२) वह अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर से आयकर अफसर की आज्ञा के विरुद्ध अपील कर सकता है। — धारा ३०

५ मांग का नोटिस (Notice of Demand) धारा २९

कर की रकम निश्चित करने के पश्चात् आयकर अफसर कर-दाता को एक नोटिस भेजता है जिसके अन्तर्गत लिखी हुई एक निश्चित तारीख तक कर-दाता को कर की कुल रकम जमा करानी पड़ती है। इस नोटिस के साथ कर निश्चित करने के निर्णय की एक नकल भी भेजी जाती है। यदि नकद पैसा एक बार में ही देने में कोई वास्तविक आपत्ति हो तो आयकर अफसर कर-दाता को यह अधिकार दे सकता है कि वह उस रकम का कुछ किस्तों में जमा करा देवे।

६ भूल सुधार (Rectification of Mistake) धारा ३५

कमिश्नर, अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर या आयकर अफसर द्वारा किसी निर्णय (Order) में कोई भूल हो गई हो जो कि बिल्कुल स्पष्ट हो तो वे अपनी ओर से या कर-दाता के प्रार्थना करने पर उसका भूल सुधार कर सकते हैं। निर्णय की तारीख से ४ वर्ष की अवधि तक ऐसी भूल सुधार हो सकती है।

७ अतिरिक्त कर-निर्धारण (Additional Assessment or Re-opening Assessment) धारा ३४

यदि आयकर अफसर को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई आय कर लगने से रह गई है तो वह उस पर उस आय के कर-निर्धारण वर्ष के बाद भी कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है। यदि उसने घाटे की या घिसाई की छूटे अधिक दे दी है तो उसे पुन विचार का अधिकार है। ऐसा नोटिस जारी करने के पहले कुछ दशाओं में आयकर कमिश्नर की स्वीकृति भी प्राप्त करनी पड़ती है। परन्तु आयकर अफसर ३१-३-१९४१ के पहले वाले किसी भी समय के लिए कोई भी नोटिस जारी नहीं कर सकता। पहले जो ८ वर्ष की सीमा थी वह अब हटा दी गई है। यदि कर-दाता कसूरवार नहीं है तो ऐसा नोटिस ४ वर्ष के भीतर ही जारी किया जाना चाहिए।

८ तत्कालीन कर-निर्धारण (Emergency Assessment) धारा २४ ए

यदि आयकर अफसर को यह मालूम हो जाए कि कोई व्यक्ति चालू वर्ष में या उसके समाप्त होने के बाद ही भारत छोड़ कर सदैव के लिए

बाहर जाने वाला है तो वह केवल सात दिन का नोटिस दे कर उसे पिछले गत वर्ष के बाद की आय का नक्शा भेजने के लिए बाध्य कर सकता है। चालू वर्ष में उसके जाने की तारीख तक की आय का अनुमान लगा कर उस पर चालू वर्ष की दरों से कर वसूल कर लिया जाता है। यह धारा इस सामान्य नियम के अपवाद स्वरूप है कि कर-निर्धारण गत वर्ष की आय पर ही किया जाता है।

९ प्रतिनिधि कर-निर्धारण (Representative Assessment) धाराएँ २४ बी, ४० तथा ४१ —

कई बार उन कर-दाताओं पर जो कि आमदनी के मालिक हैं कर न लगाया जाकर उनके प्रतिनिधियों पर कर लगाया जाता है ऐसे प्रतिनिधि प्रबन्धक, एक्जीक्यूटिव, वैधानिक प्रतिनिधि, सरक्षक, ट्रस्टी, महा प्रबन्धक इत्यादि हैं जो कि अपने किसी मृत व्यक्ति, नाबालिग, पागल, हिताधिकारी की आय पर कर देने के लिए उत्तराधिकारी हैं।

१० कर-भुगतान प्रमाण पत्र (Tax-Clearance Certificates) धारा ४६ ए

यदि कोई व्यक्ति भारत छोड़ कर बाहर जाता है तो उसको जाने के पहले कर-भुगतान प्रमाण-पत्र या कर-मुक्त आय प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था १९५३ के आयकर सशोधन अधिनियम से सरकार ने आय को सुरक्षित करने के हेतु की है। भारत से बाहर जाने से पहले उस व्यक्ति द्वारा अपने क्षेत्रों के आयकर अफसर को प्रार्थना की जाती है। आयकर अफसर के पूर्णतया सतुष्ट हो जाने पर इस आशय का एक अधिकृत फॉर्म (Authorisation form) कर-दाता को मिल जायगा। यह फॉर्म विदेशी विभाग के आयकर अफसर से कर-भुगतान प्रमाण पत्र या कर-मुक्त आय प्रमाण पत्र के बदले में बदल दिया जायगा। भारत से जाने वाले व्यक्तियों के पास ऐसा प्रमाण पत्र है या नहीं इस बात को पूर्णतया जाँच करने की जिम्मेदारी उन जहाजी कपनियों पर है जो कि यात्रियों को भारत से बाहर ले जाती हैं। यदि अपने आप को पूर्णतया सतुष्ट किए बिना ही किसी व्यक्ति को अपने पूर्ण कर भुगतान किए बिना जाने दिया हो तो जिम्मेदारी जहाजी कपनी की होगी। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें इस प्रकार के प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने से मुक्त कर दिया गया है।

११ दंड (Penalties) —

भारतीय आयकर अधिनियम की धाराएँ २५ (२), २८, ४४ ई, ४४ एफ, ४६ (१), ५१ तथा ५२ के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के दंड का विधान है।

विभिन्न प्रकार की त्रुटियों तथा गलतियों के विभिन्न प्रकार के दंड हैं। सबसे मुख्य धाराएँ २८ तथा ४६ (१) हैं। ठीक समय में आयकर-पत्रक (Return of Income) नहीं भरने तथा धारा २२ (४) व २३ (२) के अन्तर्गत जारी किए गए नोटिसों की पूरी शर्तों का पालन नहीं करने एवं आमदनी को छुपाने (Concealment of Income) के अपराध में कर की रकम से $1\frac{1}{2}$ गुना दंड तक लगाया जा सकता है। यह दंड इस्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिशनर ऑफ इनकम-टैक्स की पूर्वानुमति से आयकर-अफसर लगा सकता है—धारा २८। ठीक समय पर कर नहीं भरने पर आयकर-अफसर बाकी कर की रकम के बराबर दंड लगा सकता है।—धारा ४६ (१)

प्रश्न

प्र० १ सक्षिप्त टिप्पणी लिखो —

- (क) आय का नक्शा
- (ख) अस्थायी कर-निर्धारण
- (ग) अति-उत्तम निर्णय के आधार पर कर-निर्धारण
- (घ) भूल सुधार
- (ङ) अतिरिक्त कर-निर्धारण
- (च) तत्कालीन कर-निर्धारण
- (छ) कर-भुगतान प्रमाण-पत्र
- (ज) प्रतिनिधि कर-निर्धारण।

उ० देखो (क) कड़िका २, (ख) कड़िका ३, (ग) कड़िका ५
 (घ) कड़िका ६, (ङ) कड़िका ७, (च) कड़िका ८,
 (छ) कड़िका १०, (ज) कड़िका ९।

कर-भुगतान तथा वसूली

PAYMENT AND RECOVERY OF TAX

१ (I) उद्गम स्थान पर कर कटौती (Deduction of Tax at Source) — धारा १८

आयकर विभाग को कर देने के कई तरीके हैं। एक तरीका कर-भुगतान का वह है जिसके अनुसार निम्न प्रकार की आय पर निश्चित दरों से उद्गम स्थान पर कर काटना अनिवार्य है —

- (अ) वेतन
- (ब) प्रतिभूतियों का ब्याज,
- (स) अनिवासी को भुगतान।

२ उद्गम स्थान पर निम्न दरों से कर काटा जाता है —

- (क) वेतन — यदि कर्मचारी की वेतन से आय कर-योग्य है तो मालिक के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने कर्मचारी के वेतन की रकम में से कुल वेतन पर लागू होने वाली कर-दरों से आयकर व अतिरिक्त कर काट ले और काटी हुई रकम खजाने में जमा करा दे।
- (ब) प्रतिभूतियों पर ब्याज — ऐसा ब्याज देने वाले का उत्तरदायित्व है कि वह ब्याज की रकम पर उच्चतम दरों से आय कर काट लेवे।
- (स) अनिवासी को भुगतान — अनिवासी को भुगतान की गई कुछ रकमों पर उच्चतम दर से आयकर तथा १९ प्रतिशत अथवा उसकी आय पर लगने वाली दर से (जो भी अधिक हो) अधिकतर काटा जाता है। पर यदि अनिवासी एक कंपनी है तो कंपनी पर लागू होने वाली दरों से कर काटा जायगा।
- (३) यदि आय कम है तो आयकर अफसर के प्रमाणपत्र देने पर कर कम दरों पर भी काटा जाता है।

- (४) काटी हुई कर की रकम को सरकारी खजाने में एक हफ्ते के अन्दर पहुँचाना चाहिए। कर-निर्धारण करते समय काटी गई रकम का श्रेय कर-दाता को मिलता है। यदि काटी हुई रकम वास्तविक कर से ज्यादा हो तो अधिक रकम वापस कर दी जाती है।

३ (II) कमाते जाओ और कर देते जाओ (Pay-as-you earn scheme) — धारा १८ ए

- (१) इस योजना के अन्तर्गत जिस वर्ष में आय उत्पन्न होती है उसी वर्ष आयकर और अधिकर चालू दरों से ही वसूल कर लिया जाता है। अर्थात् नियमित कर-निर्धारण से पूर्व ही कर की रकम अग्रिम वसूल की जाती है। इसलिए इस का नाम कर कर का अग्रिम भुगतान (Advance Payment of Tax) भी है।
- (२) यह योजना उस आय पर लागू होती है जिन पर उद्गम स्थान पर कर नहीं कटता, जैसे, जायदाद की आय, व्यापारिक-लाभ तथा अन्य साधनों की आय (लाभांश को छोड़ कर)।
- (३) यह योजना केवल उन्हीं कर-दाताओं पर लागू होती है जिन की आय गतवर्ष में उनके लिए न्यूनतम करयोग्य सीमा से २,५००) से अधिक हो। अर्थात् यह योजना एक व्यक्ति, अपजीयित सार्थ या अन्य जन-मंडल पर तब लागू होती है जबकि गत वर्ष के अंतिम पूरित करनिर्धारण (Latest Completed Assessment) के अनुसार उनकी आय ५,५०० रु० (३,००० + २,५०० रु०) से अधिक रही हो या अनुमानित हो। यह योजना अविभक्त हिन्दू परिवार पर तब लागू होती है जबकि उसकी आय गत वर्ष के पूरित कर-निर्धारण के अनुसार ८,५०० रु० (६,००० + २,५००) से अधिक हो।
- (४) पेशगी कर की किस्तों का भुगतान १५ जून, १५ सितम्बर, १५ दिसम्बर और १५ मार्च को किया जाता है।
- (५) यदि अंतिम पूरित कर-निर्धारण में कर-दाता की आय उपरोक्त रकमों से ज्यादा रही हो तो आयकर अफसर उसी रकम को इस वर्ष की आय मान कर पेशगी कर की रकम निश्चित करेगा। परन्तु यदि कर-दाता को उम्मीद है कि चालू वर्ष में गत वर्ष की

अपेक्षा कम आय होगी तो वह अपने हिसाब से पेशगी कर का भुगतान कर सकता है।

(६) यदि कर-दाता इसी अंतिम पूरित कर-निर्धारण के आधार पर ही कर देता है तो चालू वर्ष की आय गत वर्ष की आय से कितनी ही अधिक क्यों न हो तो भी वह किसी दंड का भागी नहीं हो सकता। परन्तु जब कर-दाता अपने अनुमान के आधार पर कर की किस्ते देता है तब यदि उसके द्वारा अनुमानित कर की रकम नियम पूर्वक कर निश्चित करने पर की गई वास्तविक रकम के ८० प्रतिशत से कम निकले तो उसको १ जनवरी से नियमपूर्वक कर निश्चित करने के समय तक इसी कमी पर ४ प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि कर-दाता ने जान बूझ कर गलत अनुमान लगाया है तो वह और भी अधिक दंडनीय होगा।

(७) यदि कर-दाता कभी भी कर से निर्धारित (assessed) नहीं हुआ है और उसकी चालू वर्ष की आय के ऊपर दी गई सीमाओं से अधिक होने की संभावना है तो उसे १५ मार्च से पहले चालू वर्ष में बिना नोटिस मिले ही आय का अनुमान भेज देना चाहिए।

(८) यदि इस प्रकार किस्तों द्वारा जमा की रकम वास्तविक रकम से अधिक है तो ऐसे आधिक्य पर सरकार ४ प्रतिशत सूद देती है।

४ कर-निर्धारण के उपरांत माँग के नोटिस पर भुगतान धारा २९

कर-निर्धारण के उपरान्त आयकर अफसर द्वारा माँग का नोटिस मिलने पर कर-दाता द्वारा भुगतान ही वास्तविक तथा अंतिम भुगतान का तरीका होता है। ऐसा भुगतान करने के पहले कर-दाता को उद्गम स्थान पर काटी गई रकम तथा अग्रिम कर की रकम पर पूरा श्रेय मिलता है। फिर शेष रकम का ही भुगतान उसे करना पड़ता है।

५. कर-अवशिष्ट तथा उनकी वसूली (Arrears of tax and Recovery thereof) धारा ४६

जब कर-दाता नियमित समय में कर का भुगतान नहीं कर सके तो आयकर अफसर कर की बाकी रकम के बराबर दंड लगा सकता है। कर की

बाकी रकम (Arrears of tax) स्थानीय कर या लगान की बाकी रकम के जैसे वसूल की जा सकती है। कर-वसूली करने के लिए आयकर अफसर को बहुत हक हासिल है।

प्रश्न

प्र० सक्षिप्त टिप्पणी लिखो —

(क) कर-अवशिष्ट तथा कर-वसूली ।

(ख) कर का अग्रिम भुगतान

(ग) उद्गम स्थान पर करकटौती ।

उ० देखो (क) कड़िका ५

(ख) कड़िका ३

(ग) कड़िका १ से २ ।

अपील पद्धति

APPELLATE PROCEDURE

१ अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर को अपील धारा ३० तथा ३१

धारा ३० के अन्तर्गत कर-दाता को आयकर अफसर की कुछ आज्ञाओं के विरुद्ध अपील करने का अधिकार दिया गया है। ऐसी अपील आयकर अफसर की आज्ञा के मिलने के ३० दिन के अन्दर की जानी चाहिए। अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर को निर्णय के मजूर करने, रद्द करने, बदलने या वापस करने का पूरा पूरा अधिकार है।

२ कमिश्नर द्वारा पुन निरीक्षण (Revision by Commissioner) धाराएँ ३३ ए तथा बी

कमिश्नर स्वयं इनकम-टैक्स अफसर के किसी निर्णय का निरीक्षण कर सकता है तथा जैसी जाँच वह चाहे करवा कर कर-दाता के पक्ष में जैसी वह ठीक समझे आज्ञा दे सकता है। यदि कोई कर-दाता २५ रु० की फीस के साथ अर्जी भेजे तो कमिश्नर उस कर-दाता के कागज जाँच करके वह कर-दाता के पक्ष में जो उचित आज्ञा हो दे सकता है या उस प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार भी कर सकता है। जब तक अपील करने का समय समाप्त नहीं हो जाता है, कमिश्नर पुन निरीक्षण नहीं कर सकता। कमिश्नर का फैसला अंतिम है जिस पर कोई अपील नहीं हो सकती।

धारा ३३ बी के अनुसार कमिश्नर को सरकारी आय के हित में रकम बढ़ाने, परिवर्तन करने या कर की आज्ञा को रद्द करके नई आज्ञा देने का भी अधिकार दे दिया गया है। यदि कोई कर-दाता कमिश्नर की ऐसी आज्ञा से सन्तुष्ट नहीं हो तो उस आज्ञा के मिलने के ६० दिन के भीतर अपीलेट ट्रिब्यूनल में (१००) की फीस देकर अपील कर सकता है।

३ अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील धारा ३३

अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के धारा ३१ के फैसले के विरुद्ध ट्रिब्यूनल में कर-दाता (१००) फीस के देकर ६० दिन की अवधि में अपील कर सकता है। ट्रिब्यूनल का निर्णय तथ्य सम्बन्धी प्रश्नों पर (questions of fact) अन्तिम (final) तथा अकाट्य होता है, परन्तु कानूनी प्रश्नों पर नहीं।

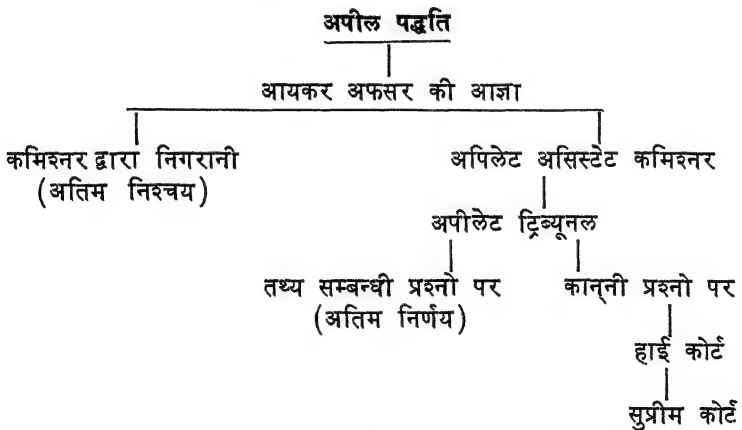
४ हाईकोर्ट को निर्देश धारा ६६

धारा ३३ की आज्ञा के मिलने के ६० दिन के अन्दर कर-दाता या कमिशनर नियमित फॉर्म में, अपीलेट ट्रिब्यूनल को कानूनी प्रश्न को हाई कोर्ट के सामने रखने की प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रार्थना के साथ कर-दाता द्वारा १०० रु० की फीस भेजी जानी चाहिए। इस प्रार्थना के ९० दिन के अन्दर अपीलेट ट्रिब्यूनल मुकदमे के प्रश्न को हाई कोर्ट के निर्णय के लिए भेज देगी। हाई कोर्ट दोनों पक्षों को सुन कर कानून-संबंधी प्रश्नों को निर्णय करता है।

५ सुप्रीमकोर्ट को अपील धारा ६६ (ए)

यदि हाई कोर्ट उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के योग्य प्रमाणित कर दे तो उस फैसले की अपील सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बदल सकती है या रद्द कर सकती है या स्वीकार कर सकती है। इसका निर्णय अन्तिम है।

निम्न चार्ट द्वारा अपील की पद्धति का पूर्ण ज्ञान स्पष्ट हो जाता है —



प्रश्न

प्र० अपील पद्धति पर एक लेख लिखो।

उ० देखो कड़िका १ से ५।

अध्याय १६

करकी वापसी

REFUND OF TAX

धारा ४८ इत्यादि

१ कर की वापसी का अर्थ तथा उसके प्रकार

नियमानुसार निश्चित की हुई कर की रकम से कर-दाता द्वारा यदि किसी रूप में अधिक रकम का भुगतान हो गया हो तो उसे उस अधिक राशि को वापस लेने का अधिकार है। निम्न लिखित अवस्थाओं में कर की वापसी का प्रश्न उठता है —

- (१) जब उद्गम स्थान पर काटी गई कर की रकम उस वर्ष के लगने वाले उचित कर से अधिक हो।
- (२) यदि कर-दाता की आय लाभशो से हो और उसकी कुल आय पर लगने वाली आयकर की दर लाभशो के उच्चतम कर की दरों से कम हो।
- (३) जब कर-दाता धारा ४९ ए तथा ४९ डी के अन्तर्गत दोहरे कर की छूट कर हकदार हो। यह छूट तब दी जाती है जबकि कर-दाता को एक बार अपने देश में तथा दूसरी बार भारत में कर देना पड़ता है।
- (४) यदि अनिवासी को किए गए भुगतानों पर काटी गई कर की दर उस दर से ज्यादा हो जिससे कि उसकी समस्त आय पर कर लगा हो।
- (५) यदि धारा ३५ के अन्तर्गत किसी भूल सुधार के कारण कर की रकम कम हो जाए।
- (६) यदि किसी अपील के कारण जो कर की रकम पहले दी जा चुकी है, कम हो जाए।
- (७) यदि अग्रिम भुगतान की रकम वास्तविक कर से अधिक हो।
- (८) जब कोई व्यापार जो १९१८ के आयकर अधिनियम के अनुसार कर दे चुका हो, बन्द हो जाए और उसे धारा २५ (३) व (४) के अन्तर्गत कुछ छूट मिले।
- (९) धारा ६० (२) के अन्तर्गत छूट मिलने पर, इत्यादि इत्यादि।

२ कर-वापसी पद्धति (Refund Procedure)

उपरोक्त कर-वापसी के प्रकारों में से अधिकांश के लिए आयकर अफसर स्वयं ही कर-वापसी मंजूर करता है। (१), (२) तथा (३) के अन्तर्गत कर-वापसी के लिए एक व्यवस्थित रीति से प्रमाणित (Verified in a prescribed manner) एक व्यवस्थित पत्र (Prescribed form) भर कर अर्जी करना चाहिए तथा तमाम सर्वोपयोगी और जरूरी कागज साथ में भेजने चाहिए।

३ कर-वापसी के हकदार

जिस व्यक्ति के हाथ में आय का कर-निर्धारण होता है वह व्यक्ति ही कर-वापसी का हकदार है। इसके अलावा एक नाबालिग, पागल, मृत पुरुष अथवा दिवालिये व्यक्ति के स्थान पर उसके कानूनी प्रतिनिधि या पालन कर्ता या हकदार कर-वापसी के लिए कानूनी रूप से मांग कर सकते हैं।

४ कर-वापसी के लिए अवधि

गत वर्ष के अगले आर्थिक वर्ष से ४ वर्ष की अवधि तक कर-वापसी के लिए अर्जी दी जा सकती है।

५ कर-वापसी की अर्जी कहाँ की जाय

(१) यदि अर्जी कर्ता भारत का निवासी है तो उसे अपने क्षेत्र के आयकर अफसर के पास अर्जी करनी चाहिए।

(२) यदि अर्जी करने वाला कर-दाता अनिवासी है तो उसे अनिवासी कर-वापसी दफ्तर (Non-residents Refund Circle) में कर वापसी के लिए अर्जी करनी चाहिये।

प्रश्न

प्र० कर-वापसी (Refunds) पर एक संक्षिप्त लेख लिखो।

उ० देखो कड़िका १ से ५।

अनुक्रमणिका

(INDEX)

		पृष्ठ
Accounting	हिसाब-किताब	५५
Additional Assessment	अतिरिक्त कर-निर्धारण	१००
Advance payment of tax	पेशगी कर भुगतान	१०४
Agricultural Income	कृषि आय	९
Allowances & Deductions (Business)	भत्ते तथा छूट (व्यापार)	४२
Annual Charge	वार्षिक भार	३९
Appeals	अपील	१०७
Appellate Tribunal	अपील न्यायाधिकरण	४
Assessee	कर-दाता	२
Assessment year	कर-निर्धारण वर्ष	५
Assessment Procedure	कर-निर्धारण पद्धति	९८
Association of Persons	जन-मंडल	७३
Authorised Representative	प्रमाणिक प्रतिनिधि	११
Bad debts	डूबत रकम	४३
Balancing Charge & allow- ance	संतुलनीय भार एवं छूट	४८
Best Judgment Assessment	अत्युत्तम निर्णयानुसार कर-निर्धारण	९९
Bonafide Annual Value	उचित वार्षिक मूल्य	३७
Bond Washing	फर्जी क्रय-विक्रय	६१
Business	व्यापार	४२
Capital Gains	पूँजीगत लाभ	५७
Carry forward of Losses	हानिको आगे ले जाना	६३
Central Board of Revenue	केन्द्रीय राजस्व बोर्ड	३
Corporation Tax	निगम कर	८१
Deduction of tax at Source	उद्गम स्थान पर कर-कटौती	१०३
Depreciation Allowance	धिसाजी भत्ता	४६
Development Rebate	विकास छूट	४७
Discontinuance of business	व्यापार का बन्द होना	८४
Earned Income	अर्जित आय	८
Earned Income Relief	अर्जित आय छूट	९
Exempted Income	कर मुक्त आय	१९
Extra Shift Allowance	अतिरिक्त पारी छूट	४७
Finance Act	वित्त अधिनियम	८७
Grossing up of Dividends	लाभाश को सकल बनाना	५७

Hindu Undivided Family	अविभक्त हिन्दू परिवार	६८
Income Escaping Assessment	कर-निर्धारण से वंचित आय	१००
Income-tax Authorities	आयकर पदाधिकारी	३
Individual	व्यक्ति	६५
Initial Depreciation	प्रारम्भिक घिसाई	४६
Insurance premium	जीवन बीमा का चढ़ा	३२
Interest on Securities	प्रतिभूतियोंका चढ़ा	३५
Non-resident	अनिवासी	८३
Notice of Demand	माँग की सूचना	१०५
Noticesu/s 22 and 23	धाराएँ २२ तथा २३ के अंतर्गत सूचनाएँ	९८
Other Sources of Income	अन्य साधनों से आय	५२
Partition of Joint Family	संयुक्त परिवार का बँटवारा	६८
Partnership firms	भागीता सार्थ	६८
Previous Year	गत वर्ष	५
Provident Funds	प्रोवीडेंट फंड	३०
Provisional Assessment	अस्थायी या सामयिक कर-निर्धारण	९९
Rectification of mistake	भूल सुधार	१००
Refund	कर-वापसी	१०९
Registered firm	पंजीयित सार्थ	७०
Registration of firm	सार्थ का पंजीयन	६९
Residence of Assessee	कर-दाताओं का निवास	१२
Resident and ordinarily resident	पक्का निवासी	१२
Resident but not ordinarily resident	कच्चा निवासी	१२
Return of Income	आय-पत्रक या नक्शा	९८
Revision	पुन निरीक्षण	१०७
Salaries	वेतन	२७
Set-off and carry-forward of Losses	हानियोंका प्रतिसादन तथा अग्रनयन	६२
Super-tax	अतिकर या अतिरिक्त कर	९०
Tax clearance certificate	कर-मुगतान प्रमाण पत्र	१०१
Total Income	कुल आय	११
Total world Income	कुल विश्व आय	११
Unabsorbed Depreciation	अशोषित घिसाई	४८
Units of Assessment	कर-निर्धारण के विभाग	२
Unregistered Firm	अपंजीयित सार्थ	७१
Vacancy Allowance	रिक्त-स्थान भत्ता	३९
Written-down Value	लिखित मूल्य	४७

APPENDIX

AGRA UNIVERSITY

B Com (Part II) Examination, 1955

N B—Questions have been answered as per the Income-tax Law up-to-date, and as modified by the Finance Act, 1959 i e as for the A Y 1959-60

N B—Attempt any five questions selecting at least two from each section All questions carry equal marks

Q 1 Explain any four of the following terms —

- (a) Previous year, (b) Agricultural Income, (c) Capital gains, (d) Dividends, (e) Extra shift allowance, (f) Bond-washing, (g) Initial depreciation, (h) Balancing charge

Ans See	(a) Chapter	I, para	8,
	(b) Chapter	I, para	12,
	(c) Chapter	IX, paras	1 to 6,
	(d) Chapter	VIII, para	4,
	(e) Chapter	VII, para	6,
	(f) Chapter	X, para	7,
	(g) Chapter	VIII, para	6,
	(h) Chapter	VIII, para	6,

Q 2 State with reasons whether the following items are admissible or inadmissible in the Profit and Loss Account of a business which is shortly to be assessed for income-tax purposes —

- (a) Interest paid on loans taken to pay of income-tax
(b) Gifts made to employees in return for services rendered, though such gifts were not legally claimable by employees
(c) Transfer to Reserve Fund for payment of premium on redemption of debentures
(d) Payment of compensation to an employee for compelling him to retire before the contracted date

(e) Bad debts in respect of loans and advances given to customers

(f) Interest on Government securities

Ans (a) It is not admissible as the loan is taken for personal purposes and not for business—Sec 10(2) (iii)

(b) They are admissible because they are incurred for business purposes—Sec 10 (2) (xv)

(c) It is not admissible as it is in the nature of reserve

(d) It is admissible because it will help the business earn more profits after dispensing with the services of such an unwanted employee

(e) They are allowed if the business is of money-lending—Sec 10(2) (xi)

(f) It is allowed

Q 3 The following are particulars of the income of Shri M V Mathur who is ordinarily resident in the taxable territory, for the year ended 31st March, 1952. You are required to prepare his assessment in proper form for the year 1953-54

(a) Salary Rs 300 p m

House rent allowance, Rs 50 p m

Contribution to unrecognized provident fund, 5 percent

Employer's contribution to above, 5 percent

Interest on provident fund (at 5 percent p a)
Rs 350

(b) His investments during the year were —

(i) Rs 5,000 in 6 percent preference shares of a Company

(ii) Rs 2,000 in 3 percent fixed deposit in a bank

(iii) Rs 4,000 in 4 percent tax-free Government Loan

- (c) He owns a house, half of which is occupied by his son for his residence and the other half is let at Rs 40 p m
- (d) He paid a premium of Rs 240 on his life policy and Rs 120 on the policy of his wife

Ans **Shri M V Mathur's Assessment for the year 1959-60**

Salaries u/s 7	Rs	Rs
Salary for 12 months @		
Rs 300 p m	3,600	
H R A @ Rs 50 p m	600	
	<hr/>	4,200
Interest on securities u/s 8 .		
4% Rs 4,000 tax free		
Govt loan	160	
	<hr/>	160
Income from Property u/s 9		
Let @ Rs 40% p m		
Annual Value	480	
Occupied Annual Value	480	
Less $\frac{1}{2}$ statutory allowance	240	
	<hr/>	240
Gross Annual Value.	720	
Less $\frac{1}{8}$ th for repairs	120	
	<hr/>	600
Income from other sources		
Dividends (on the assumption that they are less-tax) 6%		
on Rs 5,000 Preference shares of a Co	300	
3% Interest on Rs 2,000 fixed deposit in a bank	60	
	<hr/>	360
Total Income	Rs	<hr/> 5,320

L I P—Rs 360

- Q 4 A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2 2 1 The firm's Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 1954, showed a net loss of Rs 25,000 after charging the following items

	A	B	C.
	Rs	Rs	Rs
Interest on capital	3,000	3,000	1,500
Salary	Nil	Nil	2,000
Commission	2,500	Nil	Nil

A's taxable income from other sources was Rs 6,500 while B and C had no other source of income State how the assessment of partners would be made when—

- the firm is registered and
- the firm is unregistered

Ans (a) **If the firm is registered .—**

	Rs	Rs
Statement of firm's income		
Net loss as per books		25,000
Less (1) Interest on capital		
	A 3,000	
	B 3,000	
	C 1,500	
	<hr/>	
	7,500	
(2) Salary to C	2,000	
(3) Commission to A	2,500	
	<hr/>	
		12,000
		<hr/>
Total loss of the firm		13,000
		<hr/>

Allocation of Income (or loss) (In Rs)

Name of Partner	Share	Interest	Salary	Commis- sion	Share of Loss	Total income or loss
A	2	3,000	—	2,500	-10,000	- 4,500
B	2	3,000	—	—	-10,000	- 7,000
C	1	1,500	2,000	—	- 5,000	- 1,500
TOTAL		7,500	2,000	2,500	-25,000	-13,000

Assessment of Partners

- A A will be allowed to set off his share of loss from the R F Rs 4,500 against his income from other Sources Rs 6,500 Thus his net income will be Rs 2,000 which is below the taxable limit Hence he will not be required to pay any tax
- B As he has no other income he will be allowed to carry forward his share of loss from registered firm (Rs 7,000) to be set off against future profits for a period of eight years
- C As he has no other source of income, he will be allowed to carry forward his share of loss (Rs 1,500) to be set off against future profits for a period of eight years

(b) If the firm is unregistered —

The firm's loss of Rs 13,000 will be carried forward and set - off against its other business income for a period of eight years No partner can claim a set - off of his share of loss against his other income

Assessment of Partners —

- A A will pay tax on Rs 6,500
- B & C They are not liable to pay any tax this year They are also not allowed to carry forward their share of losses from the firm

- Q 5 Mr. R P Seth owns house property of the annual rental value of Rs 8,000, which he has let to Mr Kamthan at Rs 7,000 p a Mr Kamthan agreeing to bear the cost of repairs himself The expenses of Mr Seth in connection with this property amount to Rs 2,500 excluding the cost of repairs

You are required to calculate his taxable income from property Would it make any difference if the house had been let out at Rs 6,000 p a instead of Rs 7,000 p a ?

Ans Mr. R P Seth's Taxable Income from Property

	Annual Rental Value	Rs 8,000
Less	(1) Repairs (Rs 8,000-7,000)	1,000
	(2) Other Expenses in connection with this property	2,500
		<u>Rs 2,500</u>
	Income from Property	<u>Rs 5,500</u>

If the house had been let out at Rs 6,000 p a instead of Rs 7,000 p a, then Mr Seth would be allowed only $\frac{1}{3}$ th of Rs 8,000 (Annual rental value) as repairs, and Rs 2,500 as other expenses Thus his net taxable income from property would come to Rs 4,167 (Rs 8,000-Rs 2,500-Rs 1,333)

1956

- Q. 5 Explain the following terms —
 (a) Set off and carry forward, (b) Earned income,
 (c) Previous year, (d) Unabsorbed depreciation

Ans. See (a) Chapter X, para 8 and 9,
 (b) Chapter I, para 11,
 (c) Chapter I, para 8,
 (d) Chapter VII, para 6,

- Q 6 What are the different categories into which the assessées are divided with regard to residence? Give a brief a/c. of each of them

Ans. See para 1 to 4 of Chapter II

Q 7 The income of an individual (a resident ordinarily resident) for the year ended 31st March, 1954, is as follows —

- (a) Business Profits (after setting off Rs 5,000 donation paid to a University in July, 1953, and Rs 2 000 Life Insurance Premium), Rs 31,000
- (b) Interest on tax-free Government Securities, Rs 8,000
- (c) Dividend from a limited company which has paid tax on its entire income, Rs 3,000

Prepare his assessment for the year 1954-55

Ans **Assessment of an individual for 1959-60**

Interest on tax free Govt Securities		Rs 8,000
Business Profits	Rs 31,000	
Add (1) Donation to a University	Rs 5,000	
(2) L I P	Rs 2,000	
	<hr/>	
Income from business		Rs 38,000
Dividends net Rs 3,000 Gross		Rs 4,379
		<hr/>
Total Income		Rs 50,379
		<hr/>

Exempted Income

[For rebate purposes]

1 Interest on Tax-free Govt Securities	Rs 8,000
2 Donation to a University	Rs 5,000
3 L I P	Rs 2,000
	<hr/>
	Rs 15,000
	<hr/>

Q. 8. The following items are found debited to the Profit and Loss Account of a company for the year ended 31st December, 1953. Are these items deductible in computing the income of the company for income-tax

purposes for the assessment year 1954-55 ? Give reasons for your answer

- (a) Rs 1,00,000 spent on reconditioning imperfect machinery purchased
- (b) Rs 10,000 commission paid by the company for securing a contract in the course of its business
- (c) Rs 20,000 bad debts written off These bad debts were sustained by the company in respect of loans advanced to customers and written off
- (d) Rs 80,000 loss on shares written off The company had formed another company to take over its buying agency at Delhi and had taken up 80 shares of Rs 1,000 each therein The new company being unsuccessful, the amount of Rs 80,000 paid on shares was lost and hence written off

- Ans
- (a) The sum of Rs 1,00,000 spent on reconditioning imperfect machinery purchased is in the nature of capital expenditure and hence it is not deductible
 - (b) Rs 10,000 commission paid by the company for securing a contract in the course of its business is revenue expenditure and is deductible u/s 10 (2) (xv)
 - (c) Rs 20,000 bad debts written of in respect of loans advanced to customers is not deductible unless the business of the company is of banking or money lending – sec. 10 (2) (xi)
 - (d) Rs 80,000 loss on shares being a capital loss is not deductible

- Q 9. X is employed in a business office at Rs 300 per month He owns Rs 20,000 $4\frac{1}{2}$ per cent Government tax-free Securities He also owns a big house, the municipal valuation of which is Rs 800 He has let out one half of the house at Rs 50 per month while the remainder of the house is occupied by him

The house is mortgaged for a loan which he took for meeting the expenses of his sister's marriage. The interest on the mortgage was Rs 250 for the year and municipal taxes paid in respect of the house amounted to Rs 150.

Ascertain his taxable income from property and also his total income for the previous year ended 31st March, 1955.

Ans **Sri X's Assessment for 1959-60**

	Rs	Rs
1 Salaries u/s 7 @ Rs 300/- p m		3,600
2 Interest on Securities u/s 8		
Tax free Govt Securities		900
3 Income from property u/s 9		453
<i>Let</i> Annual Rental Value		
@ Rs 50/- p m	600	
Less $\frac{1}{2}$ for the taxes (Rs 75)	38	
Annual Value	562	
<i>Occupied</i> Annual Value on the basis of the house let	562	
Less $\frac{1}{2}$ statutory allowance	281	
	281	
Annual Value of both houses (Rs 562+281)	843	
Less (1) $\frac{1}{8}$ th for repairs 140		
(2) Interest on mortgage 250	390	
	453	
Total Income Rs		4,953

Exempted Income .

Interest on Tax-free Govt Securities Rs 900/-

1958 (S.)

Q 1 The following are the particulars of the income of a University Professor —

- (a) Salary Rs 1,200 p m, from which 8 percent is deducted for P F to which the university contributes 12 percent
- (b) Proctorship allowance Rs 1,200 per annum
- (c) Rent-free bungalow of which the annual letting value is Rs 720
- (d) 5 percent (tax-free) dividend on 50 shares of Rs 100 each in a limited company
- (e) 3 per cent tax-free interest on Government Loan of Rs 5,000
- (f) Income from Property let Rs 1,200
- (g) Interest on Postal Savings Bank Deposit Rs 120
- (h) Profit on sale of property, Rs 10,000

During the year he paid Rs 900 as life insurance premium on his own policy

Find his total income, taxable income, exempted income and the amount of tax payable by him for the assessment year 1957-58

Ans **Statement showing the total income taxable income, exempted income and the amount of tax payable by a University professor for the assessment year 1959-60**

1 Salaries u/s 7

	Rs	Rs
Salary @ Rs 1,200 p m	14,400	
Proctorship Allowance @ Rs 1,200 p a	1,200	
Rent free - bungalow	720	
	<hr/>	16,320

2 Interest on Securities u/s 8

Tax-free interest on Govt securities 150

3 Income from property u/s 9 1,200

4 Dividends net Rs 250 - Gross u/s 12 365

5 Capital Gains u/s 12 B

Profit on sale of property 10,000

Total income. ... 28,035

Exempted Income

1	Interest on Tax-free Govt securities	Rs	150	
2	Life insurance premium	Rs	900	
			<u>Rs 1,050</u>	
				<u>Rs 28,035</u>

A. Y 1959-60.**Calculation of Tax**

Total Income	Rs	28,035
Less Capital Gains	Rs	<u>10,000</u>
	Rs	18,035

Income-tax on Rs 18,035

(Presuming the assessee is Married with 2 dependants)

on first	Rs	3,600	nil	Rs
on next	Rs	1,400	@ 3%	= 42 = 00
„	Rs	2,500	@ 6%	= 150 = 00
„	Rs	2,500	@ 9%	= 225 = 00
„	Rs	2,500	@ 11%	= 275 = 00
„	Rs	2,500	@ 14%	= 350 = 00
„	Rs	3,035	@ 18%	= 546 = 30
	<u>Rs</u>	<u>18,035</u>	=	<u>Rs 1,588 = 30</u>

$$\bullet (\text{Average rate of tax} = \frac{\text{Rs } 1,588-30}{\text{Rs } 18,035} = 8.8067) \text{ Rs } 1588 = 30$$

Super-tax	nil.
Add Surcharge @ 5%	<u>79 = 42</u>

Total of I T & I T / S C Rs 1667 = 72

Spl S C on Tax on Unearned

Income (Rs 1715) i e Rs 308 = 70 @ 15% = Rs. 46 = 30

Total of Income-tax & S T S C etc on

Total Income, as reduced by C Gains Rs 1714 = 02

Calculation of Capital Gains-Tax

Rs 10,000/-

Tax at average rate applicabale to

Rs (28,035 - 6667) = 21,368/-

	A R	C G	nP
1 e @	(11 0538 × 10,000)		= Rs 1,105 = 38
		I T & S C	Rs 1,714 = 02

Total Tax ie Gross Demand	Rs 2,819 = 40
---------------------------	---------------

Less (i) Tax Paid or deducted by

Co from Dividends Rs 115 = 00

(ii) Rebate on (Tax-

free Govt Sec

Rs 150 + L I P

Rs 900) = Rs 1050

@ A R of 8 8067

nP per rupee

Rs 92 = 47

Rs 207 = 47

Net Tax payable by Assessee

on total Income of Rs 26,035

(which includes Rs 10,000/-

as C G)

Rs 2,611 = 93

- Q 2. An unregistered firm, having A, B and C as equal partners, made a loss of Rs 12,000 in the accounting year ended 31st March, 1956. On 1st April, 1956, C died and, under the terms of the original partnership deed A and B took his son D as a partner. A, B and D then continued the business as equal partners.

If the income of the new firm for the accounting year 1956-57 were Rs 15,000, on what income would you assess the new firm of A, B and D for the assessment year 1957-58, and how would you compute the share income of each of the partners A, B and D for the said assessment year ?

- Ans As there is a change in the constitution of the un-registered firm with effect from 1-4-56 on account of the death of C and the admission of D as a partner in place of his father "C, the loss of Rs 4,000 ($\frac{1}{3}$ rd of Rs 12,000) proportionate to the share of C will not be carried forward Hence for 1957-58 assessment year the firm's income would be computed as under -

	Rs
Profit of this year	15,000
Less Loss proportionate to the share of A and B carried forward and set off	8,000
Total Income	<u>7,000</u>

D's share of profit for this year for the purpose of inclusion in his assessment for rate purposes only is $\frac{1}{3}$ rd of Rs 15,000 i.e. Rs 5,000, while B's and C's share of income comes to Rs 1,000 each which will be included in their individual assessments for rate purposes only

- Q 3 An assessee established a new industry on 1st January, 1955, for which he purchased new machinery for Rs 50,000 and new furniture for Rs 10,000 He also purchased second-hand machinery for Rs 20,000 on 1st April, 1955 His accounting year ends on 31st December each year Find the allowable depreciation for the assessment year 1956-57 and the written-down value of machinery and furniture for the assessment year 1957-58, taking the rate of normal depreciation at 10 percent on machinery and 6 per cent on furniture

- Ans Calculation of the Allowable Depreciation for the assessment year 1959-60 and the written-down value of machinery and furniture for the assessment year 1960-61

Machinery

	Rs	Rs
(i) Purchased on 1st Jan 55		
Normal dep @ 10% on Rs 50,000 for full year	5,000	
Dev Rebate @ 25%	12,500	
(ii) Purchased on 1st April 55		
Normal dep @ 10% on Rs 20,000 for 9 months	1,500	
	<u>19,000</u>	
w d. v of Machinery for 1960-61		
Rs 70,000		
less depreciation allowed Rs 6,500	<u>63,500</u>	

Furniture

Normal depreciation @ 6% on Rs 10,000 for full year		600
w d v of furniture for 1960-61		
Rs 10,000		
Less depreciation allowed Rs 600	<u>9,400</u>	
Total depreciation (including development rebate) allowable for 1959-60 A Y		<u>19,600</u>

Q. 4 What will be the tax liability of an individual under the following circumstances ?

- When he is a member of a Hindu Undivided family
- When he is a member of an unregistered firm
- When he is a member of a registered firm
- When he is a member of an association of persons
- When he is a shareholder in a joint-stock company

Ans. See Chapter XI

Write short notes on the following —

- (a) Extra shift allowance, (b) initial depreciation, (c) vacancy allowance, (d) bond washing transactions and (e) capital gains

See (a)	Chapter VIII,	para	6
(b)	Chapter VIII,	para	6
(c)	Chapter VI,	para	3
(d)	Chapter X,	para	7
(e)	Chapter IX,	para 1 to 6	

1959

Explain the following terms

- (a) Previous year (b) Set off and carry forward, (c) Earned income relief, (d) Capital gains (e) Total world income

See (1)	Chapter I,	para	8,
(2)	Chapter X,	para	8-9,
(3)	Chapter I,	para	11,
(4)	Chapter IX,	para	1-6,
(5)	Chapter I,	para	18,

What are the classes of income to which the Income tax Act does not apply

See Chapter II, para 2,

The Profit and Loss Account for 1957 of a firm consisting of three partners A, B and C (with shares 4, 3 and 1) showed a net loss of Rs 16,000 after charging the following items —

Interest on capital A - Rs 3,000, B - Rs 2,000, C's Salary Rs 3,000 A's taxable income from other sources is Rs 5,000 while B and C have no other income Explain how the assessment would be made (a) when the firm is registered, (b) when it is unregistered

See (2) Problem No 14

A professor in a college gets a salary of Rs 800 per month He contributes one anna per rupee of his salary to a recognized provident fund to which the

college also contributes an equivalent amount. The interest on his provident fund account for the year ended 31 March, 1958 (at 5 per cent per annum) amounted to Rs 672.

He is also the owner of two houses, one (municipal valuation Rs 800) occupied by him for his own residence and the other municipal valuation Rs 1,000 let at Rs 100 per month. His expenses for the two houses were —

Municipal taxes Rs 180, Land revenue for the house let Rs 40, interest on loan taken to repair the residential house Rs 200, Fire insurance premium Rs 120, Cost of extension of electric fittings in his residence Rs 250.

Ascertain his taxable income from the property, his total income and the amount exempt from income-tax for the previous year ending 31 March, 1958. Assume that the house let remained vacant for two months and that he paid Rs 850 as premium of his life policy for Rs 8,000.

Ans A College Professor's Assessment for the Assessment year 1959-60

[Previous year ended 31-3-1959]

	Rs	Rs
1 <i>Salaries</i> u/s 7		
Salary for 12 months @ Rs 800 p m		9,600
2 <i>Income from property</i> u/s 9		
<i>Occupied—</i>		
Annual Rental value on the basis		
of house let Rs 800 \times $\frac{1,200}{1,000}$	960	
Less $\frac{1}{2}$ Municipal taxes ($\frac{1}{2} \times 80$)	40	
	<hr/>	
	920	
Less $\frac{1}{2}$ Statutory allowance	460	
	<hr/>	
Annual Value	460	

Let out

Annual Rental Value @Rs 100 p m	1,200
Less $\frac{1}{2}$ Municipal taxes ($\frac{1}{2} \times 100$)	50

Annual Value	1,150
--------------	-------

Annual Value of both houses (460 + 1150)	1,610
---	-------

Less

(1) $\frac{1}{8}$ th for repairs	268	
(2) Land revenue	40	
(3) Interest on loan	200	
(4) F I Premium	120	
(5) Vacancy allowance for 2 months	268	876
Income from property		734

Total Income	10,334
--------------	--------

Exempted Income

(1) Employee's contributions to R P F	Rs 600
(2) L I P (not to exceed 10% of sum assured)	Rs 800
	Rs 1,400

RAJPUTANA UNIVERSITY**B. Com (Final) Examination, 1959****First Paper - Income-tax and Cost Accounting.**

Q 1 Define and write detailed notes on -

- (a) Previous Year
(b) Agricultural Income

Ans (1) See Chapter I, para 8
(2) See Chapter II, para 12

Q 2 Describe the various authorities entrusted with the work of administering the law of Income-tax in India

Ans Chapter I, para 6

Q 3 Explain the following terms -

- (a) Set off and carry forward of losses
(b) Depreciation allowances

Ans (a) See Chapter X, paras 8 to 9
(b) See Chapter VII, para 6
and Problem No 7 and 8.

- Q 4 X is the principal of a College in Rajasthan drawing Rs 800 per month. He received income as royalty Rs 1,800. He held 4% debentures of B I C Ltd, to the value of Rs 15,000. He owned two houses, one let out for Rs 100 per month and other occupied by him of the municipal valuation of Rs 600 per annum. He paid Rs 200 as fire insurance premium and Rs 200 as ground rent in respect of let-out house. He paid insurance premium of Rs 150 and Rs 125 as interest on loan taken for repairs in respect of the house occupied by him for purposes of his residence.

Find out his total income and assessable income for the assessment year 1957-58

Ans **Assessment for Mr. X For 1959-60**

	Rs	Rs
1 Salaries u/s 7 @ Rs 800 p m		9,600
2 Interest on Securities u/s 8 4 % Rs 15,000 debentures of B I C Ltd		600
3 Income from Property u/s 9 Annual Letting Value of the house let out @ Rs 100 p m	1,200	
Municipal Valuation of the house occupied for residence	600	
Less $\frac{1}{2}$ statutory allowance	300	300
Annual Value of both houses	1,500	
Less		
(1) $\frac{1}{8}$ th for repairs	250	
(2) F I Premium (Rs 200 + 150)	350	
(3) Ground rent	200	
(4) Interest on loan	125	925
		575
4. Income from other sources u/s 12 Royalties		1,800
Total Income & Assessable Income		<u>12,575</u>

- Q 5 (a) A and B are partners in a Registered Firm sharing Profits and Losses equally and following is their Profit and Loss Account —

	Rs		Rs
Salaries	10,750	Gross Profit	51,040
Rent, Rates, Taxes		Interest on Tax Free	
and Insurance	1,200	Govt Securities	900
Travelling Expenses	954	Profit on Sale of	
Interest on Bank Loan	1,650	Investment	1,200
Legal Charges	1,103		
Discounts	897		
Carriage	601		
General Expenses	2,050		
Marketing	2,300		
Depreciation on Car	500		
Interest on Capital			
A	1,700		
B	1,550		
	<u> </u>		
	3,250		
Reserve for Bad Debts	1,000		
Net Profit	26,885		
	<u> </u>		<u> </u>
	53,140		53,140

After considering the following matters compute the total income of the firm for the year ended 31st March, 1958 —

- (i) Salaries include a partnership salary of Rs 200 p m. to B
- (ii) The legal charges consist of Rs 500 for alteration of the Partnership agreement and the balance for Debt collection
- (iii) Rs 200 paid as premium on an Insurance policy on the life of a debtor is included in insurance

- (iv) The general expenses include Rs 210 for additional filing cabinet and Rs 360 for a new typewriter
- (v) The car was used for domestic purposes
- (b) Illustrate grossing up of dividends for the assessment year 1958-59

Ans (a) A B Firm's Assessment For A Y 1959-60

	Rs	Rs
Net Profit as per P & L a/c		26,885
Less items treated separately		
(1) Interest on Tax-free Govt securities	900	
(2) Profit on sale of investment (exempt)	1,200	2,100
	<u> </u>	<u> </u>
Add		
(1) Interest on Capitals		24,250
A 1,700		
B 1,550	3,250	
	<u> </u>	
(2) Reserve for bad debts	1,000	
(3) Salary to B @ Rs 200 p m	2,400	
(4) Legal charges	500	
(5) L I P	200	
(6) Filing cabinet	210	
(7) New typewriter	360	
(8) Carriage Expenses (Car)	601	
(9) Depreciation on Car	500	9,021
	<u> </u>	<u> </u>
		33,806
Business Income u/s 10		
Interest on Tax-free Govt securities		900
		<u> </u>
Total Income		<u>34,706</u>

(b) See Chapter VIII, para 6 to 7